राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 9 अंक 355

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, बुधवार, 3 जून, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जो शोहदा बोली से नहीं माना, गोली से जरूर मान गया

>> 4

जागरण विशेष

कतरन से बदलाव की कहानी पहुंची अंतरराष्ट्रीय मंच तक

जागरण: कपड़ों की कतरनों से कठपुतलियां बना पर्यावरण एवं विरासत को सहेजने वाली लखनऊ की 14 साल की आलिया स्लिंगशाट चैलेंज में शामिल। • पेज-7

संपादकीय

गति पकड़ता सेमीकंडक्टर अभियान: भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स

इकोसिस्टम में महज एक उपभोक्ता या असेंबलिंग तक ही सीमित न रहकर स्वयं को एक उत्पादक के रूप में भी स्थापित कर रहा है। **हर्ष वी. पंत** का आलेख।

12 बरस की सफलताएं और विफलताएं: मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते समय इस पर भी ध्यान दे कि उसके हिस्से में कुछ नाकामियां भी हैं। **राजीव सचान** का दृष्टिकोण।

• पेज-8

विमर्श

वैश्विक मंच पर उभरता भारत: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों-यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा का एक जीवंत घोषणापत्र है। **श्री राम शा** का विश्लेषण।

बेचैन युवा भारत की अभिव्यक्ति: आज देश में राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा इंटरनेट मीडिया पर आकार ले रहा है। **डा. महुआ माजी** का आलेख। • पेज-9

दैनिक जागरण

सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

गर्मी से बचाएं आंखें और त्वचा

क्यों चकराता है सिर जानें इसका सही निदान

• पेज-13

ओएसएम में गड़बड़ी पर हटाए गए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव

आइएएस लोखंडे प्रशांत नए चेयरमैन नियुक्त, वरुण भारद्वाज सचिव बनाए गए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के जरिए 12वीं के छात्रों के कराए गए मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों को लेकर विवादों में घिरे सीबीएसई के खिलाफ सरकार मंगलवार को एक्शन में दिखी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के बाद इसके चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। वरिष्ठ आइएएस लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन और इंडियन इंफोर्मेशन सर्विस के अधिकारी वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया गया है।

इस बीच, ओएसएम से जुड़े टेंडर मामले की जांच के लिए भी एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसका जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष एस. राधा चौहान को सौंपा गया है। उन्हें एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। चौहान उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी हैं और केंद्र सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव भी रह चुकी हैं। प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह अपनी पसंद के किसी भी अधिकारी को अपने साथ नियुक्त कर सकती है। कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले ही ओएसएम के जरिए कराए गए मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ी पर एक रिपोर्ट मांगी थी, जो सोमवार देर रात ही उसे सौंप दी गई थी। इस रिपोर्ट के बाद ही यह संकेत मिलने लगे थे कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। असली दोषी की पहचान तो जांच के बाद होगी, लेकिन सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को अब कोई राहत न देने का फैसला हुआ। वैसे भी फिलहाल वही इस पूरी खामी के लिए तो सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन और कापियों को मुहैया कराने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान कुछ छात्रों को दूसरों की कापियां दे दी गई थीं। छात्रों की आपत्ति के बाद गड़बड़ियों ने और तूल पकड़ा, जो अभी तक जारी है।

राहुल सिंह। फाइल

- एक सदस्यीय समिति करेगी टेंडर मामले की जांच, 30 दिन में देगी रिपोर्ट
- समिति की अध्यक्ष कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान होंगी

लोखंडे प्रशांत सीताराम। फाइल

13 मई को रिजल्ट आने के साथ ही शुरू हो गया था विवाद

सीबीएसई के मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर यह पूरा विवाद 13 मई को 12वीं का रिजल्ट आने के साथ ही खड़ा हो गया था। छात्रों ने इस दौरान कम अंक मिलने की शिकायत की। इसे पहले सीबीएसई ने अनसुना कर दिया लेकिन जब यह मामला तूल पकड़ा

संसदीय समिति के सामने 17 साल के छात्र सार्थक ने खोली गड़बड़ियों की पोल

नई दिल्ली: मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों पर वैसे तो संसदीय समिति से जुड़े सदस्यों को सीबीएसई से सवाल करने थे और उन्होंने किए भी लेकिन समिति के सामने पेश हुए 12वीं के छात्र सार्थक ने ओएसएम से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए, उससे समिति के मौजूद सदस्य दंग रह गए। समिति के सदस्यों ने न सिर्फ मेज थपथपाई बल्कि सीबीएसई के अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ इनसे सीखो। वहीं, सार्थक के सवालों से सीबीएसई पूरी तरह से निरुत्तर दिखी। (पेज-5)

नेपाल से सीमा विवाद में तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं : भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत-नेपाल सीमा विवाद पर बयान देकर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। सीमा विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की उनकी मांग पर भारत ने साफ इन्कार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं बनती। 'नेपाल द्वारा भी भारत की जमीन पर अतिक्रमण' संबंधी बयान के बाद बालेंद्र शाह को लगातार विपक्षी दलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा, ''भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र पहले से मौजूद हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस द्विपक्षीय मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।'' पीएम शाह ने रविवार को संसद में कहा था कि भारत के साथ बातचीत के अलावा नेपाल चीन और ब्रिटेन से भी संपर्क में है। उन्होंने कहा, ''चूंकि यह विवाद ब्रिटिश काल से जुड़ा है, इसलिए ब्रिटेन को भी इसमें शामिल होना चाहिए।'' जायसवाल ने कहा कि भारत-नेपाल की लगभग 98 प्रतिशत सीमा पहले ही चिह्नित की जा चुकी है और विवादों का समाधान निकाला जा चुका है। बाकी कुछ हिस्सों में विवाद है, जिनमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी शामिल हैं। भारत इन क्षेत्रों को हमेशा उत्तराखंड का अभिन्न अंग मानता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गंडक नदी के रास्ते में बदलाव और कुछ जगहों पर अतिक्रमण के कारण यह स्थिति बनी है। दोनों देश संयुक्त रूप से इन अतिक्रमणों का नक्शा तैयार कर रहे हैं। इस मामले में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है। जायसवाल ने कहा, ''हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान को देखा है और इस पूरे मामले का समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही होगा।''

- विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग पर भारत ने किया इन्कार
- विदेश मंत्रालय ने कहा- यह पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दा, किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं बनती

नई दिल्ली में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। एएनआइ

किसी की बपौती नहीं है सरकारी बंगला, करना पड़ेगा खाली : सम्राट

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं। कुछ लोग बिहार को राजतंत्र के अनुसार चलाना चाहते हैं। यहां कानून का राज है। बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। इसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मालूम हो कि राज्य सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दिया है, जिसका वे विरोध कर रही हैं। (पेज-4)

यूपी में अपर निजी सचिव परीक्षा में कोई सफल नहीं, सभी पद रिक्त

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की अपर निजी सचिव (एपीएस) परीक्षा-2023 के परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया। 331 पदों के लिए एक भी अभ्यर्थी अंतिम यानी तृतीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र नहीं मिला। हिंदी आशुलेखन में कोई भी अभ्यर्थी 80 शब्द की त्रुटि रहित गति नहीं पा सका। (पेज-5)

तृणमूल में बढ़ी अंदरूनी कलह, 50 विधायकों के बगावत की अटकलें

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष और गुटबाजी की चर्चा तेज हो गई है। हस्ताक्षर विवाद के बाद पार्टी से निष्कासित दो विधायक ऋतब्रत बंद्योपाध्याय और संदीपन साहा को लेकर अब बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, तृणमूल के करीब 50 विधायक इन दोनों नेताओं के संपर्क में हैं और पार्टी के भीतर एक अलग शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश चल रही है।

विवाद की शुरुआत इन दोनों नेताओं की उस शिकायत से हुई, जिसमें विपक्ष के नेता के समर्थन से जुड़े एक प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर जाली होने का आरोप लगाया गया। शिकायत के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच सीआइडी कर रही है।

पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा दोनों विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाने और उनके नाम सामने आने के कुछ ही समय बाद तृणमूल ने ऋतब्रत बंद्योपाध्याय और संदीपन को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए दल से निष्कासित कर दिया।

ऋतब्रत ने अटकलों को बताया महज अफवाह : भाजपा विधायक तापस राय ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस महाराष्ट्र जैसी स्थिति में पहुंच गई है और करीब 50 तृणमूल विधायक ऋतब्रत बंद्योपाध्याय के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि इस दिन विधानसभा पहुंचने पर ऋतब्रत ने कहा कि 50 विधायकों के समर्थन की बातें केवल अटकलें हैं। वह केवल अपनी और विधायक संदीपन साहा की जिम्मेदारी ले सकते हैं।

हिंसा के विरोध में ममता का धरना, कहा- भाजपा को हटाए बिना नहीं रुकूंगी पेज>>4

- नए गुट के गठन पर कर रहे हैं विचार, स्पीकर को सौंप सकते हैं प्रस्ताव
- टीएमसी से निष्कासित दो विधायक ऋतब्रत और संदीपन बने चर्चा के केंद्र

ममता बनर्जी। प्रेट्र

खुद को वास्तविक तृणमूल बताने की तैयारी में

सूत्रों के अनुसार, कोलकाता स्थित एमएलए हास्टल में ऋतब्रत और संदीपन के साथ कई विधायकों की बैठक हुई। इनमें जावेद खान, शिउली साहा समेत करीब 16 विधायक मौजूद थे। चर्चा है कि ये विधायक खुद को वास्तविक तृणमूल बताने की तैयारी में हैं और स्पीकर को इस संबंध में एक प्रस्ताव सौंप सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, इस संभावित गुट का चेहरा ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को बनाया जा सकता है। यदि बड़ी संख्या में विधायक वास्तव में अलग रुख अपनाते हैं, तो यह पार्टी नेतृत्व के लिए नई चुनौती बन सकता है।

फेमा उल्लंघन के मामले में वेदांता ग्रुप के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में ईडी ने उद्योगपति अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप के ठिकानों की तलाशी ली। सोमवार को ईडी के अधिकारी दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के उदयपुर स्थित वेदांता के चार परिसरों में पहुंचे और विदेशी लेन-देन के जुड़ी फाइलों की पड़ताल की। फेमा उल्लंघन एक सिविल अपराध है और साबित होने पर कंपनी को जुर्माना देना पड़ सकता है।

ईडी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार लंदन स्थित मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेस और भारत स्थित वेदांता लिमिटेड के बीच हुआ लेनदेन जांच के दायरे में है। 2023 में वेदांता रिसोर्सेज ने ब्रांड शुल्क का एक हिस्सा वेदांता लिमिटेड को वापस किया था और आरोप है कि उसमें फेमा का उल्लंघन किया गया था। ईडी इसी की जांच कर रही है।

वेदांता समूह ने ईडी की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी जांच में एजेंसी का पूरी तरह से सहयोग कर रही है और सभी मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा रही है। वेदांता समूह धातुओं, महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी का वैश्विक स्तर पर उत्पादन करती है और इसका काम भारत, अफ्रीका, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया तक फैला हुआ है।

ईडी ने फिलहाल फेमा उल्लंघन करके भारत लाई गई राशि के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तलाशी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है।

- जांच एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई और उदयपुर में वेदांता समूह के परिसरों में की कार्रवाई
- विदेशी लेनदेन से जुड़े दस्तावेज खंगाले, गड़बड़ी पाए जाने पर तीन गुना तक जुर्माना संभव

अनिल अग्रवाल। फाइल

खोड़ा में चला सत्यापन अभियान, दो मदरसे सील

गाजियाबाद: खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर से पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने मंगलवार को खोड़ा इलाके में अपराधियों के खिलाफ सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान अधिकांश हिस्ट्रीशीटर व अपराधी खोड़ा छोड़कर भाग गए और घरों पर नहीं मिले। वहीं, प्रशासन ने कार्रवाई कर अवैध तरीके से चल रहे दो मदरसों को सील कर दिया, जबकि तीसरे को नोटिस जारी किया है। (पेज-2)

हवा से मार करने वाली मिसाइल रुद्र एम-2 का सफल परीक्षण

बालेश्वर: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र एम-2 का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान प्रक्षेपित की गई सभी मिसाइलों ने पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों पर अत्यंत सटीकता के साथ प्रहार किया। (पेज-10)

किश्तवाड़ और डोडा में तीन जगह फटे बादल

किश्तवाड़: किश्तवाड़ और डोडा जिलों में मंगलवार को तीन स्थानों पर बादल फटे। इसके बाद हुई मूसलधार वर्षा से मिट्टी व भारी मलबा पहाड़ों से नीचे रिहायशी क्षेत्रों में आ गया। कई जगह भूस्खलन भी हुआ। इससे स्थानीय लोगों के कई वाहनों व संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। (पेज-13)

शादीशुदा बेटियां भी परिवार का हिस्सा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित कोटे के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाहित पुत्री को 'परिवार' की परिभाषा से बाहर रखना मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के समानता सिद्धांत के खिलाफ है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से विवाहित पुत्री को परिवार की श्रेणी में शामिल नहीं माना गया था। मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा था, जिसने मृतक उचित मूल्य दुकान संचालक की पुत्री होने के नाते अनुकंपा आधार पर दुकान आवंटन का दावा किया था। उसकी अर्जी केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह विवाहित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्रित कोटे का उद्देश्य मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ये किसी प्रकार का उत्तराधिकार या विरासत का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में आवेदक की वैवाहिक स्थिति नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक निर्भरता, वित्तीय आवश्यकता, निवास और जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह मान लेना कि विवाह के बाद बेटी अपने माता-पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती, संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। आज की सामाजिक परिस्थितियों में अनेक विवाहित बेटियां अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, उनका भरण-पोषण करती हैं या उन पर निर्भर रहती हैं। वहीं कई बेटे परिवार की परिभाषा में शामिल होने के बावजूद वास्तव में आश्रित नहीं होते। इसलिए आश्रितता का निर्धारण तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर।

वैवाहिक आधार का प्रविभाजन संवैधानिक कसौटी पर टिक नहीं सकता। राज्य सरकार की इस दलील को भी अदालत ने खारिज कर दिया कि विवाहित पुत्रियां स्थानीय निवास संबंधी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी विवाहित बेटियों के बारे में एक जैसी धारणा बनाना वास्तविक परिस्थितियों से परे है।

- वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक
- आश्रितता और आर्थिक जरूरत ही होंगी कसौटी

विवाहित पुत्र को परिवार का सदस्य माना जाता है, जबकि विवाहित पुत्री को बाहर कर दिया जाता है। यह भेदभाव उस पुरानी सोच पर आधारित है कि विवाह के बाद बेटी दूसरे परिवार की सदस्य बन जाती है और मायके से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसी धारणा संविधान की समानता और लैंगिक न्याय की भावना के विपरीत है। - **सुप्रीम कोर्ट**

सुगम यातायात

राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम से निजात को बनेंगे नए रिंगरोड और बाईपास

जितेंद्र शर्मा • जागरण

नई दिल्ली: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी गति से बढ़ रहा अनियोजित शहरीकरण चुनौती भी बढ़ा रहा है। अध्ययन में यह सामने आ चुका है कि हाईवे का जो हिस्सा शहरी क्षेत्र से होकर गुजरता है, वहां स्थानीय यातायात शामिल होने के बाद हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने लगती है। इसे देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 'अर्बन डी-कंजेशन' (निर्बाध नगर यातायात) नीति बनाई है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों से स्थानीय यातायात का भार कम करने के लिए उसके आसपास एलिवेटेड रोड, बाईपास और रिंग रोड बनाए जाएंगे। राज्य इसमें सहभागी होंगे और डी-कंजेशन के तहत चिन्हित परियोजनाओं को संबंधित शहर या कस्बे के मास्टर प्लान में शामिल करेंगे।

प्रतीकात्मक

15 मीटर का निषिद्ध विकास क्षेत्र बनेगा हरित क्षेत्र

डी-कंजेशन नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, बाईपास या रिंग रोड के दोनों ओर 15 मीटर का निषिद्ध विकास नियंत्रण क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा राज्य नगर नियोजन कानूनों के तहत हरित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस क्षेत्र में विकास निषिद्ध रहेगा। वहां सिर्फ सार्वजनिक परिवहन आवश्यकताओं जैसे बस स्टाप, बिजली, पानी या सीवरेज पाइपलाइन जैसे ही काम हो सकेंगे। इस विकास नियंत्रण क्षेत्र के बाहर राज्य सरकार आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत अवसंरचना के विकास के लिए बाईपास या रिंग रोड के दोनों ओर दो किमी तक की रेडियस दूरी तक विनियमित विकास क्षेत्र (आरडीजेड) की योजना बना सकती है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ डी-कंजेशन नीति साझा की है। इससे पूर्व भारतमाला परियोजना के तहत प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित एक लाख से अधिक आबादी वाले 191 कस्बों व शहरों की पहचान की गई थी। उन पर स्थानीय यातायात के कारण हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की औसत गति 10 प्रतिशत या उससे भी कम हो जाती थी। ऐसे कई कारिडोर पर यातायात का दबाव दूर करने के कुछ उपाय किए जा चुके हैं। इनमें से जहां भी नान-एक्सेस कंट्रोल बाईपास या रिंग रोड बनाए गए, वहां राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अनियोजित शहरी विकास के कारण बाधा दूर नहीं हो सकी। इसे देखते हुए ही अर्बन डी-कंजेशन नीति में प्रविधान किया गया है कि शहरी क्षेत्रों या उसके पास नवनिर्मित रिंग रोड व बाईपास के किनारे नई सड़कों का निर्माण रोकना होगा। बनाए जाने वाले एलिवेटेड रोड या बाईपास को न्यूनतम चार लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल गलियारों के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटरचेंज या स्लिप रोड के जरिये एक्सेस-कंट्रोल हाईवे तक पहुंच सिर्फ अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों या जिलों की प्रमुख सड़कों द्वारा ही होगी। इंटरचेंज कम से कम पांच किमी के अंतराल पर बनाए जाएंगे, जबकि अन्य सार्वजनिक सड़कों तक पहुंच स्लिप रोड से होगी। इन परियोजनाओं को 50 वर्षों तक के शहरी विस्तार, जनसांख्यिकीय वृद्धि का आकलन कर बनाया जाएगा। रिंग रोड या बाईपास के बाहरी हिस्से पर सर्विस रोड का विकास राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक करेगी।

इन पैमानों पर होगा चयन पेज>>10

2 जून को दिल्ली में कहीं वर्षा नहीं हुई, लेकिन तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री कम 37.7 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार और शुक्रवार के लिए फिर से मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ वर्षा का यलो अलर्ट जारी कर दिया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 03 जून, 2026

आज का मौसम

गर्जन वाले बादल बनने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने के आसार।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
3 जून	38.0	27.0
4 जून	38.0	28.0
नोएडा		
3 जून	38.0	26.0
4 जून	39.0	26.0
गुरुग्राम		
3 जून	41.0	28.0
4 जून	40.0	26.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

जल बोर्ड के उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को स्वीकृति

नई दिल्ली : दिल्ली उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मालवीय नगर के विधायक सतीश उपाध्याय को दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किए जाने को स्वीकृति दे दी है। इनके साथ ही नांगलोई जाट से विधायक मनोज कुमार शोकीन व घोंडा के विधायक अजय कुमार महावर और दिल्ली छावनी बोर्ड के प्रतिनिधि राजेश कुमार गोयल को दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करने को भी स्वीकृति दी है। उपाध्यक्ष और तीनों सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर दो वर्षों का होगा। (जासं)

श्रमिक हिंसा मामले में आरोपित सत्यम वर्मा की जमानत निरस्त

गौतम बुद्ध नगर : जिला अदालत ने श्रमिक हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपित सत्यम वर्मा की जमानत याचिका निरस्त कर दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया उनकी संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। (जासं)

रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार एओ को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआइ अदालत ने रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार शाहदरा नार्थ जोन में तैनात रहे प्रशासनिक अधिकारी (एओ) दिव्यांशु कगौतम की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपित की संलिप्तता के मजबूत साक्ष्य हैं। केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। आरोपित के रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। (जासं)

खोड़ा में चला सत्यापन अभियान, दो मदरसे सील

सख्ती ▶ सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री के सख्त तेवर पर जागा पुलिस-प्रशासन तो भागे हिस्ट्रीशीटर और अपराधी

सूर्या के भाई को खोड़ा नगर पालिका में बनाया सफाई सुपरवाइजर, डीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

11 बच्चे फंस गए थे सील किए एक मदरसे में

1600 अपराधी पुलिस किए हैं चिह्नित

खोड़ा में पैदल मार्च करते सीपी, डीएम और पुलिस बल। जागरण

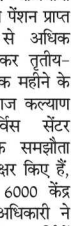

खोड़ा में मदरसे को सील करती प्रशासन की टीम। जागरण

खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर से पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने मंगलवार को खोड़ा में अपराधियों के खिलाफ सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान अधिकांश हिस्ट्रीशीटर व अपराधी खोड़ा छोड़कर भाग गए और घरों पर नहीं मिले। वहीं, प्रशासन ने कार्रवाई कर अवैध तरीके से चल रहे दो मदरसों को सील कर दिया, जबकि तीसरे को नोटिस जारी किया है। सील किए एक मदरसे में 11 बच्चे बंद हो गए थे, जिन्हें बाद में निकाला गया। सूर्या के बड़े भाई यश को खोड़ा नगर पालिका में सफाई सुपरवाइजर बनाया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मंगलवार को उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। मंगलवार को भी खोड़ा में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

खोड़ा में मंगलवार सुबह से ही पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के साथ अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस ने 1600 अपराधी चिह्नित किए हैं। जिनका तीन दिन में सत्यापन कार्य पूरा करना है, लेकिन प्रशासन के डर से खोड़ा के अपराधी घर छोड़कर फरार हैं। मंगलवार को अभियान के दौरान अधिकांश अपराधी गायब मिले, जबकि कुछ अपने घर पर ही रहे। इन्हें पुलिस ने अपराध से दूरी बनाने की चेतावनी दी। सोमवार को पुलिस ने 170 और मंगलवार को 330 अपराधियों का सत्यापन किया। साथ ही मंगलवार तक 70 में से 38 हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन भी हुआ। वहीं, प्रशासन की टीम ने खोड़ा के लोकप्रिय विहार में अवैध संचालित मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम-उल-उलूम को सील किया। जब प्रशासनिक अधिकारी मदरसे पर कार्रवाई करने पहुंचे, तो मदरसे का गेट नहीं खोला गया। इस पर प्रशासन ने मदरसे को बाहर से सील कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि जिस समय मदरसे को सील किया, तब अंदर 11 बच्चे मौजूद थे। मदरसा कमेटी के प्रमुख सचिव इलियास सैफी ने आरोप लगाया कि उनके पास मदरसा संचालन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन प्रशासनिक टीम ने उन्हें दिखाने का मौका नहीं दिया। बाद में बच्चों को बाहर निकाला गया। प्रशासन ने लोकप्रिय विहार में ही संचालित मदरसा सुल्तान अलारफीन को भी सील किया। खोड़ा गांव में मदरसा रमानिया अरनिया पासीमूल उलूक पर नोटिस चस्पा किया। विद्युत विभाग ने मदरसों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही तीनों मदरसों पर कार्रवाई की है। मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हैं और उनका अल्पसंख्यक विभाग में पंजीकरण भी नहीं है।

असद के पुराने मकान में तोड़फोड़ : खोड़ा में ही असद के पुराने मकान पर सोमवार को पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। देर रात कुछ लोग एकत्र होकर इस मकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ की। लोगों ने असद के मकान का दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद असद के घर पर पुलिस तैनात की गई और लोगों को मौके से हटाया गया।

सूर्या के घर पहुंच रहे हैं नेता : सूर्या की हत्या के बाद से खोड़ा में विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों के नेता पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, खोड़ा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रीना भाटी, मिजोरम के राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह ने सूर्या के परिवार से मिलकर सांत्वना दी। राष्ट्रीय बजरंग दल ने सूर्या के परिवार को सवा दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता सूर्या के घर पहुंचते रहे और श्रद्धांजलि देकर परिवार से मिलते रहे।

मंगलवार को खुले बाजार व दुकानें : सूर्या की हत्या के बाद से शुक्रवार से खोड़ा नवनीत विहार का बाजार व दुकानें बंद थीं। मंगलवार को खोड़ा में भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिले के सभी आलाधिकारियों ने खोड़ा में डेरा डाला। इसके बाद मंगलवार को बाजार व दुकानें खुले। अब हालात सामान्य हैं।

वृद्धावस्था व विकलांगता पेंशन भोगियों का घरों में होगा बायोमीट्रिक सत्यापन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली : राजधानी में वृद्धावस्था एवं विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले पांच लाख से अधिक लाभार्थियों का घर-घर जाकर तृतीय-पक्ष बायोमीट्रिक सत्यापन एक महीने के भीतर शुरू हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो शहर भर में लगभग 6000 केंद्र संचालित करता है। एक अधिकारी ने बताया कि सीएससी नेटवर्क लाभार्थियों के घरों पर सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में विभाग की सहायता करेगा।

उन्होंने बताया, इस प्रक्रिया के तहत सर्वेक्षण कर्मी लाभार्थियों के घर-घर जाकर फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनर का उपयोग करके बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण करेंगे। वे लाभार्थियों की लाइव तस्वीरें भी लेंगे और इलेक्ट्रानिक दस्तावेजीकरण से उनके रिकार्ड को अपडेट करेंगे। अभियान एक महीने के भीतर शुरू होने की उम्मीद है और पांच महीने के अंदर पूरा होने की संभावना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन मामलों की पहचान करना है जहां लाभार्थी की मृत्यु हो जाने, दिल्ली से बाहर चले जाने या योजना के मानदंडों के अनुसार अपात्र हो जाने के बावजूद पेंशन का लाभ अभी भी दिया जा रहा है।

हरे-भरे क्षेत्रों की रक्षा करेगा रिज प्रबंधन बोर्ड, एलजी ने दी पुनर्गठन को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

तरनजीत सिंह संधू। फाइल

एलजी तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी के हरे-भरे क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए रिज प्रबंधन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। लोक निवास के अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्गठित दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड (डीआरएमबी) एक एकीकृत, बहु-एजेंसी नियामक निकाय के माध्यम से रिज क्षेत्र का प्रबंधन करेगा। मालूम हो कि रिज दिल्ली में अरावली पर्वतमाला के प्राचीन अवशेषों का क्षेत्र है।

एक अधिकारी के अनुसार, बोर्ड का पहला दायित्व प्रमुख पर्यावरण विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और दिल्ली के महत्वपूर्ण रिज पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना होगा। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में स्थित रिज का स्वामित्व डीडीए के पास है, जबकि प्रदेश सरकार का पर्यावरण और वन विभाग इसका रखरखाव करता है। दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), राजस्व विभाग और दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियां इसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। पुनर्गठित बोर्ड एक ऐसा मंच होगा जिसका उद्देश्य पर्यावरण की निगरानी करने के साथ प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस बोर्ड में डीडीए के उपाध्यक्ष, पर्यावरण मंत्रालय के वन महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, एमसीडी और एनडीएमसी के प्रमुख सदस्य होंगे।

योगेश की गिरफ्तारी से डीयू प्रशासन ने झाड़ा पल्ला, छात्र संगठनों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर हुए श्रमिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में डीयू के छात्र योगेश मीणा को नोएडा पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ वामपंथी छात्र संगठनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर आक्रोश जताया है, तो वहीं डीयू प्रशासन ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। डीयू प्रशासन ने कहा कि उन्हे इस घटनाक्रम के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिज्ञान ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया है।

योगेश मीणा ने श्रीराम कालेज आफ कामर्स से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में वह डीयू के 'कैंपस ला सेंटर' से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह छात्र राजनीति में भी सक्रिय है और साल 2025 के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में 'दिशा छात्र संगठन' की ओर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था।

मुकुंदपुर में सिलिंडर फटने से जमींदोज हुआ मकान, चार झुलसे, छह घायल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ आवासीय क्षेत्र में बने इस मकान में अवैध रूप से होता था गैस रीफलिंग का काम

मुकुंदपुर में सिलिंडर ब्लास्ट से बिल्डिंग गिरने के बाद मलबा हटाता बुलडोजर। चंद्र प्रकाश मिश्र

बुराड़ी क्षेत्र के मुकुंदपुर में सोमवार सुबह गैस सिलिंडर फटने से एक मकान जमींदोज हो गया। यहां काम कर रहीं तीन महिलाओं समेत 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इनमें से दो की हालत नाजुक बताई गई है। चार लोग झुलसे हैं और बाकी मलबे के नीचे दबने से घायल हुए हैं।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि इस आवासीय क्षेत्र में मकान में गैर कानूनी तरीके से गैस सिलिंडर की रीफिलिंग हो रही थी, इसी दौरान चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया गया तो धमाके के साथ सिलिंडर फट गया। सूचना पर पहुंचीं दमकल की पांच गाड़ियों ने राहत व बचाव कार्य के बाद शाम चार बजे तक सर्च अभियान चलाया। मकान में बर्तन कोटिंग व मोबाइल चार्जर का तार बनाने का काम भी हो रहा था। सभी घायल बर्तन कोटिंग यूनिट में काम करते थे। पुलिस ने बर्तन कोटिंग यूनिट के संचालक सुधीर राय और मकान मालिक के भाई हरकेश उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। भलस्वा डेरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 287, 125ए, 125बी और 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यहां से खाली 38 और बगल के मकान से 46 खाली सिलिंडर बरामद किए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि भलस्वा डेरी थाना अंतर्गत गांव मुकुंदपुर के ईशू विहार में सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे धमाके के साथ सिलिंडर फटने से एक मकान गिर पड़ा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस व दमकल विभाग को सूचित किया और स्वयं राहत व बचाव कार्यों में जुट गए। चार-पांच घायलों को स्थानीय लोगों ने मलबे से बाहर निकाला। एनडीआरएफ व दमकल कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। छह घायलों को जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवनराम अस्पताल में भर्ती कराया, इनमें से अखिलेश राम की गंभीर हालत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में एक अन्य दीपा को भी सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली।

हरियाणा से 80 क्यूसेक अधिक पानी मिलने से भी दूर नहीं हुआ जल संकट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

▶ जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, यमुना में पानी की कमी से हो रही समस्या

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा।

हरियाणा से अधिक पानी मिलने के बाद भी दिल्ली में पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर सामान्य से लगभग साढ़े पांच फीट नीचे चला गया है। इस जलाशय से वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) को कच्चा पानी मिलता है। इसमें कमी आने से दोनों संयंत्र क्षमता के अनुसार नहीं चल रहे हैं। राजधानी में लगभग 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) कम पानी की आपूर्ति हो रही है।

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी पिछले कुछ दिनों से पानी की कमी की बात स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 12 विधानसभा क्षेत्रों से जल आपूर्ति की शिकायत मिल रही है। दिल्ली में लगभग एक हजार एमजीडी पेयजल उपलब्ध होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें कमी आई है। यमुना में पानी की कमी के कारण वजीराबाद जलाशय का जलस्तर 674.15 की जगह 668 फीट रह गया है। वजीराबाद और चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए यमुना से लगभग 135 एमजीडी पानी लिया जाता था। जलाशय का जलस्तर कम होने से इसकी जगह इस समय 50 एमजीडी से भी कम पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा से कैरियर लिंक कैनाल (सीएलसी) और दिल्ली सब ब्रांच (डीएसबी) नहरों के माध्यम से 920 क्यूसेक पानी मिलता था।

कुख्यात तस्कर अंसारी से हथियार खरीदने वालों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई शुरू

राकेश कुमार सिंह ● जागरण

▶ क्राइम ब्रांच ने दक्षिण जिला के गैंगस्टर रोहित चौधरी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया

सलीम पिस्टल

शाहबाज अंसारी

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने देश के बड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार सप्लायरों में एक शाहबाज अंसारी सिंडिकेट के खिलाफ व्यापक अभियान चला रखा है। इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने अंसारी गिरोह पर कठोर कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगा दिया है। इस मामले में 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ये वो लोग हैं जो अंसारी के निर्देश पर नेपाल व अन्य जगहों से हथियार लाकर उन्हें तय स्थान पर रखते थे और गैंगस्टरों को पहुंचाते थे। क्राइम ब्रांच अब दिल्ली-एनसीआर के उन गैंगस्टरों को भी यूएपीए में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अंसारी से हथियार खरीदे थे। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अभी गैंगस्टरों पर बीएनएस की धारा के तहत ही मुकदमे होते थे, लेकिन अब यूएपीए लगने से उन पर शिकंजा और कसेगा। पुलिस अधिकारी का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर के तमाम गैंगस्टर अंसारी सिंडिकेट से ही अत्याधुनिक हथियार खरीदते हैं। जिनके भी तार अंसारी से जुड़ेंगे उन पर यूएपीए लगाया जाएगा। कुछ समय पहले क्राइम ब्रांच ने दक्षिण जिला के रोहित चौधरी को यूएपीए में गिरफ्तार किया। अब सलीम पिस्टल समेत अन्य पर भी पुलिस जल्द यूएपीए लगा सकती है। सलीम पिस्टल पहले शाहबाज अंसारी के लिए काम करता था। बाद में उसने खुद विदेश से हथियार मंगवाकर गैंगस्टरों को आपूर्ति करना शुरू कर दिया। अंसारी की तरह सलीम भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के सहयोग से भारत में हथियार तस्करी का धंधा करता है। सलीम को पिछले साल अगस्त में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच ने देशव्यापी छापेमारी कर 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें शाहबाज का दाहिना हाथ माना जाने वाला सोनू गुप्ता, शाहदरा से घनश्याम और खुर्जा से नवाब बड़े नाम शामिल थे। इसके ठीक बाद पुलिस ने एक कार को रोककर नेपाल रूट के हैंडलर इमरान और कामरान को गिरफ्तार किया। इमरान, सरगना शाहबाज अंसारी का साला है।

यह सिंडिकेट विदेश में सेना और स्पेशल फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खतरनाक हथियार भी गैंगस्टरों को सप्लाई करता है। अंसारी के गुर्गे नेपाल से गाड़ियों के भीतर गुप्त स्थान में हथियार छिपाकर दिल्ली लाते थे।

हादसे के बाद एमसीडी की टूटी नींद, 42 लंबित मामलों में होगी कार्रवाई

निहाल सिंह ● जागरण

सैदुलाजाब हादसा

- सैदुलाजाब में 81 इमारतें अवैध निर्माण के लिए चिन्हित, दूसरे इलाकों में भी होगी कार्रवाई
- एमसीडी ने अवैध निर्माण की ज्यादा संभावना वाले इलाकों के सर्वे के लिए बनाई टीम

नई दिल्ली : सैदुलाजाब में पांच मंजिला इमारत गिरने के हादसे में किरकिरी के बाद एमसीडी ने इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज करने की बात कही है। इलाके में चिह्नित 42 मामलों में कार्रवाई होगी। इसमें जिन मामलों में सीलिंग की जरूरत हैं, सीलिंग होगी। अगर ध्वस्त करने की जरूरत है तो निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। इतना ही नहीं इलाके में खिड़की एक्सटेंशन समेत दूसरे इलाके, जहां अवैध निर्माण की ज्यादा संभावना रहती है वहां सघनता से जांच अभियान चलेगा। ऐसे इलाकों के लिए सर्वे की टीम बना दी गई है जो अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलाके में छह लोगों को सीलिंग का नोटिस सोमवार को दिया गया था। इनको 72 घंटे के भीतर संपत्ति खाली करनी है। इसमें दो और संपत्तियों पर सीलिंग के लिए नोटिस दिया गया है। अधिकारी ने आगे बताया कि इलाके में अवैध निर्माण के लिए चिन्हित सभी इमारतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इलाके में 81 इमारतों को अवैध निर्माण के लिए चिह्नित किया गया था। इसमें 42 पर कार्रवाई शेष है। इन लंबित मामलों को निपटाने के लिए जहां नियमानुसार नोटिस देने की जरूरत है, सीलिंग का नोटिस दिया जाएगा। जहां अवैध निर्माण को गिराना है वहां उसे गिराने का काम किया जाएगा। सूत्रों ने आगे बताया कि इलाके में जहां अवैध निर्माण की ज्यादा संभावना रहती है, वहां पर जोनल टीम बनाकर सर्वे किया जा रहा है। मंगलवार को खिड़की एक्सटेंशन इलाके में सर्वे किया गया है।

डीजीसीए का आदेश

सिक्योरिटी होल्ड एरिया और टरमैक पर फोटोग्राफी के लिए एयरपोर्ट आपरेटर की अनुमति अनिवार्य, एयरपोर्ट आपरेटर को एयरपोर्ट पर की गई हर फोटोग्राफी का पूरा रिकार्ड तीन साल तक सुरक्षित रखना होगा

बिना अनुमति नहीं चमकेगा कैमरा, फोटोग्राफी के लिए तय की गई शर्तें

गौतम कुमार मिश्रा ● जागरण

आइजीआइ एयरपोर्ट। फाइल

नई दिल्ली : एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने 'एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 13' के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

नए आदेश के मुताबिक, अब एयरपोर्ट के सबसे संवेदनशील हिस्सों, सिक्योरिटी होल्ड एरिया और टरमैक (जहां विमान खड़े होते हैं) पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी के लिए एयरपोर्ट आपरेटर की लिखित और पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। इस आदेश के बाद अब यात्रियों द्वारा सुरक्षा जांच क्षेत्र यानि सिक्योरिटी होल्ड एरिया में मोबाइल निकालकर फोटो खींचने या विमान के पास खड़े होकर सेल्फी और रील बनाने पर कानूनी रूप से शिकंजा कस गया है।

डीजीसीए ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों और बिना अनुमति कैमरा चमकाने वालों पर विमानन कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों की तरह फोटोग्राफर की होगी सुरक्षा जांच, आईडी कार्ड जरूरी : आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फोटोग्राफी करने वाले किसी भी व्यक्ति (चाहे वह क्रू मेंबर हो या कोई अन्य पेशेवर) को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना होगा। इसके अलावा, ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा जारी एंट्री परमिट होना भी जरूरी है। एयरसाइड में जहां विमान रनवे पर होते हैं, में प्रवेश करते समय फोटोग्राफी करने वाले हर व्यक्ति को उसी तरह की कड़ी सुरक्षा जांचसे गुजरना होगा, जिससे एक आम हवाई यात्री गुजरता है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी।

विदेशी क्रू पर पाबंदी, तीन साल तक सुरक्षित रखना होगा रिकार्ड : एयरपोर्ट पर होने वाली किसी भी फोटोग्राफी में किसी विदेशी क्रू को शामिल नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में कोई विदेशी नागरिक फोटोग्राफी कर रहा है, तो संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से उसकी 'सिक्योरिटी क्लीयरेंस' होना अनिवार्य है। एयरपोर्ट आपरेटर को एयरपोर्ट पर की गई हर फोटोग्राफी का पूरा रिकार्ड तीन साल तक सुरक्षित रखना होगा। डीजीसीए जब भी चाहे, निरीक्षण के लिए इस रिकार्ड को मांग सकता है।

इन पांच शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगी अनुमति

- फोटोग्राफी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विमान या विमान के संचालन को खतरा न हो
- यात्रियों की आवाजाही, कार्गो (सामान) के मूवमेंट या सुरक्षित विमान संचालन के लिए बनाई गई किसी भी सुविधा में कोई बाधा न आए
- सुरक्षा या विमान संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ध्यान न भटके और न ही उनके काम में कोई रुकावट आए
- एयरपोर्ट परिसर के भीतर फोटोग्राफी या शूटिंग की वजह से किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो
- शूटिंग या फोटोग्राफी के नाम पर एयरपोर्ट परिसर के अंदर किसी भी तरह का अस्थायी या स्थायी ढांचा खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी

कैंडल मार्च निकालकर हादसे के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सैदुलाजाब में हादसे के मृतकों को गौतम नगर स्थित महाराजा रणजीत सिंह पार्क में कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। विपिन शर्मा

सैदुलाजाब में बिल्डिंग हादसे को लेकर फेडरेशन आफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फाइमा) की ओर से मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला गया। गौतम नगर स्थित बड़ा गुरुद्वारा से महाराजा रणजीत सिंह पार्क तक निकाले गए मार्च में डाक्टरों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। हादसे में मारे गए चार डाक्टरों और अन्य लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई।

फाइमा के फारेन मेडिकल ग्रेजुएट (एफएमजी) विंग के अध्यक्ष डा. जसवंत सिंह यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि हादसे की सरकार उच्चस्तरीय समिति बनाकर जांच करे और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मृतकों और घायलों के स्वजन को राहत राशि प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि 28 जून को होने वाली परीक्षा के लिए जो डाक्टर तैयारी कर रहे थे उनके लैपटाप और स्टडी मटीरियल मलबे में दबे हैं। सरकार से मांग है कि उनका सामान जल्द निकाला जाए। वहीं साकेत में कोचिंग संस्थान और पीजी नियमों के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाए।

54 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की जाती हैं। 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा जल संधि हुई थी। फरक्का नामक यह समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है।

वेनेजुएला के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की ओर भारत

अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगुएज गोम्स 3 से 7 जून तक भारत यात्रा पर

भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है वेनेजुएला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिगुएज गोम्स 3 से 7 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रही हैं। पहले वे एक जून को इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट में शामिल होने वाली थीं, लेकिन समिट टल जाने के कारण यह यात्रा कार्यकारी रूप में हो रही है। रोड्रिगुएज गोम्स विदेश मंत्री, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना तथा परिवहन मंत्रियों के साथ आ रही हैं, जो बताता है कि भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए वह बेहद गंभीर हैं। वैसे यह उनकी छठी भारत

डेल्सी एलोइना रोड्रिगुएज गोम्स। फाइल

यात्रा होगी। इसके पहले विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के तौर पर वह पांच बार भारत आ चुकी हैं। वह सत्य श्री साई बाबा की भक्त हैं और पूर्व में दो बार आंध्र प्रदेश स्थित पुत्तपर्थी (साई बाबा का आश्रम) का दौरा कर चुकी हैं।

बहरहाल, इस बार उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता होने की संभावना बताई जा रही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण समाप्त होने के बाद भारत ने वहां से तेल आयात में भारी वृद्धि कर दी है। पारंपरिक तौर पर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता रहा है लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इसमें बाधा आती रही है। पश्चिम एशिया की मौजूदा अस्थिरता व हार्मुज जलडमरूमध्य की बंदी के कारण रूस के बाद वेनेजुएला के कच्चे तेल की खरीद भारत बढ़ा चुका है। अप्रैल 2026 में भारत ने 1.25 करोड़ बैरल (छह वर्षों में सर्वाधिक) वेनेजुएला से क्रूड आयात किया। मई में यह बढ़कर औसतन 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जिससे वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। जानकारों के मुताबिक महंगा होने के बावजूद वेनेजुएला भारत के लिए अच्छा विकल्प साबित हो रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बाधित है और भारतीय रिफाइनरियां भारी-उच्च सल्फर वाले वेनेजुएला क्रूड को प्रोसेस करने में सक्षम हैं।

पीएम मोदी से द्विपक्षीय चर्चा करेंगी अंतरिम राष्ट्रपति

अंतरिम राष्ट्रपति यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय चर्चा करेंगी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत बातचीत होगी। भारत सरकार की तेल कंपनियां वेनेजुएला में ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही निवेश करती रही हैं। अब वहां बेहतर माहौल होने से ये कंपनियां वहां निवेश बढ़ाने को इच्छुक हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और आटोमोबाइल क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों का दौरा करेगा ताकि भारतीय तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझा जा सके और सहयोग के नए अवसर तलाशे जा सकें। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने तथा दोनों देशों के बीच विविध क्षेत्रों में गहरे सहयोग की उम्मीद है।

सीजेआइ सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के पांच नए जजों को दिलाई शपथ

नई दिल्ली में मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलवाते प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में पांच नए जजों शील नागू (पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश), श्री चंद्रशेखर (बांबे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश), संजीव सचदेवा (मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश), अरुण पल्ली (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश) और सीनियर एडवोकेट वी. मोहना को पद की शपथ दिलाई। मोहना जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद 'बार' (वकालत) से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला जज हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। स्वीकृत संख्या (सीजेआइ सहित) 38 है।

जिनका लेना-देना नहीं, वे जम्मू-कश्मीर पर टिप्पणी न करें: भारत

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत ने मंगलवार को यूरोपीय यूनियन (ईयू) और पाकिस्तान के बीच आठवीं रणनीतिक वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के उल्लेख को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत ने कहा, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

- यूरोपीय यूनियन-पाकिस्तान वार्ता के बाद संयुक्त बयान में किया गया था उल्लेख
- कहा, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न व अविभाज्य हिस्से

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में भारत का रुख दोहराते हुए कहा, "हम कहना चाहेंगे कि हम भारत के अंदरूनी मामलों पर संयुक्त बयान में ऐसे बेवजह के उल्लेख को खारिज करते हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। जिन लोगों का ऐसे मामलों में लेना-देना नहीं है, उन्हें इन पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।" विदेश मंत्रालय का यह बयान सोमवार को पाकिस्तान और ईयू के बीच वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद ने जम्मू-कश्मीर पर यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी, जबकि ईयू की तरफ से पाकिस्तानी पक्ष को यूक्रेन युद्ध के बारे में जानकारी दी गई। संयुक्त बयान में लिखा था, "पाकिस्तानी पक्ष ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर जानकारी दी। ईयू की तरफ से रूस के यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध के बारे में जानकारी दी गई।"

गत माह चीन- पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के उल्लेख को भी भारत ने खारिज कर दिया था। उसमें भी कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख देश के अभिन्न व अविभाज्य हिस्से हैं और किसी दूसरे देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उल्लेख पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा था कि भारत का रुख एक जैसा है और संबंधित पक्षों को यह अच्छी तरह पता है।

विदेशी मेहमानों को राहत, 180 दिन पूरे होने से पूर्व कभी भी कराएं वीजा का नवीनीकरण

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और पंजीकरण संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब छह माह या उससे अधिक अवधि के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिक 180 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय अपना पंजीकरण या वीजा नवीनीकरण करा सकेंगे। वहीं, निर्धारित समयसीमा चूकने वालों के लिए नियम पहले से अधिक सख्त कर दिए गए हैं। नए नियम सुविधा और सख्ती के बीच संतुलन बनाने की दिशा में कदम माने जा रहे हैं।

- वीजा नियमों में बड़ा बदलाव, सहूलियत के साथ देरी पर बढ़ी सख्ती
- विदेशी नागरिकता पाने वाले बच्चे की जानकारी 30 दिन में देना होगा अनिवार्य

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आव्रजन एवं विदेशी (संशोधन) नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इनका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना और अनुपालन को अधिक प्रभावी बनाना बताया गया है। अब तक व्यवस्था यह थी कि 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होता था। संशोधित नियमों में यह सुविधा दी गई है कि विदेशी नागरिक अवधि समाप्त होने से पहले ही कभी भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, समयसीमा बीत जाने के बाद पंजीकरण केवल आपात या अप्रत्याशित परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा। सरकार ने बच्चों की नागरिकता संबंधी मामलों में भी स्पष्टता बरती है। यदि भारत में रहने के दौरान किसी बच्चे को विदेशी नागरिकता मिलती है, तो माता-पिता में से किसी एक को 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी। हालांकि, यह प्रविधान उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है। संशोधन के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए भी रिपोर्टिंग संबंधी नियमों को अपडेट किया गया है, ताकि विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव डिजिटल अपील व्यवस्था का है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति निर्धारित आनलाइन पोर्टल के माध्यम से 30 दिनों के भीतर आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा। आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद 60 दिनों के भीतर अपील के निस्तारण का प्रयास करना होगा।

भाजपा अध्यक्ष से मिला नेपाली प्रतिनिधिमंडल, जेन-जी समेत कई अहम मुद्दों पर भी की चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नेपाल में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचा। नेपाल की संसद में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर बयानबाजी ने वहां भले ही पारा चढ़ा दिया हो, लेकिन यहां आपसी रिश्तों की गर्माहट में कोई कमी नहीं थी। प्रतिनिधिमंडल का यहां भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद आरएसपी अध्यक्ष रवि लामीछने और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच आत्मीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने राजनीति और लोकतंत्र में जेन-जी की भूमिका सहित कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की।

नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामीछने। एएनआइ

- सीमा विवाद को लेकर बयानबाजी के बीच भाजपा मुख्यालय पहुंचा आरएसपी का प्रतिनिधिमंडल
- नितिन नवीन ने उन्हें मोदी के नेतृत्व में जनहित की योजनाओं व सुशासन माडल के बारे में बताया

भाजपा अध्यक्ष ने बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक और जन-जन के संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने इस तरह की भेंट-वार्ता को लोकतांत्रिक संवाद के साथ ही भाजपा और आरएसपी के संबंधों को मजबूत करने में सहायक बताया। नितिन नवीन ने नेपाल से आए मेहमानों को भाजपा की राजनीतिक यात्रा, विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और जनकेंद्रित राजनीति के बारे में बताया। भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की जनहित की योजनाओं और सुशासन के माडल के बारे में भी बताया। आरएसपी के अध्यक्ष भाजपा सदस्यता प्रक्रिया, प्रत्याशी चयन और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के चयन एवं जुड़ाव को बनाए रखने की व्यवस्था को जानने को उत्सुक दिखाई दिए। इस भेंट वार्ता में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, संजय जायसवाल आदि शामिल हुए। प्रेट्र के अनुसार, लामीछने ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय विकास साझेदारी व लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

बांग्लादेश से गंगा जल साझा करने से संबंधित मुद्दों की जांच करेगा भारत

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश के साथ गंगा जल साझा करने के समझौते से संबंधित मुद्दों की जांच करेगा। भारत-बांग्लादेश के बीच साझा नदियों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र होने पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा,गंगा जल साझा करने के समझौते से संबंधित मामले मौजूदा सहयोग ढांचे के भीतर विचार किए जाएंगे। चूंकि गंगा जल संधि इस वर्ष के अंत में समाप्त होने वाली है, इसका नवीनीकरण भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने की उम्मीद है।

- समझौते के मामले मौजूदा सहयोग ढांचे में विचार किए जाएंगे : विदेश मंत्रालय

रणधीर जायसवाल।

गंगा जल संधि इस वर्ष के अंत में समाप्त होनी है, इसका नवीनीकरण अहम मुद्दा

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के महासचिव और ग्रामीण विकास और सहकारी मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के गंगा जल साझा करने के समझौते पर हालिया टिप्पणियों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दिया। जायसवाल ने कहा, "हमारे पास 54 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की जाती हैं। हमारे पास संयुक्त नदियों का आयोग है, जो उन सभी नदियों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए संरचित द्विपक्षीय तंत्र है जो हम भारत-बांग्लादेश के बीच साझा करते हैं। हम इन मुद्दों को भी नदियों पर हमारे संरचित द्विपक्षीय सहयोग के हिस्से के रूप में देखेंगे।" वहीं, आलमगीर ने कह कि बांग्लादेश और भारत के बीच मजबूत संबंधों का भविष्य गंगा जल साझा करने के समझौते के नवीनीकरण पर निर्भर करता है, जिसे सामान्यतः फरक्का संधि के नाम से जाना जाता है, जो दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। मौजूदा गंगा जल साझा करने की संधि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। इसने सूखे के महत्वपूर्ण मौसम (जनवरी-मई) के दौरान गंगा के जल को साझा करने के लिए 30 वर्षों का ढांचा प्रदान किया।

ब्रिक्स संस्कृति समूह की बैठक कल से वाराणसी में, कई मुद्दों पर मंथन

जागरण संवाददाता, वाराणसी

ब्रिक्स देशों के संस्कृति कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) की बैठक वाराणसी में चार और पांच जून को होटल ताज में होगी। इसमें भारत समेत ब्रिक्स से जुड़े 11 देशों के 30 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इंडोनेशिया समेत कई देशों के प्रतिनिधिमंडल मंगलवार देर रात और बुधवार दोपहर तक वाराणसी पहुंचेंगे। बैठक में एआइ, जलवायु परिवर्तन और चोरी हुई सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

- भारत समेत 11 देशों के 30 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, स्वागत की तैयारी पूरी
- ओडीओपी और जीआइ उत्पादों से रूबरू होगी दुनिया, आज पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से होटल ताज तक स्कूली बच्चे विभिन्न देशों के झंडे लहराकर मेहमानों का स्वागत करेंगे। 'हर-हर महादेव' के उद्घोष के बीच सांस्कृतिक दल और डमरू वादन दल काशी की लोक परंपरा व सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करेगा। होटल परिसर में काशी और उत्तर प्रदेश के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) तथा जीआइ टैग प्राप्त उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे विदेशी प्रतिनिधि प्रदेश की कला, शिल्प और पारंपरिक उत्पादों से परिचित हो सकेंगे। बैठक में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने और हस्तकला व संस्कृति से जुड़े समझौतों (एमओयू) पर भी सहमति बनने की संभावना है। सम्मेलन में शामिल विदेशी मेहमान गंगा घाटों का भ्रमण करेंगे, नौका विहार का आनंद लेंगे और विश्वप्रसिद्ध गंगा आरती भी देखेंगे। कुछ प्रतिनिधियों के सारनाथ भ्रमण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

इन देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल : ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया व भारत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में संस्कृति मंत्रालय की सचिव समेत कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

महाराष्ट्र में किसानों को दो लाख तक की कर्जमाफी

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना को हरी झंडी दिखा दी गई। इस योजना के तहत राज्य के संकटग्रस्त किसानों का दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के 56 लाख किसानों को सीधे तौर पर कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी।

मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, इस कर्ज माफी योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका कृषि ऋण 30 सितंबर, 2025 तक बकाया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक पारदर्शी और व्यापक योजना है, जिसमें किसी भी प्रकार के अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा एलान किया है। जो किसान ईमानदारी से अपने ऋण की किस्तें समय पर चुकाते रहे हैं और डिफाल्टर नहीं हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ऐसे नियमित कर्जदाता किसानों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेगी। किसानों को दी गई इस कर्जमाफी से महाराष्ट्र सरकार के बजट और राजकीय तिजोरी पर 36,585 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पूर्व में पेश किए गए 7.69 लाख करोड़ के वार्षिक बजट (2026-27) में ही इस योजना का वित्तीय खाका तैयार कर लिया गया था। हालांकि, इतनी बड़ी राशि के आवंटन से राज्य के बजट पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों के साथ ही किसानों को राहत देना अपनी शीर्ष प्राथमिकता माना है। यह कर्ज माफी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले 'महायुति' गठबंधन द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किया गया एक प्रमुख और बड़ा चुनावी वादा था। चुनाव जीतने के बाद से ही सरकार इस योजना को लागू करने की तैयारी में जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया आगामी 30 जून से पहले हर हाल में पूरी की जाए, ताकि खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले किसान नए सिरे से फसलों के लिए ऋण प्राप्त कर सकें।

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय

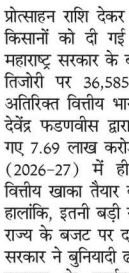
देवेंद्र फडणवीस।

इसका लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका कृषि ऋण 30 सितंबर, 2025 तक है बकाया

प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद भी सरकार की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं : मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगने के बावजूद सरकार की तरफ से अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल, राज्य में वर्तमान में विधान परिषद चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। इस कारण कैबिनेट के इस बड़े फैसले की कोई औपचारिक या आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा फिलहाल टाल दी गई है। सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता समाप्त होते ही सहकारिता विभाग द्वारा इस योजना के विस्तृत नियम-शर्तें और क्रियान्वयन का परिपत्रक (जीआर) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को मानसून से ठीक पहले बड़ी राहत मिल सकेगी।

जर्मनी के एयरपोर्ट पर आज से भारतीयों को ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : जर्मनी के हवाईअड्डे पर भारतीयों को अब ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। जर्मनी ने भारतीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। जर्मनी के दूतावास ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय तीन जून बुधवार से प्रभावी होगा। हर साल, छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों सहित बड़ी संख्या में भारतीय जर्मन हवाईअड्डों के रास्ते अन्य देशों में जाते हैं। जर्मन दूतावास ने कहा, जर्मनी के हवाईअड्डे पर ठहराव के साथ किसी अन्य देश की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को अब ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। जर्मनी ने इस बाबत मंगलवार को राजपत्र आदेश जारी किया। यह निर्णय जर्मन-भारतीय संबंधों की मजबूती, लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए जर्मनी की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज की इसी साल जनवरी में हुई भारत यात्रा के दौरान इसे लेकर वार्ता हुई थी। यह फैसला उसी का परिणाम है। ट्रांजिट वीजा विशेष और अस्थायी परमिट होता है, जो किसी यात्री को अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते में किसी तीसरे देश से होकर गुजरने या वहां कुछ घंटे/दिन रुकने की अनुमति देता है।

- जर्मन हवाईअड्डों के रास्ते अन्य देशों में जाने वाले भारतीयों को मिलेगी राहत

अलनीनो के संभावित खतरे को लेकर अलर्ट मोड में सरकार

तैयारियां

कृषि मंत्री शिवराज ने उच्चस्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की, फसल, बीज, पानी और किसानों तक सलाह पहुंचाने पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मानसून के दस्तक देने से पहले केंद्र सरकार अलनीनो के संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई है। सरकार का मानना है कि यदि अलनीनो का खतरा बढ़ता है तो खरीफ फसलों पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए इस बार तैयारी संकट आने के पहले की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मानसून की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर किसी भी चुनौती का समय रहते सामना किया जाए।

दरअसल, खरीफ का सीजन देश की खाद्य सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। धान, मक्का, दालें और तिलहन जैसी प्रमुख फसलें इसी मौसम में बोई जाती हैं। ऐसे में अलनीनो का खतरा केवल मौसम का मुद्दा नहीं, बल्कि उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। यही वजह है कि घबराने की जगह इससे निपटने की तैयारी रखने पर जोर दिया जा रहा है।

शिवराज सिंह चौहान। फाइल

जल संरक्षण पर भी विशेष फोकस

बैठक में जल संरक्षण को भी प्रमुख रणनीति के रूप में शामिल किया गया। तालाबों, जलाशयों और अन्य जल संरचनाओं में उपलब्ध पानी के बेहतर उपयोग पर बल दिया गया। सरकार का आकलन है कि यदि मानसून कमजोर रहता है तो पहले से संरक्षित जल किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अभी जलाशयों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27 प्रतिशत पानी अधिक है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने इस वर्ष मानसून सामान्य का करीब 90 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

ऐसे में बड़ी चिंता उन क्षेत्रों को लेकर है जहां खेती अब भी बारिश पर निर्भर है। देश के लगभग आधे कृषि क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और वहां किसानों की उम्मीदें सीधे मानसून से जुड़ी रहती हैं। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की रणनीति केवल बारिश का इंतजार करने की नहीं है, बल्कि कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने की है। इसी वजह से राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसल योजना बनाने, कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली किस्मों को बढ़ावा देने और किसानों तक समय पर वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने को कहा गया है।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अलनीनो का सबसे बड़ा असर बारिश के वितरण पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार कुल वर्षा बहुत कम नहीं होती, लेकिन उसका समय और क्षेत्रीय वितरण असंतुलित हो जाता है। इससे देश के विभिन्न राज्यों में बोआई, अंकुरण और फसल की शुरुआती वृद्धि प्रभावित होती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार इस बार सिर्फ कुल वर्षा के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि जिलावार मौसम की निगरानी पर जोर दे रही है।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

75 कारतूस और 100 से अधिक खोखे दक्षिण 24 परगना जिले के जीवनतल्ला इलाके में तृणमूल नेता व पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के बेहद करीबी माने जाने वाले स्थानीय तृणमूल नेता जाबेद शेख के घर पर छापेमारी कर पुलिस ने बरामद किए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 03 जून, 2026

शाह से मिलकर नरम पड़े अन्नामलाई, पीएम से मिलने के बाद लेंगे फैसला

सकारात्मक संकेत ▶ तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्रन को दिल्ली बुलाया गया

शाह से भेंट के पहले नितिन नवीन और बीएल संतोष से मिले अन्नामलाई

नीलू रंजन • जागरण

नई दिल्ली : भाजपा से इस्तीफा देने पर अड़े तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद नरम पड़ गए हैं। अब उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात होगी, उसके बाद ही वह इस्तीफे को लेकर अंतिम फैसला करेंगे। इस बीच तमिलनाडु के भाजपा नेताओं से अन्नामलाई की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को दिल्ली बुला लिया गया है। अमित शाह से मिलने के पहले अन्नामलाई ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, अमित शाह और अन्नामलाई के बीच विजय

भाजपा छोड़ने की अटकलों के बीच के . अन्नामलाई ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रेट्र

की ऐतिहासिक जीत के बाद तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियों और भविष्य की राजनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान अन्नामलाई ने पार्टी से अलग होकर कोयंबटूर से एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने के बारे में बताया। इस पर अमित शाह ने कहा कि यह जनसंपर्क अभियान भाजपा के बैनर तले भी हो सकता है और यह ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन अन्नामलाई ने प्रदेश भाजपा नेताओं के अन्नाद्रमुक और द्रमुक के साथ भीतरी गठजोड़ का हवाला देते हुए कहा कि वे इसे सफल नहीं होने देंगे। इसके जवाब में अमित शाह ने अन्नामलाई को केंद्रीय संगठन की ओर से पूरी तरह से सहयोग और प्रदेश नेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने का भरोसा दिया।

भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने मीडिया में चल रहे अन्नामलाई की ओर से नितिन नवीन को सौंपे गए पांच पन्नों के इस्तीफे से भी इन्कार किया। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन और बीएल संतोष दोनों के साथ मुलाकात में अन्नामलाई ने मौखिक रूप से इस्तीफे की बात जरूर की थी। लेकिन दोनों नेताओं ने उन्हें अमित शाह से मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लेने का अनुरोध किया था।

अन्नामलाई के तेवर नरम पड़ने के बाद भाजपा में उनके दायित्व को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इनमें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से लेकर केंद्रीय संगठन में अहम पद देने की बात की जा रही है। लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद ही तय होगा।

ध्यान देने की बात है कि अन्नामलाई विधानसभा चुनाव के पहले अन्नाद्रमुक से गठबंधन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर नाराज चल रहे थे। अन्नाद्रमुक से गठबंधन से पहले अन्नामलाई को हटाकर नयनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था।

कर्नाटक में सियासी संतुलन का तराजू लेकर सीएम पद की शपथ लेंगे शिवकुमार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ कांग्रेस की नई सरकार के मंत्रिमंडल पर हाईकमान ने शिवकुमार और सिद्दरमैया से की मंत्रणा

कर्नाटक में कांग्रेस के नए नेतृत्व के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री पद की बुधवार को शपथ लेने जा रहे डीके शिवकुमार के समक्ष अपने मंत्रिमंडल में राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों में संतुलन बनाने की चुनौती है। इसके मद्देनजर ही कांग्रेस हाईकमान ने शिवकुमार तथा निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के साथ नई कैबिनेट के स्वरूप पर मंत्रणा की। सिद्दरमैया के समर्थकों को भी नई सरकार में समायोजित किए जाने के पुख्ता संकेत हैं। वहीं, सियासी-सामाजिक समीकरण साधने के लिए दो से तीन उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर डीके शिवकुमार और सिद्दरमैया संग हुई बैठक में नई कैबिनेट के चेहरों पर मंत्रणा हुई। समझा जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने वादे के अनुरूप सिद्दरमैया को आश्वासन दिया है कि सूबे में उनके सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए मंत्रिमंडल में उनके समर्थकों को उचित भागीदारी दी जाएगी।

कर्नाटक सरकार में मुख्यमंत्री समेत 34 मंत्री ही हो सकते हैं। शिवकुमार अपने छोटे मंत्रिमंडल के साथ बुधवार

डीके शिवकुमार। फाइल

को पहले शपथ लेंगे और फिर उसका विस्तार करेंगे।

मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बुधवार को बेंगलुरु में डीके शिवकुमार के शाम 4:05 बजे होने वाले शपथ समारोह में शामिल होंगे। पार्टी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजनीतिक सामाजिक समीकरणों तथा 2028 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दलित, लिंगायत और अहिंदा तीनों समुदायों से एक-एक उपमुख्यमंत्री हो सकता है। दलित समुदाय से वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर के साथ प्रियांक खरगे डिप्टी सीएम की दौड़ में शामिल हैं। इसी तरह सिद्दरमैया के बेटे यतींद्र को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है और वह स्वयं हाईकमान से इसका आश्वासन दिए जाने की बात कह चुके हैं। वैसे भी शीर्ष नेतृत्व सिद्दरमैया को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसलिए, संकेत हैं कि सरकार तथा संगठन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता सिद्दरमैया को सौंपी जाएगी।

मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिवकुमार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सतीश जारकीहोली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान संग सरकार के स्वरूप पर हुई इस मंत्रणा के दौरान कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों के चुनाव पर भी कुछ चर्चा हुई, जिसमें तीन सीटें पार्टी को मिलनी तय हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खरगे की एक सीट पर उम्मीदवारी तय है तो दूसरी सीट पर हाईकमान सिद्दरमैया को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है, लेकिन वे सूबे की राजनीति छोड़ने पर अभी राजी नहीं हुए हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिला को राज्यसभा की तीसरी सीट देकर नेतृत्व आंध्र में पार्टी को खड़ा करने का बड़ा दांव चलना चाहता है।

बंगाल में पुरुषों को मिल रहा था 'विधवा भत्ता' और लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▶ सत्ता बदलने के बाद सरकारी योजनाओं में खजाने की खुली लूट आई सामने

▶ सीएम का दावा, राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना के 30 लाख फर्जी लाभार्थी

बंगाल में सत्ता बदलने के बाद सरकारी योजनाओं में हुए चौंकाने वाले घोटालों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर चल रही जांच में 'लक्ष्मी भंडार', 'आमफन राहत कोष', '100 दिन रोजगार योजना (मनरेगा)' और 'विधवा भत्ता' जैसी कल्याणकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार और जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है।

पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला ब्लाक में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई। यहां पुरुष डा अमलेंदु विकास मंडल के खाते में महीनों से विधवा भत्ते की राशि जमा हो रही थी। पुलिस ने आरोपित डाक्टर को गिरफ्तार किया है। डाक्टर ने खाते में पैसे आने की बात स्वीकार की है, लेकिन इसे प्रशासनिक लापरवाही या तकनीकी गड़बड़ी का नाम दिया जा रहा है।

नदिया जिले के कृष्णनगर-दो ब्लाक में महिलाओं के लिए चलाई जा रही 'लक्ष्मी भंडार' योजना का लाभ 173

शुभेंदु अधिकारी। फाइल

पुरुष उठा रहे थे। विधानसभा चुनाव से महज दो महीने पहले, फरवरी से इन पुरुषों के खातों में अवैध रूप से पैसे भेजे जा रहे थे। इस जालसाजी के आरोप में बीडीओ कार्यालय के एक कर्मचारी भोला शील को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि राज्यभर में करीब 30 लाख फर्जी लाभार्थियों ने इस योजना के तहत जनता के हजारों करोड़ रुपये लूटे हैं, जिसकी जांच के लिए एसआइटी का गठन किया गया है।

10 हजार फर्जी मछुआरों के खाते में 20-20 हजार ट्रांसफर : भ्रष्टाचार का दूसरा बड़ा मामला दक्षिण 24 परगना के फलता में सामने आया है। साल 2020 में चक्रवात 'आमफन' का लैंडफाल सागर द्वीप में हुआ था, लेकिन मुआवजे की भारी-भरकम राशि 80 किलोमीटर दूर फलता में बांट दी गई। कागजों पर 10 हजार फर्जी मछुआरों की सूची बनाकर प्रत्येक के खाते में 20-20 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए, जबकि स्थानीय वास्तविक पीड़ित अब भी दाने-दाने को मोहताज हैं। इस घोटाले के पीछे अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान का नाम सामने आ रहा है, जो फिलहाल फरार है। इसके अलावा, डायमंड हार्बर के दियारक अंचल में तृणमूल के बंद कार्यालय का ताला तोड़ने पर बड़ी संख्या में गरीबों के जाब कार्ड और राशन कार्ड बरामद हुए हैं। आरोप है कि नेताओं ने 100 दिन के काम का पैसा खुद हड़प लिया।

जो शोहदा बोली से नहीं माना, गोली से जरूर मान गया : योगी

अजय कुमार शुक्ल • जागरण

▶ कट्टा-बम नहीं, अब उत्तर प्रदेश में बनती है मिसाइल, जिससे पाक भी करता है बाप-बाप

▶ कहा- समाजवादी पार्टी घोषित रूप से रामद्रोही है, कांग्रेस ने भी उसका दिया है पूरा साथ

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हमारी बहन-बेटियों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। हमने शोहदों को ठीक किया, जो बोली से नहीं माना, गोली से जरूर मान गया। अब यूपी में कट्टा और बम नहीं बनते, जिनसे दंगे के साथ बेरोजगारी आती थी। अब उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनती है, जिसके दागने पर पाकिस्तान बाप-बाप करता है। मुख्यमंत्री मंगलवार को तमकुहीराज में 424 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहीं, आपराधिक गतिविधियों को फलने-फूलने की अनुमति दी। बिना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए, उन्होंने पूर्व की सरकार को 'जंगल पार्टी' के रूप में संदर्भित किया। कहा कि 2017 से पहले जंगल पार्टी का आतंक था और माफिया का राज था। पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष में देश व प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। हमने

तमकुहीराज स्थित एनएचआइ के पार्किंग ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

माफिया, जो बेरोजगारी और मच्छर जो बीमारी देने का काम करते थे, दोनों को एक साथ समाप्त किया। मुख्यमंत्री बोले, यूपी में अब विकास के साथ रोजगार की बात होती है, परिवारवाद की बात नहीं होती। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। विकास के लिए प्रदेश के खजाने का मुंह आपकी तरफ खोल दूंगा।

मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर की बात करते हुए कहा कि सपा घोषित रामद्रोही है, कांग्रेस को भी इसका साथ देने वाली पार्टी बताया। कहा, श्रीराम मंदिर बनने में 498 वर्ष लग गए। भाजपा की सरकार बनी तो भव्य नव्य श्रीराम मंदिर अपनी पुरानी विरासत के साथ खड़ा है। अयोध्या अपने वैभव के साथ त्रेता युग की याद दिला रही है।

योगी ने की फाजिलनगर का नाम पावागढ़ करने की घोषणा: योगी ने बंद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शीघ्र हवाई सेवा शुरू करने की बात कही। फाजिलनगर का नाम बदल कर पावागढ़ करने की भी घोषणा की। कहा कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के साथ पावागढ़ का नाम भी प्रमुखता प्राप्त करेगा।

पावागढ़ की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़कर, देश और दुनियाभर के लोग इस पवित्र स्थान की ओर आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विकास के नाम पर पीछे धकेलने का जिम्मेदार कांग्रेस व सपा को ठहराते हुए कुशीनगर का उदाहरण दिया। कहा कि वैदिक व रामायणकाल की साक्षी बुद्ध और महावीर की धरती की पहचान मुखमरी व बीमारी के लिए थी। अब मेडिकल कालेज व कृषि विश्वविद्यालय है, जहां से डाक्टर और विज्ञानी तैयार होंगे। उन्होंने निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इसी सत्र से शैक्षणिक कार्य शुरू कराने को कहा।

हिंसा के विरोध में ममता का धरना, कहा-भाजपा को हटाए बिना नहीं रुकूंगी

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▶ टीएमसी सुप्रीमो ने पार्टी में टूट कराने की साजिश रचने का लगाया आरोप

▶ धरनास्थल पर केवल छह विधायक और पांच सांसद आए नजर

बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार बड़े सार्वजनिक मंच से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कोलकाता के वाई चैनल में मंगलवार को आयोजित धरना मंच से उन्होंने कहा कि वह आखिरी सांस तक भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ती रहेंगी और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। भाजपा को हटाए बिना नहीं रुकूंगी। मतदान के बाद हिंसा के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने धरना कार्यक्रम आयोजित किया था। धरने में पार्टी के अपेक्षित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी नहीं दिखी। धरनास्थल पर केवल छह विधायक और पांच सांसद ही नजर आए।

शुभेंदु सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि भाजपा में अब पुराने कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि अन्य दलों से आए नेताओं की चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

कोलकाता के एस्प्लेनेड में मंगलवार को आयोजित धरने को संबोधित करती टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। एएनआइ

दिल्ली से तृणमूल को कमजोर करने और पार्टी में टूट कराने की साजिश रची जा रही है।

माइक तक की नहीं मिली अनुमति: धरना कार्यक्रम को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ममता ने कहा कि उन्हें माइक तक की अनुमति नहीं मिली और हैंड माइक के सहारे भाषण देना पड़ रहा है।

विपक्ष के नेता को लेकर विधानसभा में दिनभर चला राजनीतिक ड्रामा

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर मंगलवार को नया राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि विधानसभा के नियमों के अनुसार विपक्ष के नेता के चयन के मामले में संबंधित राजनीतिक दल द्वारा स्पीकर को दिया गया पत्र ही अंतिम और निर्णायक दस्तावेज होता है। इसी आधार पर पार्टी ने स्पीकर के नाम एक महत्वपूर्ण पत्र विधानसभा में जमा कराने की कोशिश की।

हालांकि, उस समय स्पीकर दिल्ली में होने के कारण विधानसभा में मौजूद नहीं थे। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि स्पीकर के सचिव ने विपक्षी दल का पत्र स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि सचिव ने यह कहकर पत्र लेने से मना कर दिया कि स्पीकर की अनुपस्थिति में वह विपक्ष की ओर से कोई पत्र स्वीकार नहीं करेंगे।

कुणाल घोष ने बताया कि सचिव द्वारा पत्र नहीं लेने के बावजूद तृणमूल नेताओं ने पत्र उनके कार्यालय की मेज पर रख दिया और पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी रिकार्ड किया।

किसी की बपौती नहीं है सरकारी बंगला, हर हाल में करना पड़ेगा खाली : सम्राट

जागरण टीम, पटना

▶ मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी पर आवास खाली नहीं करने को लेकर साधा निशाना

▶ कोई भी अपराधी पुलिस को चुनौती देता है तो 48 घंटे के अंदर मिलेगा जवाब

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं। बिहार में लोकतंत्र है। यहां कानून का राज है। बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। इसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। उनका निशाना लालू परिवार पर था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास खाली नहीं करने को लेकर उन्होंने कहा कि पति, पत्नी, बेटा के लिए अलग-अलग आवास चाहिए। सभी को अलग-अलग सुरक्षा चाहिए। उन्हें नीति सिद्धांत से मतलब नहीं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो आवास भी 15 दिनों में खाली कर दिया, मगर कुछ लोग यहां राजतंत्र चलाना चाहते, मगर ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में सहयोग शिविर का शुभारंभ करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।

उल्लेखनीय है कि राबड़ी देवी को पिछले साल 15 दिसंबर को ही 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कराने का

सम्राट चौधरी । एएनआइ

पत्र भवन निर्माण विभाग ने भेजा था। फिर 29 मई को रिमाइंडर भेजा गया है।

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि वे वर्ष 1999 से विभिन्न सरकारी पदों पर हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे 3,400 वर्गफीट के निजी आवास में रहते थे। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहने के बाद भी वह पिता के घर में रहे। पिताजी ने घर का एक हिस्सा दिया था। पीएम मोदी, नीतीश कुमार, एनडीए के नेता और जनता ने मुख्यमंत्री बनाया तो सीएम आवास में आया हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी आपको एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी अपराधी या गुंडा पुलिस को चैलेंज करता है तो उसे 48 घंटे में जवाब मिलेगा।

समय आया तो हवाई चप्पल पहन निकल जाएंगी राबड़ी

राजद प्रदेश इकाई के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राबड़ी देवी जब तक पद पर हैं, तब तक सरकारी बंगले में रहने की अधिकारी हैं। हालांकि, उन्होंने समय पर हवाई चप्पल पहनकर राबड़ी के निकल जाने का भी हवाला दिया। सोमवार को राजद ने कहा था कि अगर राबड़ी देवी से सरकारी बंगला खाली कराया गया, तो राजद के सभी विधायक व विधान पार्षद सरकारी आवास खाली कर देंगे।

वंदे मातरम पर कांग्रेस-भाजपा में छिड़ी रार

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरलम विधानसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े सियासी महासंग्राम में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़े वाक् युद्ध ने देश के आत्मगौरव और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। दोनों दल एक-दूसरे पर तुष्टीकरण और राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में वंदे मातरम् के सभी पांच अंतरों (स्टैंजा) को गाए जाने की अनिवार्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे दर्शकों पर एक 'अनावश्यक बोझ' करार देते हुए कहा कि आम तौर पर लोग इसके शुरुआती कुछ छंद ही जानते हैं।

थरूर के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह कांग्रेस की उसी पुरानी मानसिकता को दर्शाता है जिसके तहत पंडित नेहरू ने जिन्ना के दबाव में आकर वंदे मातरम् को सिर्फ दो अंतरों तक सीमित कर दिया था।

बदलाव के रंग

ज्योति बसु से शुभेंदु अधिकारी की सरकार में पहुंची राजनीतिक विरासत

मां थीं वाममोर्चा सरकार में मंत्री, बेटी भाजपा के मंत्रिमंडल में

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

बंगाल की राजनीति में एक दिलचस्प और प्रतीकात्मक अध्याय जुड़ गया है। मां पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकार में मंत्री थीं, बेटी अब भाजपा सरकार में मंत्री बनी हैं। कांदी से भाजपा विधायक गार्गी दास घोष ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही मंत्रिपद की शपथ ली है। 60 वर्षीया गार्गी ने गत विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी अपूर्व सरकार को 10 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया। गार्गी ने बचपन से अपनी मां छाया घोष को विधायक और मंत्री के रूप में काम करते देखा। छाया घोष वाममोर्चा के शासनकाल की चर्चित नेताओं में से एक थीं।

छाया घोष 1977 में मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्र से फारवर्ड ब्लाक के टिकट पर पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1982, 1991 और 2001 में भी

कोलकाता में सोमवार को मंत्री पद की शपथ के बाद अभिवादन करतीं भाजपा विधायक गार्गी दास घोष। आइएएनएस

विधायक चुनी गईं।

उन्हें 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बनाया गया था। वह ज्योति बसु सरकार में 1996 तक मंत्री रहीं। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार में 2001 से 2005 तक कृषि विपणन मंत्री के रूप में कार्य किया। 2005 में पोस्ता खेती से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था और फारवर्ड ब्लाक ने भी उन्हें निलंबित कर दिया।

2006 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वह जनवादी फारवर्ड ब्लाक में शामिल हो गई थीं। 12 फरवरी, 2010 को उग्र संबंधी समस्याओं के कारण उनका निधन हो गया था। अब वर्षों बाद उनकी बेटी गार्गी मंत्री बनी हैं।

मंत्री बनीं सुमना के पिता कांग्रेस के पूर्व विधायक, भाई तृणमूल में

राजनीतिक परिवार से आने वालीं सुमना सरकार का सफर विचारधाराओं और दलों के बदलाव से भरा है। उनके पिता बीरन सरकार कांग्रेसी विधायक रह चुके हैं, जबकि भाई तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। खुद सुमना भी एक समय तृणमूल में सक्रिय थीं। 2021 के विस चुनाव से पहले सुमना ने भाजपा का दामन थामा और 'दुर्गा वाहिनी' से जुड़कर संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस बार चुनाव में जीत दर्ज कर सीधे मंत्रिपद तक पहुंच गईं। हुगली के बलागढ़ की रहने वालीं सुमना छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ी रही हैं।

55 साल बाद फिर मंत्रिमंडल में गोरखा चेहरा

कालचीनी से विधायक विशाल लामा को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वह 1971 के बाद पहले ऐसे गोरखा नेता हैं, जिन्हें राज्य में मंत्रिपद मिला है। विश्लेषकों के अनुसार, उनकी नियुक्ति दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र और डुआर्स के गोरखा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। विशाल लामा ने 2008-09 के दौरान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। 2012 में भाजपा में शामिल हो गए। 2016 के विस चुनाव में हार गए। 2021 में पहली बार विधायक बने और 2026 में फिर जीत दर्ज की।

प्लातिलाल बोले-घरेलू सहायिका नहीं, मंत्री बनी कलिता मेरी बेटी है

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर

बंगाल की शुभेंदु सरकार में मंत्री बनीं कलिता माझी मेरी मुंहबोली बेटी हैं। मेरी बेटी का निधन हो गया था, जिसके बाद घर में जो खालीपन आया, उसे उन्होंने ही भरा था। पहले वह मुझे 'काका' कहती थीं, लेकिन बाद में 'बाबा' कहकर पुकारने लगीं। यह कहते हुए प्लातिलाल पात्रा भावुक हो उठते हैं। प्लातिलाल के घर पर ही कलिता घरेलू सहायिका के तौर पर कार्य करती थीं।

कलिता के मंत्री बनने के बाद जब प्लातिलाल से बात की गई तो उन्होंने उनसे अपने रिश्तों के बारे में तो बात की ही साथ ही उम्मीद जताई कि अब क्षेत्र की खराब सड़कें, बदहाल अस्पताल और विकास के अन्य रुके काम कलिता के नेतृत्व में जरूर पूरे होंगे।

प्लातिलाल की पत्नी कृष्णा कहती हैं कि एक मंत्री के रूप में कलिता अपनी सभी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ पूरी करेंगी।

कलिता भी इस बात को सहर्ष स्वीकार करती हैं कि पात्रा परिवार ने उन्हें कभी भी केवल घरेलू सहायिका की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि हमेशा परिवार के एक सदस्य और बेटी का दर्जा दिया।

प्लातिलाल पात्रा और उनकी पत्नी कृष्णा पात्रा के साथ बंगाल की मंत्री कलिता माझी (बीच में)। स्रोत- इंटरनेट मीडिया

16 हजार से अधिक सीबीएसई के 12वीं के विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन के लिए मंगलवार अपराह्न तीन बजे तक सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके थे। इसके पहले विद्यार्थियों ने तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी।

संसदीय समिति के सामने 17 साल के सार्थक ने खोली गड़बड़ियों की पोल

समिति के सदस्यों ने अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ इनसे सीखो

छात्र ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया– टेंडर जिस कंपनी को दिया गया, उसकी जांच नहीं की गई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों पर वैसे तो संसदीय समिति से जुड़े सदस्यों को सीबीएसई से सवाल करने थे और उन्होंने किए भी लेकिन समिति के सामने पेश हुए 12वीं के छात्र सार्थक ने ओएसएम से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए, उससे समिति के मौजूद सदस्य दंग रह गए। समिति के सदस्यों ने न सिर्फ मेज थपथपाईं बल्कि सीबीएसई के अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ इनसे सीखो। वहीं, सार्थक के सवालों से सीबीएसई पूरी तरह से निरुत्तर दिखी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुआई वाली शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने 12वीं के छात्र सार्थक को बुलाया था। सार्थक ने इस दौरान एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही कहा कि मूल्यांकन के लिए अपनाई गए ओएसएम सिस्टम से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, न ही इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है। गड़बड़ी यह हुई कि इसका काम जिस कंपनी को दिया गया, उसकी कोई जांच नहीं की गई। उसके पास पूर्व में ओएसएम का कोई अनुभव नहीं है। सूत्रों की मानें तो सार्थक ने बताया कि कोएम्प्ट एडुकेट को टेंडर देने के लिए किस तरह ब्लैक लिस्टिंग के नियमों में बदलाव किया गया। खराब प्रदर्शन के क्लाज को हटाया गया। वित्तीय पात्रता व दूसरे नियमों में ढील दी गई।

नई दिल्ली में मंगलवार को संसदीय समिति के सामने प्रस्तुतीकरण देने जाते सीबीएसई छात्र सार्थक सिद्धांत (बाएं)। एएनआइ

छात्रों को ग्रेस मार्क्स दें या जल्दी पुनर्मूल्यांकन कराएं : संसदीय समिति

मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए सीबीएसई अधिकारियों ने इस दौरान जहां गड़बड़ियों को सही किए जाने का दावा दिया, वहीं पुनर्मूल्यांकन के शुरू होने की जानकारी दी। समिति के सदस्य हालांकि उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने छात्रों के हितों के मद्देनजर नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स देने या फिर पुनर्मूल्यांकन के काम को तेजी से कराने का सुझाव दिया। समिति का कहना है कि इससे छात्रों को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। समिति ने इस दौरान सीबीएसई से ओएसएम को बगैर ट्रायल और ट्रेनिंग के शुरू किए जाने पर पूछा कि ऐसी क्या जल्द थी, उसे टेंडर देने के डेढ़ महीने के भीतर लागू भी कर दिया। पहले ट्रायल क्यों नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई अधिकारियों ने इस दौरान अधिकांश सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ वह सवालों को सुनते और नोट करते दिखे। समिति ने टेंडर प्रक्रिया से की गई छेड़छाड़ पर भी सवाल किए गए। इस पर सीबीएसई ने लिखित में जवाब देने का आश्वासन दिया। इस दौरान समिति ने शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई अधिकारियों से कहा कि इन गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

पीएम मोदी से जुड़ी टिप्पणियों पर दिग्विजय को घेरा

समिति से जुड़े सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को पीएम मोदी से जुड़ी टिप्पणियों पर घेरा और कहा कि जब सोमवार को बैठक में पीएम से जुड़ा कोई मुद्दा उठा ही नहीं, तो फिर कैसे उन्होंने मीडिया को यह बयान दिया कि नीट-यूजी पुनर्परीक्षा में अब कोई गड़बड़ी हुई तो पीएम जिम्मेदार होंगे। समिति से जुड़े सदस्यों ने कहा कि वैसे भी समिति की बैठक को सार्वजनिक करना नियमों का उल्लंघन है।

सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को हटाना मामला दबाने की कवायद: राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार द्वारा आन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) विवाद के बाद सीबीएसई के दो शीर्ष अधिकारियों- चेयरमैन और सचिव को हटाए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे कवर-अप यानी मामले को दबाने की कवायद बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हटाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचा लिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और तुरंत एक स्वतंत्र न्यायिक जांच का आदेश दिया जाए।

राहुल गांधी।

राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में शामिल 18.5 लाख छात्रों की परवाह की होती तो प्रधान को पहले ही हटा दिया गया होता।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'सीबीएसई चेयरमैन – हटाए गए। सीबीएसई सचिव – हटाए गए। एक सदस्यीय जांच समिति गठित। और असली दोषी धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटाया गया। मंत्री को बचाया गया। यह जवाबदेही नहीं है। यह कवर-अप है।' उन्होंने कहा- 'हमारी मांग आज भी वही है यानी शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें और एक स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएं।'

एनटीए के री-एग्जामिनेशन पोर्टल में 'सेंध' लगाने का दावा

रीतिका मिश्रा • जागरण

- दुबई के साइबर सुरक्षा शोधकर्ता का पोर्टल में गंभीर सुरक्षा खामी का पता लगाने का दावा
- सुपरएडमिन डैशबोर्ड तक पहुंच, डाटा एक्सपोर्ट और स्टाप प्रबंधन से जुड़े फीचर खुले मिले, परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी सामने आई

नई दिल्ली: सीबीएसई की आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को लेकर उठे साइबर सुरक्षा संबंधी सवालों के बीच अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के री-एग्जामिनेशन पोर्टल में भी तकनीकी खामियां देखने को मिली हैं।

दुबई के साइबर सुरक्षा शोधकर्ता रायलन अनिल ने दावा किया है कि उन्होंने एनटीए के आधिकारिक री-एग्जामिनेशन पोर्टल में एक गंभीर सुरक्षा खामी का पता लगाया, जिसके जरिये उन्होंने सुपरएडमिन लागिन को बाईपास कर डैशबोर्ड तक पहुंच प्राप्त की। रायलन ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पोर्टल में बेहद कमजोर क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सुपरएडमिन एक्सेस हासिल करना संभव हुआ। क्रेडेंशियल्स का अर्थ लागिन आइडी (यूजरनेम) और पासवर्ड होता है। इनका उपयोग करके आप किसी वेबसाइट, ऐप या सिस्टम में सुरक्षित रूप से लागिन करते हैं।

रायलन ने इस एक्सेस के स्क्रीनशाट भी साझा किए। इस खामी के कारण करीब 7,900 आब्जर्वर, 676 सिटी को-आर्डिनेटर और 5,400 सेंटर सुपरिंटेंडेंट व परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी तक पहुंच मिली। इसमें नाम, ई-मेल पते, मोबाइल नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां शामिल हैं। साइबर सुरक्षा की भाषा में इस प्रकार की जानकारी को व्यक्तिगत पहचान योग्य सूचना (पीआइआइ) माना जाता है, जिसका दुरुपयोग फिशिंग, धोखाधड़ी या अन्य साइबर अपराधों में किया जा सकता है।

संवेदनशील डाटा की सुरक्षा से जुड़ा है मामला

शोधकर्ता छात्र ने दावा किया कि सुपरएडमिन डैशबोर्ड में केवल डाटा देखने की सुविधा ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक विकल्प भी उपलब्ध थे। इनमें आब्जर्वरों और अन्य कर्मियों का प्रबंधन, नियुक्ति पत्र तैयार करना और डाउनलोड करना, विभिन्न टैम्पलेट अपलोड करना व नोडल अधिकारियों की मैपिंग जैसे फीचर शामिल थे। यह केवल एक तकनीकी खामी नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में संवेदनशील डाटा की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति को ऐसी पहुंच मिल जाए तो परीक्षा प्रबंधन प्रणाली की गोपनीयता और अखंडता पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय से तत्काल यह स्पष्ट करने की अपील की कि इतनी गंभीर खामी सिस्टम में कैसे मौजूद रही।

नीट विवाद पर शशि थरूर बोले, 'पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात'

- कहा- परीक्षाओं की शुचिता खत्म हो जाए तो मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में आ रही गड़बड़ियों, विशेषकर नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में बार-बार हो रही खामियों को देश की 'पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात' करार दिया। उन्होंने कहा कि जब परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता ही खत्म हो जाए, तो कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बार-बार परीक्षा रद होने से पूरी प्रक्रिया दूषित हो चुकी है।

शशि थरूर। फाइल

परीक्षा प्रणाली की साख पर उठे सवाल : उन्होंने वैश्विक स्तर का उदाहरण देते हुए पूछा कि जब दुनिया भर में सैट (स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट) या कैंब्रिज जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्षता से हो सकती हैं, तो भारत सरकार एक राष्ट्रीय परीक्षा को भी पूरी ईमानदारी से आयोजित करने में अक्षम क्यों साबित हो रही है?

थरूर ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की कि यह लापरवाही आगे होनी चाहिए। गौरतलब है कि नीट-यूजी 2026 परीक्षा अब पेपर लीक के आरोपों के बाद 21 जून के लिए पुनर्निर्धारित की गई है और सीबीआइ इसकी जांच कर रही है।

साइबर हमलों के बीच शुरू हुई सीबीएसई की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पोर्टल को बाधित करने के लिए दो मिनट में 15 लाख हिट भेजे गए

सीबीएसई की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों के सत्यापन के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार तड़के चार बजे से शुरू हो गई। बोर्ड के अनुसार, पोर्टल एक समय में आठ हजार से अधिक उपयोगकर्ताओं को संभाल रहा है। हालांकि, इस बीच दिनभर पोर्टल को निशाना बनाकर साइबर हमलों की भी कोशिश की गई। इसमें पोर्टल को बाधित करने के लिए दो मिनट के भीतर 15 लाख हिट भेजे गए, जबकि एक लाख से अधिक बार अनधिकृत फाइलों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद दोपहर तीन बजे तक 16 हजार से अधिक विद्यार्थी सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके थे। इसके बाद की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस दौरान कई विद्यार्थियों ने लागिन और तकनीकी दिक्कतों की भी शिकायत की।

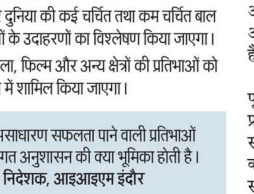

फाइल

बोर्ड के मुताबिक, सुरक्षा तंत्र सक्रिय है और आवेदन प्रक्रिया जारी रखी गई है। तकनीकी टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया गया है। विद्यार्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर पोर्टल में कई बदलाव भी किए गए हैं। पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि छह जून मध्यरात्रि तक निर्धारित की गई है।

तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की : क्रिया शुरू होते ही कई विद्यार्थियों ने पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों की शिकायत भी की। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर आवेदन करने के दौरान के स्क्रीनशाट साझा करते हुए लागिन में परेशानी, आर्थेटिकेशन फेल होने और धीमी गति से पेज खुलने जैसी तकनीकी दिक्कतों की बात कही।

चार लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया आवेदन : बोर्ड ने बताया कि चार लाख से अधिक विद्यार्थियों ने 11 लाख से अधिक मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों (कापी) के लिए आवेदन किया था। इन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका में त्रुटियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर आइआइटी मद्रास और आइआइटी कानपुर के विशेषज्ञ ओएसएम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में सामने आई तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायता कर रहे हैं।

डिजिलाकर के लागिन सुरक्षा तंत्र पर भी उठे सवाल

रायलन अनिल ने सीबीएसई के डिजिलाकर पोर्टल की लागिन सुरक्षा व्यवस्था में भी कमजोरी होने का दावा किया है। उनके अनुसार पोर्टल में लागिन के समय डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एईएस (एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड) एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लिए उपयोग होने वाला पासवर्ड (पासफ्रेज) वेबसाइट के कोड में ही लिखा हुआ है। एन्क्रिप्शन वह तकनीकी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पठनीय जानकारी (प्लेनटेक्स्ट) को गणितीय एल्गोरिदम और एक डिजिटल-की (चाबी) की मदद से ऐसे गुप्त कोड (साइफरटेक्स्ट) में बदल दिया जाता है, जिसे केवल वही पढ़ सकता है जिसके पास सही चाबी हो। शोधकर्ता का कहना है कि एन्क्रिप्शन से जुड़ा पूरा लाजिक एक सार्वजनिक जावास्क्रिप्ट फाइल में मौजूद है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ऐसे में एन्क्रिप्शन सुरक्षा की प्रभावी परत नहीं रह जाती क्योंकि एन्क्रिप्शन कुंजी और प्रक्रिया दोनों सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती हैं। वेबसाइट का यह कोड सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है। यानी जिस ताले से डाटा को सुरक्षित किया जा रहा है, उसकी चाबी भी उसी के साथ रखी हुई है। ऐसे में कोई तकनीकी जानकारी रखने वाला व्यक्ति यह समझ सकता है कि डाटा को सुरक्षित करने की प्रक्रिया कैसे काम कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि एन्क्रिप्शन की कुंजी और उसे इस्तेमाल करने का तरीका दोनों सार्वजनिक हो जाएं, तो साइबर हमलावरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को समझना और उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करना आसान हो सकता है। इससे उपयोगकर्ताओं के लागिन डाटा और अन्य संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा प्रभावित होने का जोखिम बढ़ जाता है। मामले में एनटीए व सीबीएसई की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

अपर निजी सचिव परीक्षा में कोई सफल नहीं, सभी 331 पद रह गए रिक्त

राज्य ब्यूरो, जागरण • प्रयागराज

- हिंदी आशुलेखन की 80 शब्द प्रति मिनट की त्रुटिरहित गति नहीं पा सका कोई उम्मीदवार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीएपीएससी) की अपर निजी सचिव (एपीएस) परीक्षा-2023 के परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया। 331 पदों के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में ऐसा परिणाम सामने आया कि एक भी अभ्यर्थी अंतिम यानी तृतीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र नहीं मिला। हिंदी आशुलेखन में कोई भी अभ्यर्थी 80 शब्द की त्रुटि रहित गति नहीं पा सका। इसके चलते सभी 331 पदों को आयोग ने अगली भर्ती के लिए बढ़ा दिया।

एपीएस परीक्षा-2023 के तहत 331 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रथम चरण की परीक्षा सात जनवरी 2024 को हुई थी, जिसका परिणाम चार मार्च 2024 को घोषित किया गया। इस परीक्षा में 5889 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए सफल घोषित किया गया था। द्वितीय चरण की परीक्षा 28 जून से 18 जुलाई 2024 के बीच लखनऊ में दो सत्रों में आयोजित की गई, जिसमें 4240 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। द्वितीय चरण में हिंदी आशुलेखन (शार्टहैंड) और हिंदी टंकण (टाइपिंग) की परीक्षा शामिल थी। इसका पूर्णांक क्रमशः 75 और 25 अंक था। नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की त्रुटिरहित गति हासिल करना अनिवार्य था।

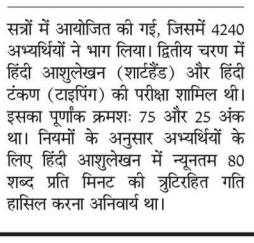

फाइल फोटो

सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार परीक्षा में शामिल कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित मानक के अनुसार हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की त्रुटिरहित गति प्रदर्शित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप किसी भी अभ्यर्थी को तृतीय चरण की परीक्षा के लिए सफल घोषित नहीं किया गया। ऐसे में जिस परिणाम का अभ्यर्थी तीन वर्ष से इंतजार कर रहे थे, वह मंगलवार को घोषित किया गया तो उन्हें तगड़ा झटका लगा है।

जल्द जारी होंगे अंक : आयोग ने यह भी बताया है कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व अन्य विवरण शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। यूपीएपीएससी की इस भर्ती परीक्षा का परिणाम हाल के वर्षों में सबसे असामान्य परिणामों में गिना जा रहा है, जहां हजारों उम्मीदवारों की मेहनत के बावजूद एक भी चयनित उम्मीदवार अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सका और सभी पद खाली रह गए।

ओडिशा में दिव्यांग श्रमिक की हिरासत में पिटाई के बाद मौत

जागरण संवाददाता, अनुगुल: ओडिशा के गंजाम जिले में दिव्यांग दिहाड़ी श्रमिक 32 वर्षीय सुशांत साहू की पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद मौत हो गई। सुशांत के परिवार के लोगों ने पुलिस पर थर्ड डिग्री टार्चर व गंभीर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सुशांत की पत्नी ममाजिनी प्रधान ने कहा कि पुलिस ने पति के साथ क्रूरता की हदें पार करते हुए मारपीट की और शरीर पर गर्म पानी डालकर तथा घावों पर मिर्ची लगाकर जानवरों की तरह प्रताड़ित किया।

ममाजिनी ने बताया कि 25 मई को पुलिस उनके पति और एक अन्य व्यक्ति ईश्वर साहू को एक पत्थर खदान से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी। दोनों को छह दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। 31 मई को पुलिस ने सुशांत को गंभीर हालत में घर भेज दिया। उसे अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में कबिसूर्यनगर थाना प्रभारी को पद से हटाकर जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया।

खुद को श्रीकृष्ण का अवतार बता युवतियों से गंधर्व विवाह रचाता था कथित बाबा अभिषेक

जागरण संवाददाता, मथुरा

24 युवतियों से संपर्क के मिले साक्ष्य, गोवर्धन के राधाकुंड आश्रम में रहती थी युवतियां

धार्मिक प्रवचनों की आड में युवतियों का शोषण करने वाला कथित बाबा अभिषेक मिश्रा खुद को श्रीकृष्ण का अवतार बताता था। वह युवतियों से गंधर्व विवाह करने का ढोंग करता था। युवतियों को नशे की आदत डलवाकर उनका शारीरिक शोषण करता और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। उसे गोवर्धन के राधाकुंड में आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उसके संपर्क में रहने वाली 24 युवतियों के बारे में जानकारी मिली हैं। इनमें से अधिकांश इंजीनियर हैं और आकर्षक पैकेज पर नौकरी करती हैं। कई घंटे की पूछताछ के बाद मंगलवार को पुलिस ने अभिषेक को जेल भेज दिया है। आइआइटी रुड़की से बीटेक करने के बाद कथित बाबा बने अभिषेक ने तीन साल पहले ओडिशा से आकर यहां आश्रम बनाया था।

15 मई को एक युवती ने एसएसपी से छोटी बहन के साथ अश्लील हरकतें करके ब्लैकमेल करने की शिकायत की थी। जांच के बाद सोमवार को पुलिस ने अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। आश्रम में छत्तीसगढ़ की दो युवतियां और एक युवक भी मिला। तीनों नशे के आदी थे। पुलिस ने उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दिया। अभिषेक के मोबाइल से पुलिस को कई युवतियों की तस्वीरें और वीडियो भी मिले। पुलिस की पूछताछ में उसने कई राज उगले।

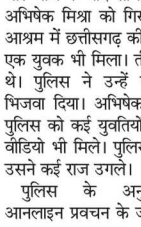

अभिषेक मिश्रा।

नशे की आदत डलवाकर करता था दुष्कर्म, रुड़की आइआइटी से कर चुका है बीटेक

पुलिस के अनुसार अभिषेक आनलाइन प्रवचन के जरिये युवतियों का ब्रेनवाश करता था। इसके बाद उन्हें आश्रम बुलाता था। खुद को श्रीकृष्ण का अवतार बताकर उन्हें अध्यात्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता था। उनसे गंधर्व विवाह करता। आश्रम में अलग-अलग समय में दर्जन भर से ज्यादा युवतियां रहती थीं। कई युवतियां किराये के कमरों में भी रहती थी। वे नियमित आश्रम आती-जाती थीं। कथित बाबा आश्रम में रहने वाली युवतियों को गांजे का नशा करवाता था। पूरी तरह चंगुल में फंसाने के बाद उनका शारीरिक शोषण करता था। इसी दौरान उनके वीडियो भी बना लेता था।

एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि छह माह पूर्व अभिषेक के आश्रम में रहने वाली मध्य प्रदेश की युवती को लेने उसके स्वजन पहुंचे थे। विरोध करते हुए आश्रम में रहने वाली युवतियों ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया था। अभिषेक मिश्रा के मोबाइल और इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। पीड़ित युवतियों से भी संपर्क किया जा रहा है।

सफलता का विज्ञान

कुछ प्रतिभाएं शिखर पर कैसे टिकती हैं और कुछ क्यों बिखर जाती हैं, जीन, परिवार, माहौल और अनुशासन की भूमिका की होगी पड़ताल

वैभव सूर्यवंशी की कामयाबी का गणित समझेगा आइआइएम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

खेल, कला, फिल्म और अन्य क्षेत्रों में कम उम्र में प्रतिभाओं की असाधारण सफलता के पीछे कौन से कारक काम करते हैं और उनमें से कई प्रतिभाएं लंबे समय तक शिखर पर कैसे बनी रहती हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), इंदौर विशेष अध्ययन करेगा। हाल में आइपीएल में अपने प्रदर्शन से चर्चा में आए युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी इस शोध का हिस्सा होंगे।

शोध अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि किसी बाल प्रतिभा को असाधारण बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है। क्या सफलता का आधार जन्मजात क्षमता और जीन होते हैं, या परिवार, स्कूल, प्रशिक्षक और सामाजिक वातावरण उसे आगे बढ़ाते हैं? शोधकर्ता यह भी परखेंगे कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और अभ्यास का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। अध्ययन में उन उदाहरणों की भी तुलना की जाएगी, जिनमें कुछ बाल प्रतिभाएं शुरुआती सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने में सफल रहीं, जबकि कुछ अपेक्षित ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकीं। शोधकर्ताओं का प्रयास यह समझने का होगा कि सफलता को टिकाऊ बनाने वाले कारक कौन से हैं और किन परिस्थितियों में प्रतिभाएं अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं।

शोध का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष कम उम्र में मिलने वाली प्रसिद्धि और उसके मानसिक प्रभावों पर केंद्रित होगा। इंटरनेट मीडिया के दौर में अचानक मिलने वाली लोकप्रियता, लोगों की बढ़ती अपेक्षाएं, लगातार बेहतर प्रदर्शन का दबाव और असफलता का डर युवाओं के व्यक्तित्व और करियर को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका भी विश्लेषण किया जाएगा।

शोध में उपलब्धियों के साथ-साथ उस पूरी यात्रा का अध्ययन होगा, जिसने किसी प्रतिभा को असाधारण बनाया। परिवार का सहयोग, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन, संसाधनों की उपलब्धता, व्यक्तिगत समर्पण और संघर्ष जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। आइआइएम का मानना है कि यह अध्ययन केवल किसी खिलाड़ी या कलाकार की सफलता का विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि इससे ऐसे व्यावहारिक निष्कर्ष सामने आ सकते हैं, जो भविष्य की उभरती प्रतिभाओं के संतुलित और दीर्घकालिक विकास में मददगार साबित हों।

वैभव सूर्यवंशी - फाइल फोटो

ये रहेगी प्रक्रिया

- पहले चरण में शोध प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
- इसके बाद लगभग तीन माह में अध्ययन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- देश और दुनिया की कई चर्चित तथा कम चर्चित बाल प्रतिभाओं के उदाहरणों का विश्लेषण किया जाएगा।
- खेल, कला, फिल्म और अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अध्ययन में शामिल किया जाएगा।

अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि कम उम्र में असाधारण सफलता पाने वाली प्रतिभाओं के विकास में परिवार, प्रशिक्षक, माहौल और व्यक्तिगत अनुशासन की क्या भूमिका होती है। इससे उपयोगी मार्गदर्शन मिल सकेगा। - प्रो. हिमांशु राय, निदेशक, आइआइएम इंदौर

ट्रैफिक चालान से खोज निकाला 24 वर्ष से फरार 50 हजार का इनामी

जागरण संवाददाता, आगरा

- आगरा में 2002 में पौने दो लाख रुपये की लूट के बाद फरार हुआ था सैमुअल, पकड़े गए थे दो साथी

पौने दो लाख रुपये की लूट करके फरार हुआ लुटेरा 24 साल से दिल्ली में पहचान बदलकर छुपा था। 10 साल से दिल्ली के नांगलोई में रह रहे लुटेरे सैमुअल उर्फ अमित उर्फ सहदेव यादव को दबोच लिया गया। वह एक स्कूल में निशानेबाजी का कोच था। 50 हजार के इनामी लुटेरे की छह माह पहले नए सिरे से तलाश शुरू हुई। दिल्ली में हुए ट्रैफिक चालान से मिले सुराग को खोजते हुए आगरा पुलिस आरोपित तक पहुंच गई।

शहर निवासी सैमुअल ने दो साथियों के साथ चार नवंबर 2002 में आगरा में युवक से 1.72 लाख रुपये लूटे थे। आठ नवंबर 2002 को एक आरोपित दीपक शाही को गिरफ्तार कर लिया। उसके जरिये अमित उर्फ मोनू और सैमुअल के नाम सामने आए। 17 नवंबर 2006 को अमित उर्फ मोनू भी पकड़ा गया। सैमुअल पर 2018 में 25 हजार रुपये और 2026 में 50 हजार का इनामी घोषित किया गया। बड़ा इनाम राशि वाले फरार अपराधियों के लिए जनवरी 2026 में अभियान शुरू किया था। तब 24 वर्ष से फरार सैमुअल रडार पर आया।

सैमुअल 24 वर्ष पहले।

सैमुअल उर्फ सहदेव यादव अब।

Loot Blink
SABSE BADI DEALS, SABSE BADA FAAYDA!
JOIN INDIA'S MOST TRUSTED
DEALS CHANNEL
SAVE MORE SPEND LESS!
100% REAL DEALS
LIMITED TIME OFFERS
BEST PRICES GUARANTEED
SAB PE BADI BACHAT!
UP TO 90% DISCOUNT DEALS
BIGGEST DISCOUNTS • BEST BRANDS • LIMITED STOCK
LIMITED STOCK
JOIN KARO AUR PAO SABSE BADI LOOT DEALS!
boat Airdopes 141 TWS Earbuds ₹2,990 ₹249 92% OFF YOU SAVE ₹2,741
Noise Pulse 2 Smart Watch ₹4,999 ₹349 93% OFF YOU SAVE ₹4,650
iPhone 13 128GB ₹59,900 ₹5,399 91% OFF YOU SAVE ₹54,501
SAMSUNG 32" HD Smart TV 89% OFF YOU SAVE ₹25,800
realme Narzo N55 (6GB+128GB) ₹13,999 ₹799 94% OFF YOU SAVE ₹13,200
ASUS Vivobook 15 (i3 12th Gen, 8GB/512GB SSD) 90% OFF YOU SAVE ₹40,491
GREEN SOUL Office Chair Ergonomic ₹14,999 ₹1,499 92% OFF YOU SAVE ₹17,500
SAMSUNG 980 500GB NVMe SSD ₹6,999 91% OFF YOU SAVE ₹6,400
WILDCRAFT Backpack ₹1,999 ₹149 93% OFF YOU SAVE ₹1,850
PHILIPS Trimmer Series 3000 ₹1,995 ₹199 90% OFF YOU SAVE ₹1,796
AGARO Air Fryer 4.5L ₹6,999 ₹699 90% OFF YOU SAVE ₹6,300
PUMA Men's Running Shoes ₹3,999 91% OFF YOU SAVE ₹3,650
ZEBRONICS Study Headphones with Mic ₹1,499 ₹169 89% OFF YOU SAVE ₹1,330
PORTABLE Laptop Table Foldable ₹1,299 ₹129 90% OFF YOU SAVE ₹1,170
boAt Stone 650 Bluetooth Speaker ₹3,999 ₹199 95% OFF YOU SAVE ₹3,800
UPTO 90% OFF ON TOP BRANDS
PRICE DROP ALERTS BE THE FIRST TO KNOW
100% GENUINE PRODUCTS
FAST DELIVERY ACROSS INDIA
DEALS ITNI BADI, KI CHOOK GAYE TO PACHTAOGE!
ABHI JOIN KARO AUR LOOTNA SHURU KARO!
JOIN OUR WHATSAPP CHANNEL
Instant Deal Alerts
Exclusive Offers
Limited Stock Updates
CLICK HERE
JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL
Latest Deals & Offers
Price Drops Alerts
Limited Time Offers
CLICK HERE
SAVE TIME SHOP SMART
SAVE MONEY LIVE BETTER
SMART CHOICES. BRIGHTER FUTURE!
SHOP SMART. SAVE BIG. SHINE BRIGHT.
JOIN 1 LAKH+ SMART SHOPPERS & SAVE THOUSANDS EVERY MONTH!

20.8 किग्रा का ट्यूमर 59 वर्षीय एक मरीज के पेट से एम्स जोधपुर के चिकित्सकों ने साढ़े आठ घंटे चले बेहद जटिल और उच्च जोखिम वाले आपरेशन के बाद निकाला। इसे राजस्थान में निकाला गया सबसे बड़ा ट्यूमर बताया जा रहा है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 03 जून, 2026

नौकरी का लालच, अश्लील बातें और अंत में खूबसूरत एजेंट मांग रही खुफिया जानकारी

ओवरग्राउंड नेटवर्क तबाह होने से इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हुई पाक की खुफिया एजेंसी

भारतीय सेना की जानकारी लेने के लिए किया जा रहा कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल, ट्रैप में फंस चुके कई लड़के

नवीन नवाज • जागरण

श्रीनगर: 'हेलो-आइ एम सायमा, आइ लव कश्मीर एंड कश्मीरी'। आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप घर बैठे महीने के हजारों रुपये कमा सकते हैं, आपको केवल अपने क्षेत्र की खूबसूरत और महत्वपूर्ण जगहों की तस्वीरें और उनका विवरण देना है, जिसे हम अपनी टूर एंड ट्रैवल कंपनी के ब्राउशर में इस्तेमाल करेंगे। यह कुछ संदेश हैं, जो फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, एक्स जैसे इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग माध्यमों पर स्थानीय युवाओं को प्राप्त हो रहे हैं। यह लुभाने वाले प्रस्ताव पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और आतंकी संगठनों का हनीट्रैप है। जम्मू-कश्मीर के कई युवा इस ट्रैप में फंस चुके हैं। पिछले एक माह में ही जम्मू संभाग में तीन मामले सामने आ चुके हैं।

प्रतीकात्मक

केस स्टडी-1: धमकियों के बावजूद नहीं माना डोडा का युवक

डोडा जिले का एक युवक फेसबुक पर उजमा नामक एक युवती के संपर्क में आया। उजमा वास्तव में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ की एजेंट थी। उसने खुद को एक छात्रा बताया। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच दोनों के बीच 200 से अधिक वीडियो काल हुईं। दोनों के बीच अंतरंग बातें हुईं, तस्वीरें और वीडियो साझा हुए। इसके बाद उक्त युवती ने उसे भारतीय सैन्य ठिकानों और आतंकरोधी अभियानों में शामिल यूनिटों की तस्वीरें साझा करने को कहा। युवक नहीं माना तो उसकी निजी तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी दी गई। पुलिस ने उसे दुश्मन की चंगुल में पूरी तरह फंसने से पहले ही बचा लिया।

केस स्टडी-2: नेटवर्क तैयार करने का टास्क

डोडा का एक अन्य युवक इंटरनेट मीडिया के जरिये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हनीट्रैप में फंसा। उसे नियंत्रण रेखा के साथ सटे राजौरी में जाकर आतंकियों और आइएसआइ के लिए एक स्थानीय नेटवर्क तैयार करने का काम सौंपा गया। उसे आइएसआइ ने छह सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने को कहा था। इस युवकों को भी समय रहते पुलिस ने बचा लिया।

केस स्टडी-3: स्नैपचैट दोस्ती से जासूसी तक

जम्मू के सीमावर्ती मकवाल गांव के 23 वर्षीय युवक कर्ण की इंटरनेट मीडिया पर स्नैपचैट के जरिये एक महिला से दोस्ती हो गई। महिला ने खुद को पंजाब में तैनात सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी बताया। इसके बाद उससे जम्मू क्षेत्र में सेना के बंकरों, रक्षा चौकियों और पुलों की तस्वीरें तथा वीडियो भेजने को कहा। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी देने के बदले उसे 2,000 रुपये भी मिले।

दोस्ती, फिर प्रेम संबंध और बाद में ब्लैकमेलिंग के जरिये भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारियां हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब आइएसआइ और आतंकी संगठन जिस तेजी से इंटरनेट मीडिया के जरिये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह चौंकाने वाला है। आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क लगभग नष्ट हो गया है। दुश्मन अब इंटरनेट मीडिया के जरिये विभिन्न तरीकों से युवाओं को फांस रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की जांच में सामने आया है कि युवाओं को पहले

पूर्व जज गिरिबाला ने दिखाई अकड़, कोर्ट में नाम से बुलाए जाने पर भड़कीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल

- त्विषा शर्मा की मौत मामले में आरोपित मां-बेटे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
- कहा- क्या उनके नाम के आगे श्रीमती या मैडम नहीं लगाया जा सकता, खुद की पैरवी

माडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपित सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह की कोर्ट कक्ष में और जेल पहुंचने पर भी अकड़ बरकरार रही। गिरिबाला सिंह कोर्ट में नाम से बुलाए जाने पर भड़क गईं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद सेंट्रल जेल पहुंचीं तो भीतर तक गाड़ी में बैठकर भीतर ले जाने का दबाव बनाया। हालांकि, नियमों का हवाला देकर जेल अधिकारियों ने उनको इसकी अनुमति नहीं दी तो उन्हें बेटे समर्थ के साथ पैदल ही अंदर जाना पड़ा।

भोपाल में त्विषा के पति समर्थ सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट के बंदी गृह से जेल ले जाते सीबीआइ अधिकारी। -नईदुनिया

भोपाल में सेवानिवृत जज गिरिबाला सिंह को न्यायिक हिरासत के लिए बंदी गृह से जेल ले जाते सीबीआइ आधिकारी। -नईदुनिया

दरअसल, पांच दिन की रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को सीबीआइ ने मृतका त्विषा की सास और पति को भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) शोभना भलावे की कोर्ट में पेश किया। यहां सीधे नाम से बुलाए जाने पर भड़कीं गिरिबाला ने कहा कि क्या उनके नाम के आगे श्रीमती या मैडम नहीं लगाया जा सकता? सुनवाई के दौरान आरोपित के तौर पर खड़ीं गिरिबाला ने अपनी पैरवी स्वयं की। चूंकि सीबीआइ की ओर से कोर्ट से कहा गया कि फिलहाल उन्हें दोनों आरोपितों की रिमांड की आवश्यकता नहीं है। इस पर कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की (16 जून तक के लिए) न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। हालांकि, खतरे की आशंका को देखते हुए कोर्ट ने दोनों को सेंट्रल जेल में अन्य कैदियों से अलग रखने का आदेश भी दिया।

गिरिबाला ने वकील पर लगाया मारपीट का आरोप

गिरिबाला ने मृतका त्विषा के स्वजन के वकील अनुराग श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि उन्होंने जबलपुर कोर्ट परिसर में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट की। इस पर वकील अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जबलपुर कोर्ट में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कोर्ट तुरंत फुटेज निकालकर जांच करा सकता है।

तुरंत बंद होना चाहिए मीडिया ट्रायल: कोर्ट में गिरिबाला ने कहा कि केस में मीडिया ट्रायल तुरंत बंद होना चाहिए। हम जहां भी जाते हैं, मीडिया पहले से पहुंच जाती है। इससे उनकी जान को खतरा है।

रंगदारी नहीं देने पर गुरदासपुर में अस्पताल पर ग्रेनेड हमला

- दो बार पहले भी अस्पताल पर की गई थी फायरिंग, ताजा मामले में जांच शुरू

<< धमाके के बाद अस्पताल के दरवाजे के टूटे शीशे। जागरण

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर

गुरदासपुर के कलानौर स्थित मुल्तानी अस्पताल पर मंगलवार दोपहर करीब 2:32 बजे ग्रेनेड हमला किया गया। धमाके से इमरजेंसी वार्ड के फर्श में गड्ढा पड़ गया और अस्पताल के दरवाजे के शीशे टूट गए। ग्रेनेड हमले की सूचना मिलते ही एसएसपी आदित्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। अस्पताल मालिक डा. एसपी सिंह मुल्तानी ने बताया कि उनसे लंबे समय से रंगदारी मांगी जा रही थी और न देने पर इससे पहले भी अस्पताल पर दो बार गोलियां चलाई गई थीं।

डा. मुल्तानी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 2:32 बजे एक युवक अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ और ग्रेनेड फेंक दिया। पूर्व में अस्पताल पर दो बार गोलियां चलाई गई थी। मंगलवार दोपहर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों को छुट्टी देने के बाद वह खाना खाने के लिए घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड से धमाके की आवाज सुनाई दी।

राजस्थान में धूलभरे तूफान व बारिश से हुए हादसों में तीन की मौत

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले तीन दिनों से राज्य के करीब एक दर्जन जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। सीमावर्ती जिलों जैसलमेर एवं बाड़मेर में सोमवार देर रात धूलभरे तूफान और बारिश के कारण हुए अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हुई है। बाड़मेर में दो अलग-अलग गांवों में कच्चे घर की दीवार ढहने से दो मासूमों की मौत हो गई।

वहीं तेज आंधी के दौरान टिन शेड का कमरा ढहने से पिता-पुत्र मलबे में दब गए, जबकि दूसरे घर में बचने के लिए बाहर भाग रही एक महिला के सिर पर लोहे की एंगल गिर गई। वहीं जैसलमेर में तूफान के कारण एक रिसार्ट की कच्ची दीवार गिरने से स्थानीय गायक कलाकार की मौत हो गई। कलाकार अतिथियों के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए वहां पहुंचा था। तूफान का सबसे ज्यादा असर सीमा से लगे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। तेज हवाओं के कारण बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए और टिन शेड उड़ गए।

तीन दिन की देरी से कल केरलम पहुंचेगा मानसून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- उत्तर-पश्चिम भारत को भी गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत
- परिस्थितियां अनुकूल, तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून

सामान्य तिथि से लगभग तीन दिन की देरी से मानसून चार जून को केरलम पहुंच सकता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। केरलम में मासून के पहुंचते ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर मानसून एक जून के आसपास केरलम पहुंचता है। यहीं से देश में चार महीने के वर्षा मौसम की शुरुआत मानी जाती है।

इस बार भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने पहले 26 मई को मानसून आने का अनुमान जताया था, मगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनने के कारण इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई।

अब विभाग का कहना है कि चार जून के आसपास केरलम में मानसून की दस्तक हो सकती है। उत्तर भारत में भी बुधवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है।

मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के लिए भी राहत के संकेत दिए हैं। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में मौसम का रुख बदल सकता है। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं, गरज-चमक एवं छिटपुट बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे भीषण गर्मी और लू की स्थिति में कुछ कमी आने की उम्मीद है।

मानसून की आहट : केरल के कोच्चि में मंगलवार प्री-मानसून की बारिश के बादलों से भरे शाम में एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर। एपी

अगले छह से सात दिनों के दौरान केरलम में कई स्थानों पर सात से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। केरलम के कई जिलों में अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

इस बार 10 प्रतिशत कम बारिश की आशंका

इस बार अलनीनो के कारण पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 10 प्रतिशत तक कम बारिश हो सकती है। आइएमडी के अनुसार, पूरे देश में वर्षा दीर्घकालिक औसत की लगभग 90 प्रतिशत रह सकती है, जो सामान्य से कम श्रेणी की सीमा पर है। अभी प्रशांत महासागर में तटस्थ स्थिति धीरे-धीरे अलनीनो की ओर बढ़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून में इसका प्रभाव कमजोर रहेगा, लेकिन सितंबर तक यह मजबूत रूप ले सकता है। ऐसे में मानसून की शुरुआत भले अच्छी दिखाई दे रही हो, लेकिन पूरे सीजन के प्रदर्शन पर मौसम विज्ञानियों की नजर बनी रहेगी।

पुलिस से बचने को अफीम तस्करों ने उड़ाए नोट, मुठभेड़ में एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : झारखंड के डाल्टनगंज से मादक पदार्थ (अफीम) लेकर पंजाब जा रहे तस्करों को रविवार रात पुलिस ने घेर लिया। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अफीम तस्करों ने खूब नोट उड़ाए। पुलिस के वाहनों में टक्कर भी मारी। इसमें एसओजी प्रभारी की कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन पुलिस ने हार न मानी। मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली लगी। वह घायल होकर गिर पड़ा। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल तस्कर लुधियाना का रहने वाला प्रिंस है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।

मुठभेड़ के दौरान फरार दूसरे आरोपित की भी पहचान कर ली गई है। अब तक की जांच में उसका आपराधिक रिकार्ड नहीं मिला है। पुलिस सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन पता कर रही है। पुलिस के अनुसार ध्यान भटकाने के लिए तस्करों ने नोट उड़ाए थे। भागने के प्रयास में तस्करों ने कई बार पुलिस के वाहनों को टक्कर भी मारी। लेकिन पुलिस दूसरे की कार लेकर तस्करों का पीछा जारी रखा था।

बीएसआइपी ने मुंगेर में खोजा दुनिया का सबसे पुराना वट वृक्ष

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- विज्ञानियों के अनुसार 700 वर्ष पुराना है यह बरगद का पेड़, विज्ञानी डा. त्रिना बोस ने कार्बन डेटिंग से सिद्ध की उम्र

बिहार के मुंगेर में दुनिया का सबसे पुराना वट वृक्ष मिला है। इसकी उम्र 700 वर्ष आंकी गई है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बीएसआइपी), लखनऊ की विज्ञानी डा. त्रिना बोस और उनके शोध छात्र अवनीश मिश्रा ने रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से यह सिद्ध किया है।

मुंगेर में बड़ा बंगला परिसर में यह वृक्ष लगा है। बीएसआइपी की विज्ञानी डा. त्रिना ने बताया कि बड़ा बंगला स्थापत्य शैली से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत व मुगल काल के अंतिम समय का बना प्रतीत होता है। यानी यह लगभग 350 वर्ष पुराना होगा।

उन्होंने बताया कि परिसर में लगा बरगद बड़ा बंगला की उम्र का दोगुना यानी 700 वर्ष का है। यह वृक्ष उस समय के प्राकृतिक वन का बचा हुआ प्रमाण हो सकता है।

इस शोधपत्र के सह-लेखक एवं बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के विज्ञानी डा. मयंक शेखर ने बताया कि

बिहार के मुंगेर में बरगद के इस पेड़ की 700 वर्ष आंकी गई है - बीएसआइपी

बिहार के विभिन्न जिलों में अनेक प्राचीन एवं विरासत महत्व के वृक्ष मौजूद हो सकते हैं, जिनकी वैज्ञानिक उम्र निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग आवश्यक है। ऐसे वृक्षों की सटीक उम्र पता होने से न केवल उनके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को वैज्ञानिक आधार मिलेगा। यहां पर्यटन भी बढ़ेगा।

केरलम में ड्रग्स के खिलाफ शुरू हुआ आपरेशन तूफान

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र: केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने मंगलवार को गृह विभाग की नशा विरोधी पहल आपरेशन तूफान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का सेवन राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी युवाओं की है और ड्रग माफिया सक्रिय रूप से उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं पर नशीले पदार्थों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो पहले से कहीं अधिक क्रूर और बर्बर हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों के प्रभाव में आकर कई युवा अपने माता-पिता या परिवार के अन्य करीबी सदस्यों की हत्या तक कर दी है। उन्होंने कहा कि इस पहल में न केवल गृह विभाग बल्कि आबकारी और शिक्षा विभाग के साथ-साथ स्कूलों और अभिभावकों की भी भागीदारी आवश्यक है, ताकि नशीले पदार्थों का उन्मूलन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने छात्रों से इस अभियान के राजदूत बनने का आग्रह किया।

तीन समलैंगिक युवकों ने की दोस्त की हत्या, बोले- ब्लैकमेल करता था

जागरण संवाददाता, रामपुर

- रामपुर में 26 मई को वारदात के बाद सोने की चेन व अंगूठी भी लूटकर ले गए थे आरोपित
- तीनों आरोपित गिरफ्तार, कहा- अश्लील वीडियो बनाकर वसूलता था रुपये

यूपी के रामपुर में समलैंगिक संबंधों को उजागर करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने पर तीन दोस्तों मोहसिन, दानिश और कासिम ने साथी नईम को मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार को पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपितों ने 26 मई का गुनाह कबूल किया। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। उनका कहना है कि नईम भी समलैंगिक था। उसने धोखे से तीनों का अश्लील वीडियो बना लिया था। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डालने की धमकी देकर वह कई बार रुपये वसूल चुका था। वारदात को लूटपाट दर्शाने और रकम की भरपाई के लिए आरोपित हत्या के बाद उसकी सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल फोन व करीब 92 हजार रुपये भी ले गए।

थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि स्वजन ने नईम के दोस्त व मुरादाबाद निवासी अफसर पर शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 26 मई सुबह 10 बजे एक फोन आने पर नईम अपने पिता को दुकान पर बैठाकर बाइक से कहीं चला

रामपुर पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपित। जागरण

गया। घर से डेढ़ किमी दूर नईम का एक प्लाट था। वह दोस्तों-परिचितों के साथ अक्सर वहीं बैठता था। उसकी तलाश में पिता प्लाट पर पहुंचे तो कमरे में ही नईम का शव पड़ा मिला। नईम के मोबाइल फोन की काल डिटेल और लोकेशन ट्रेस के जरिये हकीकत कुछ और निकली। सोमवार रात तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।

दो लाख के बीमा भुगतान में 77 हजार रिश्वत ले रहे बैंक मैनेजर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण • रांची: सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने झारखंड के गोड्डा में एसबीआइ की डुमरिया शाखा के मैनेजर रोहित कुमार सिंह को 77 हजार रुपये रिश्वत लेते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मैनेजर पर जीवन बीमा दावे के दो लाख रुपये का भुगतान करने के एवज में बीमित वृद्धा (दिवंगत) के बेटे से 77 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है।

सीबीआइ ने आरोपित की गिरफ्तारी के बाद उसके कार्यालय व आवासीय परिसर की भी तलाशी ली। बैंक मैनेजर के घर से दो लाख रुपये नकद तथा निवेश से संबंधित संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। मैनेजर को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआइ ने उसे धनबाद स्थित विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शिकायतकर्ता ने 31 मई को सीबीआइ से शिकायत की थी कि उनकी मां का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये का बीमा था। मां के निधन के बाद बीमा राशि के दावे को निष्पादित करने के एवज में बैंक मैनेजर ने 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

इतिहास

राखीगढ़ी की खोदाई में महिला कंकाल की कमर पर मिले करीब एक हजार मनकों के अवशेष, शंख की चूड़ियों और सोने के मनकों ने खोले प्राचीन श्रृंगार संस्कृति के नए रहस्य

सोने के मनकों वाली तगड़ी पहनती थीं हड़प्पाकालीन महिलाएं

सुनील मान • जागरण

हांसी: विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पाकालीन बस्तियों में शुमार हरियाणा स्थित राखीगढ़ी की हाल ही में हुई खोदाई ने हजारों वर्ष पुरानी महिलाओं के श्रृंगार और सामाजिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर किया है। टीला-7 पर मिले एक महिला के कंकाल की कमर के पास करीब एक हजार अगेट (कीमती पत्थर) मनकों के अवशेष मिले हैं, जिन्हें पुरातत्वविद तगड़ी का हिस्सा मान रहे हैं। इसके साथ ही हाथों में शंख की चूड़ियां और आसपास मिले सोने के मनके संकेत देते हैं कि हड़प्पाकालीन महिलाएं भी आभूषणों और विशेष श्रृंगार की शौकीन थीं।

इस बार राखीगढ़ी में सात कंकाल मिले हैं, जिनमें तीन महिलाओं और चार पुरुषों के अवशेष शामिल हैं। इनमें महिला कंकालों से प्राप्त साक्ष्य विशेष महत्व रखते हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार पहली बार किसी महिला कंकाल की कमर पर तगड़ी जैसे आभूषण के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। यह खोज न केवल उस समय की सौंदर्यबोध और सामाजिक परंपराओं को उजागर करती है, बल्कि वर्तमान हरियाणा और उत्तर भारत में प्रचलित तगड़ी पहनने की परंपरा से भी सांस्कृतिक निरंतरता का संकेत देती है।

अब इन कंकालों को सुरक्षित निकालकर कोलकाता स्थित एंथ्रोपोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सनौली से विशेषज्ञ ताहिर हुसैन को बुलाया गया है। वह पहले भी कई प्राचीन कंकालों को सुरक्षित निकालने का कार्य कर चुके हैं। कंकालों के अध्ययन से यह पता लगाने का प्रयास होगा कि उस समय लोगों की मृत्यु किन कारणों से होती थी, उनका खानपान कैसा था, वे किस प्रकार का जीवन जीते थे और उनकी शारीरिक संरचना कैसी थी।

एंथ्रोपोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया की अधिकारी डा. नंदनी भट्टाचार्य भी इस अध्ययन की निगरानी कर रही हैं। वहीं, एक कंकाल का डीएनए नमूना पहले ही डा. नीरज राय की टीम द्वारा लिया जा चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार, कंकालों को निकालने की प्रक्रिया बेहद धीमी और सावधानीपूर्ण होती है, जिसमें पीओपी, रसायनों और जूट की बोरियों की सहायता से अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। एक कंकाल को पूरी तरह सुरक्षित निकालने में लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद मनोज सक्सेना के अनुसार सभी कंकालों को सुरक्षित निकालकर शोध के लिए कोलकाता भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राखी के टीलों पर पाए गए महिला के कंकाल। जागरण

बिहार नहीं लौटे 50 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी, वोट डालने गए थे बंगाल

जागरण संवाददाता, दरभंगा

- दरभंगा का मामला, वास्तविक पहचान को लेकर उठने लगे सवाल
- इन किरायेदारों को बिना पुलिस सत्यापन के दिया गया था मकान

बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद से बांग्लादेशी घुसपैठिये अपने देश लौटने लगे हैं। इसका असर बिहार के दरभंगा में भी देखने को मिला। जहां कथित तौर पर बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने गए 50 से अधिक फेरी वाले अब तक वापस नहीं आए हैं। इनके इस तरह गायब होने से सभी के बांग्लादेशी होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन दिनों बंगाल के हाकिमपुर चौकी पर घुसपैठियों के बांग्लादेश लौटने की होड़ लगी है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इन किरायेदारों को बिना पुलिस सत्यापन और किसी औपचारिक सूचना के कमरे किराये पर दिए गए थे। ऐसे में उनकी वास्तविक पहचान और पृष्ठभूमि को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

उर्दू, शिवधारा, अलीनगर आदि मोहल्लों में बंगाल निवासी होने का दावा कर किराये पर रहने वाले 50 से अधिक लोग यहां फेरी का काम करते थे। बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद भी ये मोहल्लों में नहीं दिख रहे।

मकान मालिकों को भी उनके लौटने का इंतजार है। वैसे तो ये लोग अपने घर जाने की बात कह कई बार गए हैं, लेकिन सप्ताहभर में वापस हो जाते थे। बता दें कि देह व्यापार के नेटवर्क में शामिल एक बांग्लादेशी महिला को 22 जुलाई, 2024 को नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर से दबोचा गया था।

59 वर्षीय ड्रग तस्कर सलीम डोला को अप्रैल 2026 में तुर्किये से भारत वापस लाया गया था। गत 20 वर्षों में डोला ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में एक ट्रग्स तस्करी नेटवर्क बनाया था।

दाऊद से जुड़े ड्रग रैकेट मामले में मुंबई और गुजरात में 20 से अधिक ठिकानों पर छापे

वैश्विक आतंकी का करीबी सलीम डोला को हाल ही में तुर्किये से भारत वापस लाया गया था

ईडी की कार्रवाई डोला के आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर केंद्रित

मुंबई, प्रेट्र: दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े ड्रग तस्कर मो. सलीम डोला के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच के तहत ईडी ने मंगलवार को महाराष्ट्र व गुजरात के 20 अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि डोला को हाल ही में तुर्किये से भारत वापस लाया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में 20 ठिकानों के अलावा सूरत, राजकोट और अंकलेश्वर में भी छापेमारी की गई। यह छापेमारी ईडी द्वारा मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद की गई। अफसरों ने बताया कि यह छापेमारी डोला के अवैध धन के स्रोतों का पता लगाने के लिए की गई है। इन छापों में अहम दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। सलीम डोला को वैश्विक आतंकी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी माना जाता है। उस पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह चलाने का आरोप है। ड्रग्स रोधी एजेंसियों ने उसके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। ईडी उसके वित्तीय नेटवर्क व संपत्तियों का पता लगा रही है। इसका उद्देश्य अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति जब्त करना है। 59 वर्षीय डोला को अप्रैल 2026 में तुर्किये से भारत लाया गया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। एनसीबी ने कहा था कि डोला ने गत 20 वर्षों में मध्य पूर्व, अफ्रीका व यूरोप में ट्रग्स तस्करी नेटवर्क बनाया था और एनसीबी, महाराष्ट्र-गुजरात पुलिस व डीआरआइ सहित कई एजेंसियों द्वारा वांछित था। गृह मंत्री अमित शाह ने 28 अप्रैल को डोला की गिरफ्तारी की घोषणा की थी। कहा था सरकार भारतीय एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए 'आपरेशन ग्लोबल हंट' के तहत दुनिया भर में ड्रग्स से जुड़े भगोड़ों व अन्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

तेलंगाना और गुजरात में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़

महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना और गुजरात में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मीरा भायंदर, वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस द्वारा एमडी ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए की गई जांच के दौरान तेलंगाना के जाहिराबाद में एक अवैध एमडी ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक कुल 20.72 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, मुंबई पुलिस ने गुजरात के नर्मदा जिले के एक गांव में चल रही मेफेड्रोन (एमडी) फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 75 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रग्स, केमिकल और उपकरण जब्त किए गए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सरकारी कर्मी के उच्च योग्यता छिपाने पर बर्खास्तगी की संभावना परखेगा सुप्रीम कोर्ट

- पीठ ने कहा-यह निर्णय प्रथम दृष्टया गलत, हम इसकी जांच करेंगे
- एसटी वर्ग के कर्मी ने मानदंड से ऊपर 'इंटरमीडिएट पास' होना छिपाया

नई दिल्ली, प्रेट्र: क्या एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी के लिए निर्धारित डिग्री से अधिक उच्च योग्यता छिपाने के कारण सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के एक फैसले की जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति की सेवा समाप्त करने के केंद्र के निर्णय को बरकरार रखा था। उसने 'दसवीं पास' मानदंड से अधिक 'इंटरमीडिएट पास' होने की जानकारी छिपाई थी, जो 'कार्य सहायक' की नौकरी के लिए आवश्यक थी।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा, अरविंद कुमार और श्री चंद्रशेखर की पीठ ने पवार सुभाष की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसने हाई कोर्ट के 27 नवंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी है। पीठ ने सुभाष के लिए उपस्थित वकील से कहा,"यह निर्णय प्रथम दृष्टया गलत है। हम इस निर्णय की जांच करेंगे। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जो कहता है कि उच्च योग्यता अयोग्यता का आधार नहीं हो सकती।"

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ता ने 'कार्य सहायक' के पद के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए निर्धारित योग्यता 'दसवीं पास' थी और उसने यह जानकारी नहीं दी थी कि वह पहले से ही "इंटरमीडिएट पास" था। इसने कहा कि सुभाष ने 2003 में 10वीं कक्षा पास की और 2006 में इंटरमीडिएट किया और 26 जुलाई, 2010 को इस पद के लिए आवेदन किया। हाई कोर्ट ने कहा कि सुभाष द्वारा किए गए घोषणा के आधार पर उसे नौकरी के लिए शार्टलिस्ट किया गया। आवेदन के चरण में और बाद की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इसे जानबूझकर जानकारी छिपाने के रूप में मानते हुए केंद्र सरकार ने 27 मई, 2013 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

सुभाष ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के समक्ष बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी, जिसने 27 मई, 2013 के आदेश को रद कर दिया और मामले को वापस भेजते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उसे सार्वजनिक रोजगार में रखने के पहलू पर पुनर्विचार करे, जिसके लिए वह अन्यथा योग्य था और एक स्पष्ट आदेश पारित करे। सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करते हुए 30 अप्रैल, 2022 को एक स्पष्ट विस्तृत आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक रोजगार के लिए अनुपयुक्त है।

'ड्रग्स मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, देश की संप्रभुता सर्वोच्च'

- जेल के अंदर से ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चलाने वाले की जमानत खारिज
- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आरोपित को प्रदान की थी जमानत

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर देश की संप्रभुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच कोई टकराव होता है, तो संप्रभुता को प्राथमिकता मिलेगी, खासकर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस एक्ट (एनडीपीएस) से जुड़े मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद करते हुए की, जिसमें मोबाइल फोन के जरिये जेल के अंदर से ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चलाने के एक आरोपित को जमानत प्रदान कर दी गई थी।

जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, "अगर देश की संप्रभुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच कोई टकराव होता है, तो बेशक संप्रभुता ही सबसे ऊपर रहेगी, खासकर तब जब देश के विरुद्ध जंग छेड़ी जाती है। भले ही वह ड्रग्स की आपूर्ति के रूप में हो, जो देश की आर्थिकी एवं लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है।" शीर्ष अदालत ने कहा, इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत इसी तरह के अपराध करने के पूर्व उदाहरण भी हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपित जमानत पर रहते हुए ऐसा अपराध नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि आरोपित ने सिर्फ एक वर्ष व सात महीने जेल में काटे हैं और दोषी पाए पर उसे 20 वर्ष तक सजा हो सकती है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत दखल का मामला भी नहीं बनता।

ड्रग्स बेचने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ड्रग्स बेचने वाले लोगों से बेहद सख्ती से निपटना होगा क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार एक आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस शील नागू और जस्टिस वी. मोहना की पीठ एक आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मद्रास हाई कोर्ट के इस वर्ष फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा था कि यह उसकी लगातार छठी जमानत अर्जी थी। अभियोजन के मुताबिक, 11 जून, 2022 को याचिकाकर्ता और दो अन्य लोग एक बैग लेकर खड़े थे। पुलिस को देखकर उन्होंने मौके से भागने की कोशिश की। आरोप है कि बैग में करीब 10.15 ग्राम वजन की 21 एमडीएमए-एक्स्टेसी टैबलेट मिली थीं। अभियोजन ने बताया कि याचिकाकर्ता एवं एक अन्य आरोपित के कबूलनामे के आधार पर मौके से भागे तीसरे आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।

लाडकी बहिन योजना बंद नहीं होगी: फडणवीस

- पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा, अपात्र पाई गई महिलाओं से राशि वापस नहीं ली जाएगी
- लेकिन जिन पुरुषों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है, उन्हें यह राशि लौटानी होगी

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को बंद नहीं करेगी। लाखों लाभार्थियों को सूची से हटाए जाने के बाद भी 1.70 करोड़ पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा। उनकी यह टिप्पणी 30 अप्रैल को ई-केवाईसी सत्यापन की समय सीमा समाप्त होने के बाद आई है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान योजना से जुड़े करीब 80 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए थे। इसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की थी।

देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा, योजना शुरू होने के बाद सरकार ने लाभार्थियों का सत्यापन कराया था। इसमें कई अनियमितताएं सामने आईं। जब योजना शुरू की गई थी, तब महिलाओं को स्वयं अपने पात्र होने का प्रमाण देने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि कई महिलाओं के पास दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। बाद में सत्यापन कराया गया, क्योंकि योजना पर होने वाला सरकारी खर्च आडिट के दायरे में आता है।

देवेंद्र फडणवीस। फाइल

फडणवीस ने कहा, योजना के तहत अपात्र पाई गई महिलाओं से पूर्व में दी गई राशि वापस नहीं ली जाएगी, पर जिन पुरुषों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है, उन्हें यह राशि लौटानी होगी। उन्होंने कहा कि जांच में कई विसंगतियां सामने आईं हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की महिलाओं द्वारा लाभ लेना और कुछ मामलों में पुरुषों द्वारा आवेदन करना भी शामिल हैं। लगभग 10 लाख लाभार्थियों के मामलों में पात्रता संबंधी गड़बड़ियां पाई गईं, जबकि करीब 14 हजार पुरुषों ने भी इस योजना के तहत आवेदन किया था। अपात्र महिलाओं और अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वालों का भुगतान रोक दिया गया है।

उगाही के विरोध पर आरपीएफ जवानों ने कैंटीन प्रबंधक को पिलाया पेशाब

- सवाईमाधोपुर जिले का मामला, प्रारंभिक जांच में सही पाए गए आरोप

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान में सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर एक कैंटीन प्रबंधक के साथ राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एएसआइ सहित चार पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। कैंटीन प्रबंधक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मासिक रिश्वत नहीं देने पेशाब पीने पर मजबूर किया। पीड़ित की शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने चारों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। प्रारंभिक जांच में कैंटीन प्रबंधक के आरोप सही पाए गए हैं।

मध्य प्रदेश के भिंड निवासी पीड़ित का आरोप है कि 26 मई की रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपित एएसआइ कैंटीन पर आए और मासिक रिश्वत मांगी। मैंने रिश्वत देने से इन्कार किया तो लाइसेंस रद कराने व झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर वापस चले गए। रात 11 बजे एक पुलिसकर्मी थाने में स्थित आवास पर ले गया। वहां आरोपित एएसआइ के साथ दो पुलिसकर्मी पहले से थे। चारों ने वारदात को अंजाम दिया। साथ ही जेब से 15,700 रुपये निकाल लिए। कोटा मंडल रेलवे पुलिस के उपाधीक्षक शकील अहमद ने बताया कि सभी पक्षों के बयान दर्ज कर साक्ष्यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। ज्ञात हो, पीड़ित ने 30 मई को जयपुर के जीआरपी मुख्यालय में मुकदमा दर्ज कराया था।

जयपुर में भाजपा नेता की गला रेतकर हत्या

जासं, जयपुर: भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रामावतार असवाल की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मनोहरपुर थाने के प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक अज्ञात व्यक्ति रात करीब आठ बजे असवाल के गोदाम में पहुंचा और बातचीत के दौरान उसने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। देर रात तक असवाल घर नहीं पहुंचे तो तलाशते हुए स्वजन गोदाम में पहुंचे। वे लहूलुहान हालत में असवाल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वजन एवं भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अधिकारियों ने कार्रवाई व स्वजन को वित्तीय मदद का भरोसा देकर धरना खत्म कराया।

रतलाम में एक माह रहे चार चीनी नागरिक, होटल संचालक ने छिपाई जानकारी

- बिजनेस वीजा पर भारत आए थे चारों चीनी नागरिक, होटल प्रबंधन ने नहीं दी पुलिस को सूचना
- 24 घंटे में सी-फार्म अपलोड करना था अनिवार्य, खुफिया एजेंसी की जांच में सामने आया मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम

मप्र के रतलाम में स्टेशन रोड थाना क्षेत्र स्थित होटल अजंता पैलेस में चीन के चार नागरिक करीब एक माह ठहरे। यह जानकारी होटल प्रबंधन ने आनलाइन प्लेटफार्म पर अपलोड नहीं की। जानकारी छिपाने का मामला खुफिया एजेंसी के संज्ञान में आने पर होटल संचालक डा. सुभाष अग्रवाल और मैनेजर शिव सिंह राठौर पर अप्रवास एवं विदेशियों विषयक अधिनियम-2025 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान चार चीनी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और मशीनरी संबंधी कार्य के संबंध में रतलाम में रुके थे। रिकार्ड के मुताबिक, जू हू 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक, झी गुआंगजियान 30 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक तथा यांग झोंगफू और लियू यान तीन जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक होटल में ठहरे थे। इसके बावजूद होटल प्रबंधन ने न तो संबंधित जानकारी सी-फार्म पोर्टल पर अपलोड की और न ही स्थानीय पुलिस अथवा एसपी कार्यालय को सूचित किया। सूत्रों के अनुसार, चारों चीनी नागरिकों की ट्रेवल हिस्ट्री की जांच के दौरान उनके रतलाम प्रवास की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद संबंधित खुफिया एजेंसी ने सी-फार्म पोर्टल का मिलान किया, लेकिन आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं मिली। इस पर एजेंसी ने रतलाम पुलिस को सूचित किया।

होटल अजंता पैलेस जहां ठहरे थे चीनी नागरिक। नईदुनिया

यह है सी-फार्म नियम

- किसी भी होटल, लाज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या निजी परिसर में विदेशी नागरिक के ठहरने पर उसकी सूचना देना अनिवार्य है।
- संचालक या प्रबंधक को विदेशी नागरिक के आने के 24 घंटे के भीतर आनलाइन सी-फार्म भरना होता है।
- यह जानकारी जिला प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों के रिकार्ड में दर्ज होती है।
- नियम का उद्देश्य विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
- जानकारी छिपाने या समय पर अपलोड नहीं करने पर आप्रवास एवं विदेशियों विषयक अधिनियम-2025 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

कतरन से बदलाव की कहानी पहुंची अंतरराष्ट्रीय मंच तक

कपड़ों की कतरनों से कठपुतलियां बना पर्यावरण एवं विरासत को सहेजने वाली आलिया स्लिंगशाट चैलेंज में शामिल

गौरी त्रिवेदी • जागरण

लखनऊ: कपड़े की कतरन किसी काम की नहीं होती, लेकिन 14 वर्षीय आलिया फातिमा रिजवी ने इन्हीं टुकड़ों को लेकर एक सपना देखा। ऐसा सपना, जिसने न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ला मार्टिनियर गर्ल्स कालेज की कक्षा नौ की छात्रा आलिया का चयन प्रतिष्ठित स्लिंगशाट चैलेंज में हुआ है, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक और डिज्नी आयोजित करते हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्हें एक हजार डालर की पुरस्कार राशि भी मिलेगी, जो वर्तमान विनिमय दर के अनुसार लगभग 95 हजार रुपये के बराबर है।

इस उम्र में ही आलिया ने यह साबित कर दिया है कि बड़ा बदलाव लाने को बड़ी उम्र की नहीं, बड़े सोच की जरूरत होती है। लखनऊ की गलियों में बिखरी कपड़ों की कतरन से शुरू हुई उनकी कहानी आज अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी है। यह एक छात्रा की सफलता नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजने वाली सोच दुनियाभर में पहचान बना सकती है।

आलिया बताती हैं कि जब वह अपने माता-पिता के साथ पुराने बाजारों में जाती थीं, तब अक्सर दर्जियों की दुकानों और सिलाई केंद्रों के बाहर कपड़ों की कतरनें बिखरी दिखाई देती थीं। उनके मन में सवाल उठता था कि आखिर इनका क्या होता होगा। मन में विचार आया कि क्यों न लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए और बेकार समझी जाने वाली सामग्री को उपयोगी बनाया जाए। उन्हें लखनऊ की प्रसिद्ध गुलाबो-सिताबो परंपरा याद आई। कठपुतलियों के माध्यम से कहानी कहने की यह कला लखनऊ की पहचान रही है। फिर उन्होंने कतरन से कठपुतलियां बनाने और उनके जरिये पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने पर कार्य शुरू किया। वह कहती हैं कि उनका माडल केवल वस्तुएं बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें बच्चों को शामिल करना, कार्यशालाएं आयोजित करना और कहानियों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना भी शामिल है।

कतरन से कठपुतली बनाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देतीं आलिया (बाएं) • स्वयं

सरकारों के भरोसे नहीं रहें लोग

आलिया बताती हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या बड़े संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर बदलाव ला सकता है। उनका संदेश है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, जबकि प्रयास और सीख हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए कभी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा कुछ नया तथा सकारात्मक करने की कोशिश करनी चाहिए।

वैश्विक प्रतियोगिता में 100 से अधिक देशों के हजारों युवाओं ने लिया हिस्सा

यह वैश्विक प्रतियोगिता युवाओं को पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने को प्रेरित करती है। इस वर्ष इसमें 100 से अधिक देशों के हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, लेकिन आलिया के अनूठे विचार ने शीर्ष में जगह बनाई। अक्टूबर में उन्हें वाशिंगटन डीसी आमंत्रित किया गया है, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

बच्चे किताबों के बजाय कहानियों व गतिविधियों से अधिक सीखते

आलिया का मानना है कि बच्चे किताबों की तुलना में कहानियों व गतिविधियों से अधिक सीखते हैं। यही वजह है कि वह कठपुतलियों के जरिये क्षेत्र के बच्चों को समझाती हैं। इसमें वह बताती हैं कि किसी भी वस्तु को कचरा मानकर फेंकना जरूरी नहीं है। उसका दोबारा उपयोग हो सकता है। बच्चे इससे प्रेरित होकर बेकार सामग्री से उपयोगी वस्तु बनाने व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयास करने लगे हैं।

कक्षा नौ की छात्रा आलिया अभिनव प्रयोग से दे रहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश • स्वयं >>

उत्तर भारत में वर्कशाप की योजना

आलिया कहती हैं कि उत्तर भारत में कठपुतली निर्माण को लेकर कार्यशालाएं आयोजित जाएंगी। इनमें बच्चे खुद कतरन से कठपुतलियां बनाना सीखेंगे। इसके बाद, इन्हीं कठपुतलियों के जरिये नाटक और कहानियों के माध्यम से बच्चों को कचरा प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

बुलेट ट्रेन परियोजना मे तीसरी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू, निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार

- यह उपलब्धि पालघर जिले की दहाणू तहसील के अंबेसरी गांव स्थित एमटी-07 सुरंग में हासिल की गई
- दहाणू में पांच माह के भीतर महाराष्ट्र की तीसरी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू हुआ है पूरा

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने एक और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। महाराष्ट्र में परियोजना की तीसरी पर्वतीय सुरंग का सफल ब्रेकथ्रू (सुरंग के दोनों सिरों का मिलन) पूरा हो गया है। इससे देश की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। यह उपलब्धि पालघर जिले की दहाणू तहसील के अंबेसरी गांव स्थित एमटी-07 सुरंग में हासिल की गई। परियोजना का यह हिस्सा तकनीकी दृष्टि से सबसे चुनौतीपूर्ण खंडों में से एक माना जाता है।

अश्विनी वैष्णव। फाइल

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने एक और मील का पत्थर पार किया है। दहाणू में पांच माह के भीतर महाराष्ट्र की तीसरी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू पूरा हुआ है। पीएम नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल यह बुलेट ट्रेन कारिडोर देश के दो प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक केंद्रों मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा को नया आयाम देने के साथ ही आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेगा। नई एमटी-07 सुरंग की लंबाई 417 मीटर और चौड़ाई 14.4 मीटर है। इसे हाई-स्पीड रेल लाइन की अप और डाउन दोनों पटरियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुरंग की खोदाई दोनों सिरों से एक साथ नियंत्रित ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक के माध्यम से की गई, जिसमें उन्नत इंजीनियरिंग और सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग किया गया।

परियोजना अधिकारियों के अनुसार, निर्माण के दौरान संरचनात्मक स्थिरता और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक भू-तकनीकी उपकरणों तथा रियल टाइम निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया गया। इनमें सतही धंसाव बिंदु, थ्री-डी मानिटरिंग टारगेट, स्ट्रेन गेज और सिस्मोग्राफ जैसे उपकरण शामिल थे। इनकी मदद से सुरंग की स्थिति, भूमि की हलचल और कंपन के स्तर पर लगातार नजर रखी गई। निर्माण के दौरान वेंटिलेशन सिस्टम, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था और निरंतर भू-तकनीकी निगरानी जैसे व्यापक सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए। इससे पहले महाराष्ट्र में परियोजना की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आ चुकी हैं।

पालघर जिले के सफाले के निकट स्थित 1.5 किलोमीटर लंबी एमटी-05 सुरंग का ब्रेकथ्रू दो जनवरी 2026 को पूरा हुआ था। इसके बाद तीन फरवरी 2026 को एमटी-06 सुरंग का ब्रेकथ्रू हुआ। इसकी लंबाई 454 मीटर है, जिसे न्यू आस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) के माध्यम से बनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रगति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि किसी भी बड़ी रेल परियोजना में सुरंग और भूमिगत निर्माण कार्य उसकी गति निर्धारित करते हैं। सुरंगों के सफल ब्रेकथ्रू से इंजीनियरिंग संबंधी अनिश्चितताएं कम होती हैं और ट्रैक बिछाने, सिस्टम इंस्टालेशन तथा अन्य निर्माण कार्यों का मार्ग प्रशस्त होता है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत प्रस्तावित आठ पर्वतीय सुरंगों में से सात महाराष्ट्र के पालघर जिले में तथा एक गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है। वलसाड की सुरंग का निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

दैनिक जागरण
शिक्षा आदर्श व्यक्तित्व निर्माण का आधार है

शहरों की बिगड़ती सूरत

देश की राजधानी में एक पांच मंजिला भवन गिरने से छह लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद भवन स्वामी की गिरफ्तारी करने के साथ ही नगर निगम के दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए। इस घटना के बाद नगर निगम यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर शिकायतों के बाद भी उक्त इमारत में अतिरिक्त मंजिल का अवैध निर्माण कैसे हो रहा था? वह अन्य ऐसी ही इमारतों की छानबीन में भी जुट गया है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और अवैध निर्माण का सिलसिला बंद होगा, क्योंकि यदि ऐसा होना होता तो बहुत पहले हो गया होता। आखिर दिल्ली में ऐसी कोई इमारत पहली बार नहीं गिरी, जो अवैध रूप से बनी थी या निर्मित की जा रही थी। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और फिर भी नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि नगर निकाय के अधिकारी-कर्मचारी कुछ ले-देकर अवैध निर्माण होने देते हैं। वे पैसों के लालच में भवन निर्माण संबंधी नियम-कानूनों की अनदेखी करते हैं। इस मामले में जो स्थिति दिल्ली की है, वही शेष देश की भी है।

हमारे हर छोटे-बड़े शहर में अवैध एवं बेतरतीब निर्माण हो रहा है। यह स्थानीय निकायों के संरक्षण और उनकी जानकारी में होता है। इसी कारण शहरों में अवैध तरीके से रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों का निर्माण होता रहता है। स्थिति यह है कि जो पुराने भवन दो-तीन मंजिल के होते हैं, वे जर्जर होने के बाद भी अवैध निर्माण के सहारे चार-पांच मंजिलों में तब्दील कर लिए जाते हैं। इससे क्षेत्र विशेष में आबादी का दबाव बढ़ने के साथ नागरिक सुविधाओं का अभाव भी बढ़ता है। अपने देश में ऐसा कोई नियम ही नहीं कि किसी इलाके में कितनी आबादी रहनी चाहिए। इससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि हर कहीं रिहायशी इलाके व्यावसायिक इलाकों में तब्दील हो रहे हैं। देश भर में घरों में दुकानें बनाने की होड़ सी कायम है। ऐसा पुराने मोहल्लों के साथ नए मोहल्लों में भी हो रहा है। इसी कारण हमारे शहर बेतरतीब विकास का पर्याय बन गए हैं और वे नागरिक सुविधाओं के अभाव के साथ प्रदूषण एवं गंदगी से घिरते जा रहे हैं। अनियोजित शहर नगरीय जीवन को केवल कष्टकारी ही नहीं बनाते, बल्कि वे विकास में बाधक भी बनते हैं। आज के युग में शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, लेकिन तभी, जब उनका नियोजित ढंग से विकास हो। विडंबना यह है कि जिन नगर निकायों की पहली जिम्मेदारी शहरों के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है, वे उसका ही निर्वाह करने में बुरी तरह नाकाम हैं। यदि शहरों की सूरत संवारनी है और उन्हें विकास का वाहक बनाना है तो स्थानीय निकायों के कामकाज के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदलना होगा।

निगरानी जरूरी

झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग समुदायों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए संचालित योजनाएं राज्य की समावेशी विकास नीति का महत्वपूर्ण आधार हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर छात्रवृत्ति, छात्रावास, स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति की समीक्षा तथा लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश स्वागतयोग्य हैं। विशेष रूप से ओबीसी छात्रवृत्ति का मुद्दा महत्वपूर्ण है। यदि केंद्र से अपेक्षित राशि नहीं मिल रही है, तब भी राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर यह संदेश देना सकारात्मक है कि आर्थिक संसाधनों की कमी विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा नहीं बनने दी जाएगी। छात्रवृत्ति समय पर मिलना हजारों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा जारी रखने का आधार है। छात्रवृत्ति समय पर मिले, यह हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि केवल बजट आवंटन पर्याप्त नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि प्रशासनिक विलंब, निगरानी की कमी और समन्वय के अभाव में अच्छी योजनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। ऐसे में हर छह महीने में समीक्षा बैठक करने का सुझाव व्यावहारिक है। नियमित समीक्षा से कमियों की पहचान समय रहते हो सकेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। कल्याणकारी योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना यही है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचे।

> कल्याणकारी योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना यही है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचे

गति पकड़ता सेमीकंडक्टर अभियान

हर्ष वी. पंत

भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम में महज एक उपभोक्ता या असेंबलिंग तक ही सीमित न रहकर स्वयं को एक उत्पादक के रूप में भी स्थापित कर रहा है

अवधेश राजपूत

वर्तमान दौर में सेमीकंडक्टर की अहमियत किसी से छिपी नहीं रही है। इस संदर्भ में अच्छी बात यह है कि भारत ने भी इसके निर्माण में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया नीदरलैंड दौरे पर वहां की दिग्गज कंपनी एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रानिक्स के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। एएसएमएल को आधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण की रीढ़ मानी जाने वाली उन्नत लिथोग्राफी प्रणालियों के मामले में विश्व के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में से एक माना जाता है। यह अनुबंध इसका प्रतीक है कि भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम में महज एक उपभोक्ता या असेंबलिंग तक ही सीमित न रहकर समूची मूल्य श्रृंखला में स्वयं को स्थापित करने पर ध्यान दे रहा है। यह करार गुजरात के धोलेरा में 11 अरब डालर के निवेश वाले टाटा के प्रस्तावित चिप निर्माण संयंत्र के लिए बेहद अहम है। धोलेरा को भारत के सेमीकंडक्टर हब के रूप में भी देखा जा रहा है।

सेमीकंडक्टर को लेकर भारत का दृष्टिकोण आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों से प्रेरित है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्ट्रानिक्स की खपत में तेजी के चलते देश सेमीकंडक्टर के आयात पर बड़ी हद तक निर्भर है। आज के इस दौर में तमाम चिप्स आटोमोबाइल एवं दूरसंचार से लेकर रक्षा प्रणालियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे उदीयमान क्षेत्रों की रीढ़ बन चुके हैं, वहां उसकी आधारभूत सामग्री पर बाहरी निर्भरता को घटाना आत्मनिर्भरता के साथ ही आर्थिक सुरक्षा का भी एक अहम अवयव बन गया है। इसका भू-राजनीतिक संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन मुख्य रूप से ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका में केंद्रित है। कोविड-19 महामारी से लेकर अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी मोर्चे पर तनातनी जैसे पहलुओं ने इस आपूर्ति में गतिरोध पैदा करने का काम किया है। इसने दर्शाया है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं का संकेंद्रण कितना भारी पड़ सकता है। इसका ही परिणाम रहा कि प्रमुख वैश्विक विनिर्माताओं और सरकारों ने उत्पादन में विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए चीन से इतर उत्पादन की 'चीन प्लस वन' वाली नीति को अपनाया। इस क्रम में अपने बड़े बाजार, जनसांख्यिकीय गहराई और बढ़ते भूराजनीतिक महत्व के चलते भारत स्वयं को एक आकर्षक वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेमीकंडक्टर निर्माण के निहितार्थ केवल वाणिज्यिक हितों तक सीमित नहीं हैं। सुरक्षित और विश्वसनीय चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण का पहलू अब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी गहराई से जुड़ा है। विशेष रूप से रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, साइबर बुनियादी ढांचे, दूरसंचार और एआइ संचालित तकनीकों जैसे क्षेत्रों में। इसी कारण सेमीकंडक्टर परिदृश्य महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के एक नए मोर्चे के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र में भारत का प्रवेश बदलती वैश्विक वास्तविकताओं को स्वीकारने के उसके रवैये को ही रेखांकित करता है। नई दिल्ली ने इसी को ध्यान में रखकर अपना नीतिगत ढांचा भी तैयार किया है। इसके अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आइएसएम, स्वीकृत चिप निर्माण परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता जैसी पहल की गई हैं। शायद ही विश्व में कहीं और ऐसे प्रोत्साहन दिए गए हैं। केंद्रीय बजट में भी आइएसएम 2.0 के दायरे का विस्तार करते हुए सेमीकंडक्टर उपकरण, सामग्री, बौद्धिक संपदा विकास, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन और शोध एवं विकास यानी आरएंडडी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सेमीकंडक्टर अभियान से जुड़ी कई परियोजनाएं अब धरातल पर साकार होने लगी हैं। गुजरात इन गतिविधियों का गढ़ बना हुआ है। धोलेरा में टाटा-पावरचिप फैब्रिकेशन परियोजना तो साणंद में माइक्रोन की एटीएमपी इकाई स्थापित हो रही है। असम को टाटा की ओसैट परियोजना हासिल करने में सफलता मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एचसीएल-फाक्सकान संयुक्त उपक्रम के माध्यम से स्वयं को इस परिदृश्य पर मजबूती से उभारने में लगा है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 तो बाकायदा दर्शाती है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी, कर छूट, भूमि दरों में रियायत, बिजली रियायत और कौशल विकास पहलों के माध्यम से केंद्रीय प्रोत्साहनों की पूरक बनकर इस प्रक्रिया को रफ्तार दे रही हैं। केंद्रीय रणनीतिक दूरदर्शिता और राज्यस्तरीय प्रतिस्पर्धा के बीच का यह तालमेल धीरे-धीरे भौगोलिक रूप से एक व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है।

कई स्तरों पर प्रगति के बावजूद इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चिप निर्माण उन उद्योगों में से एक है, जिनके लिए व्यापक स्तर पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। पानी की भरोसेमंद एवं सतत आपूर्ति, बिजली की निरंतर उपलब्धता, कुशल कामकाजी आबादी एवं सक्षम आपूर्ति तंत्र का सुनिश्चित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान विश्व में निर्यातों को लेकर जिस तरह के नियंत्रण एवं भू-राजनीतिक तनाव, खेमेबंदी और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसके प्रभाव से यह क्षेत्र भी अछूता नहीं। इन पहलुओं के सम्मिलित प्रभाव भी इस क्षेत्र के भविष्य की दशा-दिशा को प्रभावित करेंगे। देखा जाए तो टाटा-एएसएमएल अनुबंध, माइक्रोन संयंत्र के संचालन और आइएसएम 2.0 के साथ स्पष्ट है कि भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति संकल्पना के स्तर से वास्तविकता का आकार ग्रहण करने लगी है। इससे एक दीर्घकालिक औद्योगिक क्रांति की बुनियाद रखी जा रही है। वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में स्वयं को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे भारत को इससे केवल आर्थिक लाभ ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वह रणनीतिक स्वायत्तता भी प्राप्त होगी, जहां तकनीकी क्षमताएं शक्ति संतुलन में अहम भूमिकाएं निभाने लगी हैं।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

12 बरस की सफलताएं और विफलताएं

राजीव सचान

मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते समय इस पर भी ध्यान दे कि उसके हिस्से में कुछ नाकामियां भी हैं

मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह तय है कि इस अवसर पर उसकी ओर से अपनी उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। इसके लिए भाजपा की ओर से एक अभियान चलाया जाने वाला है, जिसमें लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। निःसंदेह मोदी सरकार के पास अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और यह हर सरकार का अधिकार है कि वह उनके बारे में जनता को अवगत कराए। यदि मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करें तो उनकी एक लंबी सूची है। इन उपलब्धियों में कई ऐसे फैसले हैं, जिनमें से कुछ के बारे में यह कल्पना करना कठिन था कि कोई सरकार ऐसे फैसले ले पाएगी, जैसे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करना और फिर आपरेशन सिंदूर। ये दोनों सैन्य अभियान इस मायने में विशेष रहे कि विश्व में पहली बार किसी परमाणु हथियार संपन्न देश ने दूसरे ऐसे ही देश पर हवाई हमले किए। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, लेकिन यदि मोदी सरकार नहीं होती तो शायद यह रास्ता बाधित ही रहता और राम मंदिर का निर्माण आनन-फानन नहीं होता। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में एक समान नागरिक संहिता की दिशा में भी आगे बढ़ रही है।

जीएसटी लागू होना भी इस सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वैसे तो नोटबंदी भी एक साहसिक फैसला था, लेकिन इसके वैसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए, जैसे अपेक्षित थे। माओवाद का खात्मा भी मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ वर्षों पहले तक माओवाद का खात्मा असंभव सा दिखता था, पर मोदी सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संभव कर दिखाया और वह भी तय समय में। पिछले 12 वर्षों में आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। देश भर में सड़कों का तेजी से निर्माण हुआ है। इसी तरह पुल, बिजलीघर, हवाई अड्डे निर्मित हुए हैं और

विफलताओं पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी। फाइल

रेल सुविधाओं का विकास हुआ है। ग्रामीण विकास की योजनाओं ने भी रफ्तार पकड़ी है। देश में डिजिटलीकरण भी द्रुत गति से हुआ है। इसके चलते भारत डिजिटल लेनदेन के मामले में विश्व में अग्रणी है। विकास के साथ ही प्रभावशाली जनकल्याणकारी योजनाओं की भी एक लंबी सूची है। इन योजनाओं ने आम आदमी का जीवन बदला है। शौचालय निर्माण, उज्ज्वला, आवास, बिजली, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन संबंधी जैसी योजनाओं ने सचमुच लोगों को लाभान्वित किया है। जनधन योजना निर्धन जनता के वित्तीय समावेशन की एक बड़ी मिसाल है। इन योजनाओं के चलते करोड़ों लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि उसे जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना आता है। इन 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी बहुत काम हुआ है।

यदि आज भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की 22 राज्यों में सरकारें हैं तो इसका एक बड़ा कारण मोदी सरकार की रीति-नीति है। कोई भी सरकार हो, उसकी प्रत्येक योजना कसौटी पर खरी नहीं उतरती। ऐसा ही मोदी सरकार की कुछ योजनाओं के साथ हुआ है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। हर सरकार के समय महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे रहते हैं। मोदी सरकार के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

अब जब मोदी सरकार अपने 12 साल की उपलब्धियों का गुणगान करने में जुटने वाली है, तब किसी को उसका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिए कि कुछ ऐसे मोर्चों पर उसे विफलता हाथ लगी है, जिनमें उसे सफलता अर्जित करनी चाहिए थी, जैसे शिक्षा और परीक्षाओं की सूरत बदलनी चाहिए थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद भी शिक्षा का हाल संतोषजनक नहीं और परीक्षाओं, विशेषरूप से प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल तो बहुत ही बुरा है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारें एक ही नाव पर सवार हैं। रह-रहकर प्रश्नपत्र लीक होते रहते हैं। मोदी सरकार की एक बड़ी विफलता न्याय को सुलभ और सुगम न बना पाना है। लचर न्यायिक तंत्र देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। इसी तरह की एक बड़ी बाधा सरकारी कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार लाइलाज हो गया दिखता है। जहां निर्माण वहां तो भ्रष्टाचार है ही, इसके अलावा जहां कहीं भी सरकारी अनुमति, अनुमोदन आदि की आवश्यकता होती है, वहां भी लेन-देन होता है। स्मार्ट सिटी योजना भी कुल मिलाकर नाकाम ही रही और हमारे शहर बेतरतीब विकास की कहानी कहने के साथ विकसित भारत के लक्ष्य का बड़ी बाधा बने हुए हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि मोदी सरकार अपनी 12 बरस की उपलब्धियों को गिनाते समय इस पर गंभीरता से ध्यान दे कि उसे कुछ विफलताएं भी हाथ लगी हैं, जिनके कारण देश में बेचैनी बढ़ रही है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म का मर्म

धर्म एक ऐसा विशाल छत्र है, जिसकी छाया में पूरा संसार क्रियाशील है। ये धर्म ही है, जो जगत को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक अदृश्य संविधान के रूप में संसार में व्याप्त है। यही अनंतकाल से भौतिक संसार को निर्बाध बांधे हुए है। धर्म की विकृत तथा संकुचित परिभाषा ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि धर्म का अभिप्राय मात्र मत या पंथ से है। वास्तविकता में तो धर्म वह अटल एवं शाश्वत सिद्धांत है, जिसके माध्यम से संसार की हर क्रिया संचालित होती है। ग्रहों का धर्म है एक निश्चित गति पर सूर्य की परिक्रमा करना, ऋतुओं का धर्म है अपने स्वभाव अनुसार फल देना, वृक्ष का धर्म है छाया तथा फल देना।

मानव के संबंध में धर्म का मर्म बहुत व्यापक है। मानव के अतिरिक्त संपूर्ण जगत का धर्म एक सीमा से बंधा हुआ है, किंतु मानव का धर्म और व्यवहार देश-काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष भी है। उसे इस कसौटी पर खरा भी उतरना है, क्योंकि यदि व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप धर्मोचित व्यवहार न करे तो वह अधर्म है। इस कारण भी कि मानव के पास ही वह विवेक है जो तय करता है कि उसके लिए किस समय क्या धर्म है। यहां प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि धर्म का अनुपालन आवश्यक क्यों है? वस्तुतः धर्म ही वह महीन रेखा है जो उचित तथा अनुचित को अलग करती है।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का समग्र जीवन एक आदर्श धर्मोचित जीवन का जीवंत उदाहरण है। तभी हम कहते हैं 'रामो विग्रहवान धर्मः' अर्थात राम ही धर्म का विग्रह स्वरूप हैं। अतः जीवन में धर्म का पालन कर्तव्य से मुक्ति के लिए आवश्यक है। महाभारत की शिक्षा है 'यतो धर्मस्ततो जयः' अर्थात जहां धर्म है, वहीं विजय है और विजयश्री का आलिंगन धर्म की परिधि में ही संभव है। धर्म ही उत्थान है और अधर्म ही पतन।

आदित्य नारायण अवस्थी

'साइकिल संस्कृति' को करें आत्मसात

सुधीर कुमार

एम्सटर्डम की सड़कों और गलियों को साइकिल चालकों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है

नीदरलैंड (हालैंड) की राजधानी एम्सटर्डम अपनी अनूठी 'साइकिल संस्कृति' के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की तकरीबन 60 प्रतिशत से अधिक आबादी आवागमन के लिए प्रतिदिन साइकिल का इस्तेमाल करती है। हां के नागरिकों में साइकिल के प्रति गजब का जुनून है। यह उनकी जीवनशैली का हिस्सा होने के साथ-साथ 'स्टेटस सिंबल' तक बन चुका है।

एम्सटर्डम एक ऐसा शहर है, जहां की सड़कों और गलियों को साइकिल चालकों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जबकि आमतौर पर ऐसा करते समय साइकिल चालकों के बारे में गंभीरता से सोचा भी नहीं जाता है। हालांकि एम्सटर्डम को अपनी विशिष्ट साइकिल संस्कृति विकसित करने में दशकों लग गए। इसे परिवहन का व्यावहारिक साधन बनाने में कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रमुख योगदान रहा। द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के दौरान ईंधन की उपलब्धता के प्रभावित होने से साइकिल ही आवागमन का सहारा बनी, जिससे साइकिल की मांग एकाएक बढ़ गई, लेकिन विश्वयुद्ध के खत्म होते-होते जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों की मांग में जबरदस्त उछाल आ गया। 1950-60 के दशक तक आते-आते वहां चार पहिया वाहनों की संख्या इस कदर बढ़ी कि साइकिल चालकों को शहर से बाहर निकाले जाने का खतरा महसूस होने लगा। हालांकि, 1973 के तेल संकट ने इस परिदृश्य को एक बार फिर बदल दिया। अरब निर्यातक देशों द्वारा नीदरलैंड समेत कई देशों पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप तेल की कीमत चौगुनी हो गई। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री जूप डेन उइल द्वारा डच नागरिकों से जीवनशैली में बदलाव लाने और ऊर्जा बचत के आह्वान ने लोगों को टिकाऊ परिवहन की ओर अग्रसर किया। साइकिल के प्रति बढ़ते क्रेज का नतीजा है कि आज एम्सटर्डम में साइकिलों की संख्या वहां के निवासियों से अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एम्सटर्डम की आबादी लगभग आठ लाख है, जबकि साइकिलों की संख्या साढ़े आठ लाख से भी अधिक पहुंच चुकी है। इस अनूठी साइकिल संस्कृति से एम्सटर्डम को यातायात की भीड़ एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और सतत विकास को बढ़ावा देकर 'नेट जीरो' के 2050 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिली है। यह 'जीवन प्रत्याशा' को सुधारने और नागरिकों के लिए आर्थिक बचत का माध्यम भी बन रहा है।

साइकिल परिवहन का किफायती और पर्यावरणनुकूल साधन है। इसे प्राथमिकता देने से ईंधन की बचत होगी, निर्भरता घटेगी और प्रदूषण-मुक्त समाज की स्वप्न भी साकार हो पाएगा। ईंधन संकट के मौजूदा दौर में समाज को 'साइकिल संस्कृति' की ओर लौटना ही होगा।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

शिक्षा के स्तर में हो सुधार

'अविश्वास से घिरती जा रही परीक्षाएं' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने परीक्षा व्यवस्था पर गहराते अविश्वास, नकल, प्रश्नपत्र लीक तथा नैतिक मूल्यों के क्षरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। निःसंदेह यह चिंता समयोचित है, किंतु इस संकट की जड़ें परीक्षा कक्षों से कहीं अधिक गहरी हैं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं, आर्थिक असमानताओं और शिक्षा की बदलती प्राथमिकताओं का भी परिणाम है। वर्तमान समय में परीक्षा ज्ञानार्जन का साधन कम और आजीविका का प्रवेशद्वार अधिक बन गई है। करोड़ों युवा सीमित अवसरों के लिए संघर्षरत हैं। जब नियुक्तियां वर्षों तक लंबित रहें, प्रतियोगिता असंतुलित हो और सफलता का एकमात्र मानदंड अंक बन जाएं, तब व्यवस्था के प्रति संशय स्वाभाविक है। दुर्भाग्य यह है कि हम परिणामों पर विमर्श करते हैं, कारणों पर नहीं। एक तथ्य यह भी है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास माना गया था, किंतु आज वह अंकों और प्रमाणपत्रों की प्रतिस्पर्धा में सिमटती जा रही है। कोचिंग-केंद्रित संस्कृति ने जिज्ञासा का स्थान स्मरणशक्ति को और ज्ञान का स्थान परीक्षा-कौशल को दे दिया है। ऐसी स्थिति में अनैतिक साधनों का आकर्षण बढ़ना अस्वाभाविक नहीं। समाधान केवल कठोर दंड में नहीं, बल्कि शैक्षिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना में निहित है। भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, तार्किक चिंतन और कौशल विकास को समान महत्व मिले। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं की अनिश्चितता कम की जाए। परीक्षा तभी विश्वसनीय बनेगी, जब व्यवस्था निष्पक्ष, अवसर पर्याप्त और समाज ईमानदारी को सफलता से अधिक सम्मान देने लगेगा।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

'खेत बचाओ अभियान' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के नुकसान से अवगत कराया गया है। यह अत्यधिक उपयोग जिन कारणों से होता है उसमें सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी है। जिसके कारण प्रति वर्ष सरकार को पौने दो लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसकी कीमत घट जाती है। किसान नासमझी में या यूं कहें जागरूकता के अभाव में अत्यधिक पैदावार के लोभ में दोगुना उर्वरकों का प्रयोग कर डालते हैं। जाहिर सी बात है यूरिया में एनपीके की मात्रा भी असंतुलित रहती है। आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। कहीं-कहीं अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी बंजर होने के कगार पर है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

विकास या मौत का जाल

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का गिरना कोई सामान्य तकनीकी खराबी या प्राकृतिक हादसा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर प्रशासनिक साठगांठ, भ्रष्टाचार और इंसानी जिंदगियों के साथ किया गया एक घिनौना खिलवाड़ है। इस पूरे मामले में जो सबसे गंभीर और आपराधिक लापरवाही सामने आई है, वह यह है कि तीन महीने पहले ही पिलर में आई दरार को तकनीकी रूप से ठीक करने के बजाय महज सीमेंट से पाटकर छिपा दिया गया। सोचने कि बात यह है कि अगर यह लापरवाही समय रहते सामने न आती और पुल बनकर तैयार हो जाता तो क्या होता? इससे भी बड़ा सवाल सरकार और नीति-निर्धारकों पर उठता है कि जिस कंपनी का पुल पहले बिहार में गिर चुका है, उसे ब्लैकलिस्ट करने के बजाय यूपी में दोबारा करोड़ों के टेंडर क्यों सौंप दिए गए? साफ है कि यहां जनता की सुरक्षा से ज्यादा महत्व कमीशनखोरी को दिया गया। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जनता के पैसे और उनकी जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा।

निकिता जोशी, कानपुर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं अकेले खाड़ी के देशों में। वे न केवल भारत में अपनी गाढ़ी कमाई भेजकर देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं, बल्कि वे विदेश में भारत के सांस्कृतिक राजदूत भी हैं।

श्री राम शा
shriramshaw@nda.jagran.com

आजकल

वैश्विक मंच पर उभरता भारत

हाल में संपन्न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों-यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा का एक जीवंत घोषणापत्र है। यह यात्रा भारत के लिए सामरिक सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने का एक ऐसा अवसर बनकर उभरी है, जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यूएई के साथ मिलकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति लाइन को सुरक्षित करता भारत। फाइल

वैश्विक राजनीति और अर्थनीति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां पुराने समीकरण बदल रहे हैं, और नए गठबंधनों का उदय हो रहा है। अमेरिकी विदेश नीति में आए बदलावों, रूस-यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचते संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया नए और भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है। ऐसे नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों - संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड्स, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा का एक जीवंत घोषणापत्र है। यह यात्रा भारत के लिए सामरिक सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने का एक ऐसा त्रिवेणी संगम बनकर उभरी है, जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पांच दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात था, जो वैश्विक तेल बाजार में आए भूचाल और अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण बेहद संवेदनशील समय पर हुआ। जब पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तब भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक मजबूत ढाल प्रदान की। यह तथ्य है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग दसवां हिस्सा यूएई से आयात करता है और वह यूएई की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का सबसे बड़ा खरीदार भी है।

इस यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौते भारत की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। 'इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड' और यूएई की 'एड्नाक' के बीच हुए समझौते के तहत यूएई भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में कच्चे तेल की आपूर्ति को बढ़ाकर तीन करोड़ बैरल करेगा। दोनों देशों ने भारत में रणनीतिक गैस रिजर्व स्थापित करने की संभावनाओं पर सहमति जताई, ताकि भविष्य में किसी भी वैश्विक आपूर्ति संकट से देश को बचाया जा सके। यूएई ने भारत में पांच अरब डालर (लगभग 41 हजार करोड़ रुपये) के नए निवेश की प्रतिबद्धता जताई, जो दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे 85 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा का अगला चरण यूरोप के नवाचार और तकनीक के गढ़-नीदरलैंड्स और स्वीडन की ओर था। वर्तमान समय में यूरोप चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहता है और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी रक्षा और ऊर्जा प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहा है। ऐसे में यूरोप भारत को एशिया में सबसे भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देख रहा है। नीदरलैंड्स की यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण तकनीकी क्षेत्र, विशेषकर सेमीकंडक्टर मिशन रहा। नीदरलैंड्स दुनिया की सबसे उन्नत लिथोग्राफी मशीनें बनाने वाली कंपनी एएसएमएल का घर है, जिसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण असंभव है। इस यात्रा के दौरान गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जो भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाने के सपने को साकार करेगा। दोनों देशों ने बैटरी, इलेक्ट्रानिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक 'क्रिटिकल मिनरल्स' (महत्वपूर्ण खनिजों) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समझौते किए। जल प्रबंधन और ग्रीन हाइड्रोजन में डच महारत का लाभ उठाने पर भी सहमति बनी।

गोटेबर्ग में स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के साथ हुई बैठक ने भारत-यूरोप संबंधों को नया आयाम दिया। भारत और स्वीडन के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर ले जाया गया। दोनों देशों ने 'संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0' और 'भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारिडोर' की शुरुआत की। अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का संकल्प लिया गया।

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचे। मोदी और मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक में भावी रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। भारत-इटली संयुक्त कार्य योजना 2025-29 इस साझेदारी को एक व्यावहारिक एवं भविष्योन्मुखी ढांचा प्रदान करती है। साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत-ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई। 2027 में 'इटली-इंडिया ईयर आफ कल्चर एंड टूरिज्म' मनाने की योजना का भी एलान किया, जिसका मकसद दोनों सभ्यताओं के लोगों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों की यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच भारत को लेकर एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा किया है। आज जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और मंदी का माहौल है, निवेशक अत्यधिक सतर्क हैं और पूंजी सुरक्षित स्थानों की तलाश में है, तब भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को आकर्षित करने में सफल रहा है। ज्ञात हो कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश केवल धन नहीं लाता, यह बिना ब्याज की ऐसी पूंजी है, जो देश में आधुनिक तकनीक लाती है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करती है और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करती है।

सामने आईं चीन की रणनीतिक सीमाएं

धीरज यादव
भू-राजनीति, रक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकार

हालिया वैश्विक संघर्षों ने दुनिया के सामने शक्ति संतुलन की एक नई तस्वीर पेश की है। जहां एक ओर अमेरिका ने ईरान की सैन्य शक्ति और नेतृत्व को भारी क्षति पहुंचाई है, वहीं दूसरी ओर खुद को सुपरपावर बताने वाले चीन की रणनीतिक निष्क्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की संतुलित कूटनीति कारगर साबित हो रही है। चीन का रणनीतिक साझेदार ईरान आज अपने इतिहास के एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है।

भौगोलिक रूप से भी दोनों देशों के बीच केवल पाकिस्तान है, इसके बावजूद, चीन न तो ईरान को आधुनिक हथियारों की पर्याप्त आपूर्ति कर पाया और न ही उसके सैन्य बलों को ठोस सैन्य प्रशिक्षण या रणनीतिक सहायता दे पाया। यह विफलता इसलिए अधिक चौंकाने वाली है, क्योंकि ईरान तथा अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध के संकेत पिछले वर्ष 12-दिवसीय लड़ाई से ही मिल गए थे और दोनों पक्षों के बीच शत्रुता दशकों पुरानी है। चीन के विपरीत अमेरिका हजारों मील दूर से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार वह 13000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले कर ईरान की कमर तोड़ चुका है।

अमेरिका ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व, सैन्य शक्ति और परमाणु ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई है। अमेरिका, इजरायल और अन्य खाड़ी देशों को भी नुकसान हुआ है, पर वह तुलनात्मक रूप से काफी कम है। यह सही है कि अमेरिका इस समय कई मोर्चों पर एक साथ उलझा हुआ है- जहां एक ओर वह ईरान के साथ युद्ध में फंसा है, वहीं दूसरी ओर क्यूबा की तेल नाकाबंदी कर रखी है और 2022 से यूक्रेन को निरंतर समर्थन भी दे रहा है। इसके बावजूद चीन ने ताइवान के एकीकरण के लिए किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से परहेज किया है। यह अमेरिका और चीन की सैन्य क्षमताओं के बीच बड़े अंतर को दर्शाता है। यह चीन की उस छवि को धूमिल करता है जिसमें उसे अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था।

अमेरिका एक-एक करके चीन के सहयोगी देशों को परास्त कर एवं उनमें सत्ता परिवर्तन कर अपने सहयोगियों में बदल रहा है। अन्य देश देख रहे हैं कि चीन के हथियारों और उसकी रणनीतिक साझेदारी पर भरोसा करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इससे साफ हो रहा कि अब वे अमेरिकी एवं यूरोपीय हथियार ज्यादा खरीदेंगे और हर परिस्थिति में अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ब्रिक्स सदस्य और कच्चा तेल उत्पादित करने वाले खाड़ी देश भी डी-डालराइजेशन जैसी किसी पहल का समर्थन करने से कतराएंगे।

इस समय भारत की राष्ट्रहित सर्वोपरि की नीति अत्यंत तर्कसंगत है- अमेरिका से अनावश्यक टकराव नहीं, लेकिन जहां राष्ट्रहित हो वहां दृढ़ता से खड़े रहना है। भारत ने अमेरिकी सैन्य कारवाई की खुली आलोचना नहीं की, परंतु साथ ही ईरान के युद्धपोत आइआरआइएस लवान को कोच्चि में शरण दी और उसके 100 से अधिक नौसैनिकों को अर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित वापस भी भेज दिया। इस संतुलित नीति का ही परिणाम है कि आज भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं और ईरान ने भी 18 अप्रैल को हार्मुज जल मार्ग को दोबारा बंद करने से पहले जिन गिने चुने मित्र देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी उनमें भारत भी शामिल था। यह भारत की संतुलित विदेश नीति का प्रमाण है।

भारत अब संतुलित कूटनीति से अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है यही रणनीतिक स्वायत्तता है और यही भारत को भविष्य में एक बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रही है।

खरी-खरी

झालमूड़ी-मेलोडी संवाद

डा. प्रदीप मिश्र

एक दिन झालमूड़ी ने मेलोडी को तीखी जुबान में हड़काया, 'क्यों री! आजकल तू कुछ ज्यादा इतरा रही है? फारेन क्या हो आई, तेरे भाव ही नहीं मिल रहे हैं? दूकानों में तू आउट आफ स्टाक हो गई है। देख मूलतः तू मीठी-गोली है। लोगों ने तुझे टाफी क्या कह दिया, तू खुद को चाको-लावा केक समझने लगी? बिन्नो जरा पांव-पांव चल।'

'मैंने ऐसा क्या किया जिज्जी? मेरा स्वाद तो आपके बाद आता है...पहले तीखा फिर मीठा। तीखे के बिना मीठे को कौन पूछे? आपका दिव्य स्वाद शरीर को झंकृत करने में समर्थ होता है। मैं तो अपनी मिठास से आपकी झनझनाहट को शांत करती हूं।' मेलोडी की जुबान में मिठास घुली थी।

'तू मुझ पर तीखेपने का लेबल चिपकाने का षड्यंत्र कर रही है।' झालमूड़ी झल्लाई। मेलोडी मुस्काई, 'आपके तो नाम में ही स्वाद जैसा तीखापन है। मेरे नाम में मेरे स्वाद की मिठास है।'

'तेरी मिठास, मिठास नहीं महामारी है। फैलाती शक्कर की बीमारी है। तू फैशनबाजों की लाचारी है। जबकि जमीनी लोगों की पसंद झालमाड़ी है।' झालमूड़ी ने आरोपों की झड़ी लगाई। मेलोडी मीठी तो थी, लेकिन जवाब देने में मुंह तोड़ थी, 'ये सारी बातें घात और प्रतिघात हैं। डाक्टर अपने मरीज से पहले मिर्च-मसाला ही छुड़वाते हैं। तुझे खाकर जब अच्छे-अच्छे तीखाड़ू जब सिसियाते हैं, तब मेलाडी को ही मुंह लगाते हैं।'

'ये बता क्या है तेरा बायोडाटा? तूने कितनों को कितने चुनाव जितवाए हैं? मैं हूं देसी, लेकिन मेरा इफेक्ट है बड़ा विशेषी। दस रुपये में मुझे खरीदो। मेरे संग सेल्फी खिंचाओ और प्रचंड बहुमत से कुर्सी का सुख पाओ।'

'पर जिज्जी तुझे कोई किसी को गिफ्ट कर सकता है क्या? तू है लोकल, मैं हूं ग्लोबल। तेरे पास जनबल तो मेरे पास मिठास का मनोबल। मैंने संभाले हैं देशों से रिश्ते, तुझे खाकर लोग पानी को तरसते। छोड़ जिज्जी आपस के झगड़े। अपने-अपने क्षेत्र में हम दोनों ही हैं तगड़े?' मेलोडी ने बातों में मिठास घोली। अब झालमूड़ी भी स्वाद तो नहीं, लेकिन मन से मीठी हो चुकी थी।

पोस्ट

भारतीय इतिहास, राजनीति पर शोध करने वाले अधिकांश पश्चिमी शिक्षाविद शोधार्थी नहीं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं।
अभिनव प्रकाश@Abhina_Prakash

पाठ्यक्रम और परीक्षा के बीच अंतर की भरपाई करने वाले तंत्र का नाम ही कोचिंग है। सरकार इस गैप को भर दे तो कोचिंग का क्या काम? लिहाजा कोचिंग वाले टीचर्स को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला, सिस्टम में सुधार चाहते हैं तो दबाव नीति निर्धारकों पर बनाइए।
मधुरेंद्र कुमार@Madhurendra13

यह बात सोलह आने सच है कि टीवी पत्रकारों वाली बीमारी आनलाइन अध्यापकों को भी लग गई और वह बीमारी है लोकप्रियता का रोग। जबकि सही बात अलोकप्रिय भी होती है। वायरल के मोह से आगे बढ़ना ही होगा। तमाशा पत्रकारिता का विकल्प तमाशा शिक्षा नहीं। संकेत उपाध्याय@sanket

तमिलनाडु में अन्नामलाई को किनारे करके भाजपा सही नहीं कर रही। वैसे, यह पहली बार नहीं है जब पार्टी में अपनी प्रतिभाओं को उपेक्षित और दोयम दर्जे के बाहरी नेताओं को उपकृत किया जा रहा हो।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या अमेरिका-ईरान के बीच कायम युद्धविराम खतरे में पड़ता दिख रहा है?

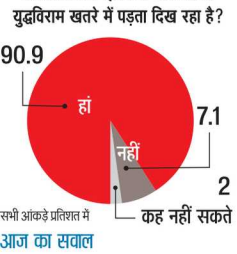

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने से तमिलनाडु में भाजपा की राह और मुश्किल होगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

साईं कबहुं न कीजिए 'इतने बढ़िया' काम,
हेलमेट में चलना पड़े हो करके बदनाम।
हो करके बदनाम लोग बरसाएं अंडे,
दौड़ाएं कुछ लोग हाथ में लेकर डंडे!
करि मनमाना काम स्वयं हित खोदे खाईं,
अब तो मालिक राम बचाएं 'उनको' साईं!!
-ओम प्रकाश तिवारी

उत्तराखंड डायरी

जीत की हैटट्रिक लगाने की चुनौती

रविंद्र बड़थ्वाल
उत्तराखंड राज्य ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में वर्ष 2017 का प्रदर्शन दोहराने का लक्ष्य रखा गया है। यानी विधानसभा सीटों की संख्या 47 से वापस 57 तक पहुंचाना भाजपा की धामी सरकार और प्रदेश संगठन के लिए नवीन टास्क है। विभिन्न प्रदेशों में बहुमत को प्रचंड बहुमत में बदलने में भाजपा को जिस प्रकार सफलता मिल रही है, पार्टी को इससे नया हौसला मिला है। बंगाल और असम में मिले प्रचंड बहुमत के बाद उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में भी भाजपा इसी प्रकार सांगठनिक कौशल में हाथ आजमाने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे में बेहद सतर्कता से आगामी चुनाव में जीत की हैटट्रिक के लिए व्यूह रचना तैयार की। विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के फार्मूले को जमीन पर उतारने का दारोमदार विधायकों से लेकर सांसदों पर भी होगा। उनका प्रदर्शन आंकने का यह आधार बनेगा।

उत्तराखंड की रणभूमि में एक और प्रयोग आजमाने की तैयारी है। समान नागरिक संहिता, मदरसा बोर्ड समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, बलवाइयों से संपत्ति क्षति की वसूली, मतांतरण पर सख्ती, धार्मिक प्रतीक चिह्नों की आड़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खेल पर शिकंजा कसने समेत अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के विरुद्ध मजबूत कानूनी आवरण तैयार करने का प्रयोग उत्तराखंड में सफल रहा है। सनातन और हिंदुत्व की भावभूमि में खड़ा किया गया यह माडल अन्य प्रदेशों के लिए अब मिसाल है। अन्य प्रदेशों में भी जनता ने इस माडल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। इससे उत्साहित भाजपा ने प्रदेश में जीत के अंतर को भारी से प्रचंड बहुमत में बदलकर हैटट्रिक लगाने को अपना अगला मिशन बनाया है। इसके लिए जमीन तैयार करने में ताकत झोंकी जा रही है।

वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। फाइल

राज्य के अगले चुनावी महासमर में उन सभी हथियारों का प्रयोग होने जा रहा है, जिनके बूते भाजपा ने अब तक अपनी विजय यात्रा को प्रचंड जीत में बदला है। बंगाल में विपरीत परिस्थितियों को लगातार सक्रियता और संघर्ष के बूते अपने पक्ष में करने में पार्टी को बड़ी सफलता मिली। वहीं असम में हैटट्रिक के लिए जमीनी तैयारी से लेकर आक्रामक रणनीति का कमाल देखने को मिला। देवभूमि का मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड सनातन को लेकर भाजपा की राजनीति के सशक्त केंद्र के रूप में उभरा है।

केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रहते हुए उत्तराखंड में वर्ष 2027 में लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव होगा। इस चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की गंभीरता का अंदाजा इससे लग सकता है कि चुनावी वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही शंखनाद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं यहां आ चुके हैं। भाजपा के नए अध्यक्ष ने राज्य में चुनाव की तैयारियों के लिए पूरे तीन दिन का समय निकाला। जीत का दायरा व्यापक करने की इच्छाशक्ति मजबूत करने के लिए उन्होंने सरकार से लेकर संगठन में हर स्तर पर जिम्मेदारियां तय कीं। अगला चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पर भी मुहर लगा दी। विधायकों, सांसदों और सरकार के बीच किसी भी प्रकार के मनमुटाव दूर करने को नितिन नवीन की प्राथमिकता का अंदाजा इससे लग सकता है कि उनके देहरादून में रहते हुए ही ऊधम सिंह नगर के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडेय गिले-शिकवे भुलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इसके बाद से संगठन की एकजुटता को लेकर उनके बयान इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। सांसदों की जवाबदेही बढ़ाकर उसे हारी हुई सीटों पर जीत तक ले जाने के लिए साफ-साफ निर्देश दिए गए हैं। विधायकों के साथ सांसदों को विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करना सुनिश्चित किया गया है।

विशेष रूप से हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर सांसदों के कौशल को परखा जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास मात्र तीन ही हैं, जबकि वर्ष 2017 में भाजपा की झोली में आठ सीट आई थीं। 2022 में नैनीताल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ऊधम सिंह नगर जिले की नौ में से पांच सीटें कांग्रेस को मिलीं, जबकि भाजपा को चार सीट पर संतोष करना पड़ा। वर्ष 2017 में इसी जिले में भाजपा को नौ में से आठ सीटें हासिल हुई थीं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में भी भाजपा का प्रतिनिधित्व 2017 की भांति बढ़ाने की चुनौती है।

मंथन

बेचैन युवा भारत की अभिव्यक्ति

आज राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा इंटरनेट मीडिया पर आकार ले रहा है। जनमत अब इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शार्ट्स, एक्स पोस्ट और वायरल मीम्स के जरिये भी निर्मित हो रहा है

डा. महुआ माजी
सदस्य, राज्यसभा

भारतीय लोकतंत्र आज एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यह परिवर्तन केवल संसद या चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की मानसिक संरचना, संवाद की प्रकृति और जनमत निर्माण की प्रक्रिया तक फैल चुका है। आज राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा इंटरनेट मीडिया पर आकार ले रहा है। जनमत अब पारंपरिक माध्यमों से आगे बढ़कर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शार्ट्स, एक्स पोस्ट, वायरल मीम्स के जरिये निर्मित हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में ''काकरोच जनता पार्टी'' जैसी अचानक उभरी लोकप्रियता को सिर्फ डिजिटल ट्रेंड मान खारिज नहीं किया जा सकता। यह उस बेचैन युवा भारत की अभिव्यक्ति है, जो स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है।

समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो जब किसी समाज की मुख्य संस्थाएं-राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और मीडिया जनभावनाओं से दूरी बनाने लगती हैं, तब नए प्रतीक और नई राजनीतिक भाषाएं जन्म लेती हैं। कई बार ये प्रतीक व्यंग्य के रूप में सामने आते हैं, लेकिन इनके भीतर गहरी सामाजिक पीड़ा और असंतोष छिपा होता है। ''काकरोच जनता पार्टी'' इसी डिजिटल युग का एक ऐसा ही सांकेतिक प्रतिरोध है। काकरोच एक ऐसा जीव है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह जाता है। यह प्रतीक आज के उस युवा मानस को आकर्षित करता है, जो बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक दबाव के बीच किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। आंकड़े बताते हैं युवाओं में बेरोजगारी की दर औसत से अधिक बनी हुई है। लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं या तो विलंबित होती हैं या विवादों में उलझ जाती हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक असंतोष का कारण बन रही है।

आज का युवा केवल रोजगार नहीं चाहता, वह सम्मानजनक भागीदारी चाहता है। वह यह महसूस करना चाहता है कि लोकतंत्र में उसकी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन जब उसे मंचों पर केवल औपचारिक आश्वासन और इंटरनेट मीडिया पर केवल प्रचार दिखाई देता है, तब वह अपनी अभिव्यक्ति के नए माध्यम खोजता है। वर्तमान चुनावी परिदृश्य में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हो गई है। चुनाव अब केवल मतदान केंद्रों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़े जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के डिजिटल अभियान, आइटी सेल और इंटरनेट मीडिया रणनीतियां जनमत निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इस डिजिटल राजनीति के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार अनुत्तरित है-क्या हम वास्तव में युवा भारत की मूल चिंताओं को समझ पा रहे हैं? आज का युवा पहले की तरह केवल परंपरागत राजनीतिक निष्ठाओं से बंधा नहीं है। वह प्रश्न पूछता है, तुलना करता है, तथ्य जांचता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इंटरनेट मीडिया ने उसे अभूतपूर्व अभिव्यक्ति की शक्ति दी है। यह लोकतंत्र के विस्तार का भी संकेत है और उसकी नई चुनौती भी।

इंटरनेट मीडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाया है। छोटे शहरों और दूरदराज क्षेत्रों के युवा भी अब राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं। जो आवाजें पहले अनसुनी रह जाती थीं, वे अब सीधे लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और सामाजिक अन्याय पर तुरंत प्रतिक्रिया संभव हुई है। यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी गंभीर है। इंटरनेट मीडिया ने राजनीति को अत्यधिक तात्कालिक और भावनात्मक बना दिया है। अब विचारों की गहराई से अधिक उनकी वायरल क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। कई बार नीतिगत बहसें पीछे छूट जाती हैं और प्रतीकात्मक राजनीति आगे बढ़ जाती है। एल्गोरिदम आधारित इस व्यवस्था में वही सामग्री अधिक फैलती है, जो उत्तेजना पैदा करे। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण और वैचारिक टकराव बढ़ता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि युवाओं की वास्तविक समस्याएं कहीं डिजिटल मनोरंजन में न बदल जाएं। बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, अवसरों की असमानता और भविष्य की अनिश्चितता जैसे गंभीर प्रश्न कई बार मीम संस्कृति में सीमित हो जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है।

जब संवाद कमजोर होता है, तब प्रतिरोध असामान्य रूप ले लेता है। इंटरनेट मीडिया युग में यह प्रवृत्ति और तेज हुई है, क्योंकि यहां प्रतिक्रिया तत्काल मिलती है, लेकिन समाधान नहीं। राजनीतिक दलों के लिए यह समय आत्ममंथन का है। यदि युवा व्यंग्यात्मक प्रतीकों और डिजिटल आंदोलनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति खोज रहा है तो यह संकेत है कि मुख्यधारा की राजनीति उसके विश्वास को पूरी तरह जीत नहीं पाई है। केवल प्रचार और नारों से यह दूरी कम नहीं होगी। इसके लिए रोजगार, शिक्षा, पारदर्शिता और वास्तविक सहभागिता को केंद्र में लाना होगा।

प्रतीकात्मक

बिजनेस

बाटलिंग सब्सिडियरी का आइपीओ ला सकती है कोका कोला

नई दिल्ली : वैश्विक बेवरेज दिग्गज कोका कोला कंपनी अपने भारत स्थित बाटलिंग सब्सिडियरी हिंदुस्तान कोका कोला हॉल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीसीएच) का अगले वर्ष आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एचसीसीएच में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने पर भी विचार कर रही है। कोका कोला ने करीब एक वर्ष पहले एचसीसीएच में अपनी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी जुबिलेंट भरतिया समूह को बेची थी। हालांकि, अभी तक इसका वित्तीय विवरण सामने नहीं आया है। (प्रेट्र)

भारत आयातित तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में ओमान के साथ व्यापार समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
– शिशिर प्रियदर्शी, प्रेसिडेंट, सीआरएफ

सेंसेक्स	74,649.84 ▲ 382.50	निफ्टी	23,483.55 ▲ 100.95	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,61,450 ▲ ₹ 1,050	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,71,000 ▲ ₹ 1,300	$ डालर	₹ 95.36 ▲ ₹ 0.17	कूड प्रति बैरल	$ 93.76

एक नजर में

आइटी शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स 382 अंक बढ़ा

नई दिल्ली : आइटी शेयरों की खरीदारी की बदौलत लगातार चार दिन से गिरावट का सामना कर रहा सेंसेक्स मंगलवार को 382.50 अंक बढ़कर 74,649.84 के स्तर पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान इसमें 1,047.07 अंक का उतार-चढ़ाव रहा। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 100.95 अंक की तेजी के साथ 23,483.55 अंक पर जाकर बंद हुआ।

ओयो को सेबी से मिली आइपीओ लाने की मंजूरी

नई दिल्ली : ट्रेवल टेक्नोलाजी प्लेटफार्म ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म को कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कंपनी आइपीओ के जरिये 6,650 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। कंपनी के 7-8 अरब डालर के मूल्यांकन पर यह राशि जुटाई जा सकती है। (प्रेट्र)

केंद्र सरकार ने चांदी आयात पर और सख्ती बढ़ाई

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चांदी आयात को लेकर मंगलवार को सख्ती और बढ़ा दी। अब केवल आरबीआइ द्वारा नामित एजेंसियां, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अनुमोदित संस्थाएं और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से योग्य जौहरी ही वैध प्रमाणन के जरिये चांदी का आयात कर सकेंगे। (प्रेट्र)

केंद्र ने बोर्ड आफ ट्रेड में 29 सदस्य नामित किए

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने बोर्ड आफ ट्रेड में 29 गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है। इसमें एसबीआइ के चेयरमैन सीएस शेट्टी, एपल इंडिया के प्रबंध निदेशक विराट भाटिया और महिंद्रा के प्रबंध निदेशक अनीश शाह प्रमुख हैं। इस बोर्ड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। (प्रेट्र)

रुपये की गिरावट थामने पर होगी बाजार की नजर

आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से, गवर्नर पांच जून को देंगे फैसलों की जानकारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक आज शुरू होगी। समिति के फैसलों की जानकारी पांच जून को दी जाएगी। इसमें विशेषज्ञों और बाजार की नजर ब्याज दरों (रेपो रेट) से ज्यादा रुपये की स्थिरता को लेकर केंद्रीय बैंक की भावी रणनीति पर होगी। आरबीआइ का अभी तक स्पष्ट रुख है कि वह रुपये को किसी खास स्तर पर रोकने का पक्षधर नहीं है, बल्कि केवल अत्यधिक अस्थिरता और भारी गिरावट को रोकने के लिए ही वह हस्तक्षेप करेगा। गवर्नर मल्होत्रा ने पहले कहा भी है कि किसी बैंड या स्तर को लक्षित करने के लिए उनकी नीति नहीं होगी।

समाचार एजेंसी प्रेट्र के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, एमपीसी की आगामी बैठक में ब्याज दरों को प्रभावित करने वाले बेंचमार्क रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने की संभावना है। सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर अर्थशास्त्रियों और ट्रेजरी प्रमुखों का मानना है कि केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 2027 के अंत में महंगाई के बढ़ते जोखिम को देखते हुए बाद में सख्त नीति शुरू कर सकता है। एसबीआइ व कुछ अन्य आर्थिक एजेंसियों की रिपोर्ट भी यह बताती है कि चूंकि महंगाई की दर अभी आरबीआइ के लक्षित बैंड (चार प्रतिशत) के करीब है, इसलिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं करेगा।

जेपी मार्गन के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन हाल में रुपये की लगातार कमजोरी को देखते हुए आरबीआइ महंगाई नियंत्रण और रुपये की अस्थिरता को अलग-अलग नजरिए से देखेगा। यानी ब्याज दरों का इस्तेमाल आर्थिक विकास और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा और रुपये की स्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री या कुछ दूसरी नीतियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई अर्थविदों ने तमाम आलेखों के जरिए कहा है कि रुपये की कमजोरी से महंगाई की स्थिति धीरे-धीरे ज्यादा खराब हो सकती है। लिहाजा ब्याज दरों को लेकर अभी से सोचने की जरूरत है।

एसबीआइ व क्रिसिल ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्टों में यह बताया है कि किस तरह से रुपये की कमजोरी से भारत में इलेक्ट्रानिक्स, ईंधन, प्लास्टिक, दवाइयों के कच्चे माल आदि महंगे हो गए हैं जिसका असर धीरे-धीरे आम जनता की जेब पर पड़ेगा। असल में पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद एशिया के अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले डालर की तुलना में भारतीय रुपये की गिरावट ज्यादा तेज रही है।

वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक रुपये 7.5 प्रतिशत तक कमजोर हो चुका है। मई 2026 में एक समय रुपया 96-97 प्रति डालर के रिकार्ड निचले स्तर के करीब पहुंच चुका है। अभी यह 95 के आसपास है। रुपये को संभालने के लिए आरबीआइ ने सिर्फ मई माह में पांच अरब डालर-रुपया क्रय-बिक्री स्वैप जारी किया है। इसके तहत बैंक आरबीआइ को डालर देते हैं और फिर इसके बदले उन्हें रुपया दिया जाता है। इससे पहले मार्च 2026 में आरबीआइ ने 29.6 अरब डालर की बिक्री की थी। इस बिक्री से विदेशी मुद्रा भंडार मई के अंत में 681.4 अरब डालर रह गया है, जो एक साल का निचला स्तर है।

- विशेषज्ञों का अनुमान, अपरिवर्तित रखा जा सकता है रेपो रेट
- महंगाई को ध्यान में रखकर फैसले कर सकती है एमपीसी

7.5 प्रतिशत तक कमजोर हो चुकी है भारतीय मुद्रा वर्ष 2026 में अभी तक

96-97 प्रति डालर के करीब पहुंच चुका है रुपया मई की शुरुआत में

भारत में घरों और मंदिरों में बड़ी मात्रा में सोना रखा हुआ है। इसके बावजूद देश जरूरत का अधिकांश सोना विदेश से आयात करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा पर दबाव को देखते हुए नागरिकों से एक वर्ष तक सोने की गैर-जरूरी खरीद टालने की अपील की। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब देश के पास पहले से ही हजारों टन सोना मौजूद है, तो इसको बाहर निकालकर अर्थव्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं बनाया जा सकता। आइए जानते हैं भारत में मौजूद सोने की स्थिति और विशेषज्ञों की राय...

30-32 हजार टन सोना है भारतीय परिवारों और मंदिर ट्रस्टों के पास

35,000 टन तक हो सकती है परिवारों-मंदिर ट्रस्टों के सोने की मात्रा

3.8 ट्रिलियन डालर के करीब है देश में रखे सोने का अनुमानित मूल्य

72.4 अरब डालर रहा वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सोने का आयात बिल

क्या है गोल्ड रिसाइक्लिंग

इसके तहत पुराने आभूषण, टूटे गहने, सिक्के, सोने की बिस्कुट, औद्योगिक स्क्रैप और इलेक्ट्रानिक उपकरणों से प्राप्त सोने को दोबारा शुद्ध कर उपयोग के योग्य बनाया जाता है। इसके तहत सबसे पहले सोने की शुद्धता जांची जाती है। फिर इसे पिघलाया जाता है। पिघलाए जाने के बाद इसे 99.9 प्रतिशत तक शुद्ध बनाया जाता है। इसके बाद नए आभूषण, सिक्के और अन्य सराफा उत्पाद बनाए जाते हैं।

सरकार क्यों दे रही रिसाइक्लिंग पर जोर

भारत अपनी सोना जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से निष्क्रिय सोने को औपचारिक आर्थिकी में लाने का प्रयास कर रही है। इससे घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सकता है।

सरकार को म्यूचुअल फंड की गोल्ड योजनाओं में निवेश पर एक-दो वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि इनमें निवेश काफी बढ़ गया है और यह योजनाएं 100 प्रतिशत भौतिक सोने से समर्थित रहती हैं। इसके अलावा रिसाइक्लिंग पर सब्सिडी एवं रिसाइक्लिंग सर्टिफिकेट देकर सरकार नागरिकों को प्रोत्साहित कर सकती है। – **डीडी शर्मा,** प्रबंध निदेशक, एमएफ किंग

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि घरों और मंदिरों में मौजूद कुल सोने का केवल एक प्रतिशत हिस्सा भी हर वर्ष रिसाइक्लिंग के लिए लाया जाए तो भारत का सोना आयात 25 से 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। कुछ आकलनों में यह कमी 33 प्रतिशत तक बताई गई है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जागरण रिसर्च

थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर 2022-23 किया

डब्ल्यूपीआइ को धीरे-धीरे उत्पादक मूल्य सूचकांक में बदला जाएगा, नए आधार वर्ष के तहत 15 जून को जारी होगा डाटा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वस्तुओं व अन्य सेवाओं के थोक मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी के व्यापक एवं उचित मूल्यांकन के लिए अब थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआइ) की शुरुआत की जा रही है। हालांकि, अभी अगले पांच साल तक डब्ल्यूपीआइ जारी किया जाएगा और उसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल डब्ल्यूपीआइ के आधार वर्ष में बदलाव करते हुए इसे 2011-12 की जगह 2022-23 कर दिया गया है। 15 जून को नए आधार वर्ष पर डब्ल्यूपीआइ जारी किया जाएगा। इसके साथ पहली बार पीपीआइ भी जारी होगा।

डब्ल्यूपीआइ के व्यापक उपयोग को देखते हुए संशोधित श्रृंखला के जारी होने की तारीख से पांच वर्षों तक पीपीआइ के साथ यह सूचकांक जारी किया जाएगा। उद्योग विभाग के मुताबिक डब्ल्यूपीआइ से पीपीआइ में यह परिवर्तन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गए वैश्विक सर्वोत्तम तरीके और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिश के अनुरूप है। इनपुट (कच्चे माल) और आउटपुट (अंतिम उत्पाद) दोनों पीपीआइ जारी किए जाएंगे। इससे यह पता लग सकेगा कि इनपुट के मूल्य में बढ़ोतरी का कैसे अंतिम उत्पाद के मूल्य बढ़ोतरी पर असर पड़ता है। नए आधार वर्ष में वस्तुओं की संख्या को 697 से बढ़ाकर 957 कर दिया गया है। बैंकिंग, प्रतिभूति लेनदेन, बीमा, पेंशन निधि प्रबंधन, रेलवे, हवाई यात्रा के पीपीआइ भी 15 जून को जारी किए जाएंगे।

ब्रिटेन से व्यापार समझौते पर अमल जल्द

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ओमान के साथ व्यापार समझौते पर अमल के बाद जल्द ही ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीटा) पर अमल हो सकता है। इसको लेकर मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार व वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि भारत ने स्टील को लेकर ब्रिटेन के रुख पर चिंता जाहिर की है।

वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अगर ब्रिटेन भारतीय स्टील के निर्यात को लेकर अपने बाजार को पूरी तरह नहीं खोलता है और शुल्क में पूरी रियायत नहीं देता है तो भारत भी ब्रिटेन से आने वाली विभिन्न वस्तुओं के शुल्क में दी गई रियायत को कम कर सकता है। इसमें ब्रिटेन से आने वाली स्काच के अलावा अन्य वस्तुएं भी शामिल हो सकती है। ब्रिटेन भारत से स्टील आयात पर शुल्क में पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहता है ताकि वह घरेलू उद्योग की रक्षा कर सके। वहीं भारतीय स्टील के आयात को लेकर कोटा भी निर्धारित किया जा रहा है।

सीटा के तहत भारत ने ब्रिटेन के स्काच पर लगने वाले शुल्क को 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया है जो अगले दस साल में 40 प्रतिशत हो जाएगा। व्यापार समझौते पर वार्ता के दौरान ब्रिटेन ने भारतीय बाजार में स्काच बेचने के लिए शुल्क में कमी पर खासा जोर दिया था। दोनों देशों के बीच सीटा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अगले एक-दो महीनों में इस पर अमल शुरू हो सकता है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार भारत से छोटा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 40,000 डालर से अधिक होने की वजह से यहां के लोगों की क्रय शक्ति अधिक है। इसलिए सीटा पर अमल के बाद ब्रिटेन में भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा।

- दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने समझौते के अमल को लेकर चर्चा की
- स्टील आयात को लेकर ब्रिटेन के सख्त रुख पर भारत ने चिंता जताई

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

महाराष्ट्र सरकार ने नरीमन प्वाइंट स्थित एअर इंडिया भवन का किया अधिग्रहण

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

- यह इमारत देश की राष्ट्रीय विमानन महत्वाकांक्षाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिष्ठा का बनी प्रतीक

मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित प्रतिष्ठित एअर इंडिया भवन अब औपचारिक रूप से महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व में आ गया है। यह अधिग्रहण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मंत्रालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित यह इमारत देश की राष्ट्रीय विमानन महत्वाकांक्षाओं व सार्वजनिक उपक्रमों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बनी रही।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच "डीड आफ सरेंडर" पर हस्ताक्षर प्रक्रिया की अध्यक्षता की। करीब 1,601 करोड़ रुपये के इस सौदे को केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में मंजूरी दी थी, जबकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नवंबर 2025 में इसे अंतिम स्वीकृति प्रदान की थी। अरब सागर के किनारे स्थित प्रसिद्ध मरीन ड्राइव (क्वीन्स नेकलेस) के सामने खड़ी 23 मंजिला यह इमारत पिछले पांच दशकों से अधिक समय से मुंबई की पहचान का हिस्सा रही है। देश के पहले केंद्रीय व्यावसायिक जिले नरीमन प्वाइंट के हृदय स्थल में स्थित यह भवन कभी एअर इंडिया के मुख्यालय के रूप में जाना जाता था और नागरिक उड्डयन के स्वर्णिम दौर में प्रमुख विमानन कंपनी की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यह अधिग्रहण केवल एक रियल एस्टेट सौदा नहीं, बल्कि मुंबई के बदलते आर्थिक और संस्थागत परिदृश्य का भी द्योतक है। महाराष्ट्र सरकार इस भवन का उपयोग उन विभागों व कार्यालयों के लिए करेगी, जो वर्तमान में मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इससे न केवल किराये पर होने वाला नियमित खर्च कम होगा, बल्कि मंत्रालय और विधान भवन के निकट विभिन्न विभागों के एकत्र होने से प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।

दो हजार करोड़ की धोखाधड़ी में अर्थ ग्रुप के चार निदेशक दोबारा किए गए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप, ईडी ने पांच दिन के रिमांड पर लिया
- चारों निदेशकों को पहले दिल्ली पुलिस भी कर चुकी है गिरफ्तार

एनसीआर समेत लुधियाना और लखनऊ जैसे कई बड़े शहरों में हाउसिंग और कामर्शियल प्रोजेक्ट लांच कर 19,425 खरीदारों से 2004 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के चार शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने सोमवार को कंपनी के चार प्रमोटर्स व निदेशक अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश कर गहन पूछताछ के लिए पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है।

ईडी ने चारों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज पांच एफआइआर के आधार पर शुरू हुआ है। जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने चारों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद इन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन अब ईडी ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया है। यह मामला भले नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में चला गया हो लेकिन 18 महीने में खत्म होने वाली प्रक्रिया छह साल में भी खत्म नहीं हो पाई है। वर्षों से यह मामला अधर में लटका होने के कारण किसी को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। खरीदार वर्षों से न्यायालयों के ही चक्कर काट रहे हैं। ईडी और ईओडब्ल्यू के अलावा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) ने भी अर्थ ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबी : ईडी की जांच में सामने आया है कि अर्थ ग्रुप ने आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की समय पर डिलीवरी और निश्चित रिटर्न का वादा करके 19,425 से अधिक खरीदारों और निवेशकों से लगभग 2004 करोड़ रुपये जुटाए थे।

अप्रैल में एनसीआर में मारे गए थे छापे

बीते अप्रैल में ईडी ने एनसीआर में अर्थ ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। उस कार्रवाई में 6.30 करोड़ रुपये कैश, 8.78 करोड़ रुपये के गहने और 100 से अधिक अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिनकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

हवा से मार करने वाली मिसाइल रुद्र एम-2 का सफल परीक्षण

जागरण संवाददाता, बालेश्वर

- मिसाइल की रेंज लगभग 350 किमी, लक्ष्यों पर अत्यंत सटीकता के साथ किया प्रहार

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र एम-2 का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान प्रक्षेपित की गईं सभी मिसाइलों ने पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों पर अत्यंत सटीकता के साथ प्रहार किया। परीक्षण रेंज में तैनात उन्नत ट्रैकिंग व रेंज उपकरणों से प्राप्त उड़ान आंकड़ों ने पुष्टि हुई कि परीक्षण के सभी निर्धारित उद्देश्य सफलतापूर्वक और पूर्ण रूप से हासिल कर लिए गए। इस मिसाइल की रेंज 350 किमी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र एम-2 के सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों व उद्योग जगत के सभी सहयोगियों को बधाई दी। कहा कि इन परीक्षणों ने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता, विश्वसनीयता व क्षमता को प्रदर्शित किया है। यह उपलब्धि उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी व रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भूमिका निभाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने परीक्षण से जुड़ी सभी वैज्ञानिक, तकनीकी व परिचालन टीमों को बधाई दी।

ओडिशा के चांदीपुर में रुद्र एम-2 मिसाइल के परीक्षण का दृश्य। स्रोत: डीआरडीओ

मृत मरीजों के नाम पर दवाइयां खरीदने में तीन बर्खास्त, एक निलंबित

जागरण संवाददाता, लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ने भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और मृत मरीजों के नाम पर दवाइयां खरीदने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। संस्थान प्रशासन ने यूरोलाजी विभाग में असाध्य रोग के इलाज व धांधली के मामले में तीन संविदा कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक चीफ फार्मासिस्ट को निलंबित कर उनके और एक डाक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

डाक्टर को छोड़कर अन्य चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। सभी से रिकवरी भी की जाएगी। विभागाध्यक्ष अपुल गोयल को हटा दिया गया है। प्रो. गोयल की जगह जनरल सर्जरी विभाग के प्रो. एचएस पहवा को कार्यवाहक विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

10वीं फेल युवक ने ठग लिए यूपी-बिहार के पुलिस अफसर

जागरण संवाददाता, बागपत

लालमोहन राय

पुलिसकर्मियों पर करता था रौब, आरोपित बिहार का मूल निवासी, दो अन्य साथियों की तलाश

10वीं फेल एक युवक लाल मोहन राय ने यूपी व बिहार के 20 पुलिस अधिकारियों को आनलाइन ठगी कर चूना लगाया। बागपत में चौकी इंचार्ज से 25 हजार रुपये की ठगी करने के बाद आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मूल रूप से बिहार का रहने वाला आरोपित वर्तमान में फरीदाबाद में रह रहा था। पुलिस उसके दो साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

बागपत चौकी इंचार्ज अमित कुमार से एसपी क्राइम बताकर अज्ञात व्यक्ति ने 25 हजार रुपये की आनलाइन ठगी की थी। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। साइबर थाने के इंस्पेक्टर संत शरण सिंह के मुताबिक विवेचना में बिहार के मोतिहारी के थाना लखौरा के गांव लक्ष्मीपुर कटहारिया के मूल निवासी लाल मोहन राय का नाम प्रकाश में आया। वह वर्तमान में परिवार के साथ फरीदाबाद रह रहा था। दिखाने के लिए वह प्राइवेट बस बुकिंग का काम करता था। पूछताछ में उसने बताया कि वह 10वीं फेल है। उसने अपने साथी अजय चौबे निवासी गोपालगंज, बिहार और विकास के साथ मिलकर बिहार के जमुई के सिमुलतला थाना प्रभारी रूबी कुमारी से 50 हजार ठगे। सिद्धार्थनगर के मोहाना चौकी इंचार्ज सुदीप कुमार यादव से 30 हजार रुपये की ठगी की।

इंडिगो 31 अगस्त से बंद कर देगी मैनचेस्टर के लिए उड़ानें

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडिगो ने बढ़ती परिचालन लागत और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 31 अगस्त से मैनचेस्टर के लिए अपनी उड़ानें बंद करने की मंगलवार को घोषणा की। इस निर्णय के बाद, एयरलाइन कंपनी लीज पर लिए गए बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान को नार्स अटलांटिक एयरवेज को वापस कर देगी। इस समय इंडिगो दिल्ली और मुंबई से मैनचेस्टर (ब्रिटेन) के लिए उड़ानें संचालित करती है।

एयरलाइन ने बयान में कहा, लगातार अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों के कारण उड़ान की अवधि में भारी वृद्धि और लागत संबंधी चुनौतियों के मद्देनजर इंडिगो को 31 अगस्त 2026 से मैनचेस्टर आने-जाने वाली अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ रही हैं। मैनचेस्टर के लिए सेवाएं पिछले साल जुलाई में शुरू की गई थीं।

18.96 करोड़ की जीएसटी चोरी में दिल्ली के दो जालसाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर

- बोगस फर्मों और जाली बिलिंग के जरिये लंबे समय से चल रहा जीएसटी चोरी का खेल
- वाट्सएप ग्रुप, फर्जी दस्तावेज और सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिये चल रहा था संगठित नेटवर्क

फर्जी बिलिंग और बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के जरिये 18.96 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में पुलिस ने 50-50 हजार रुपये के दो इनामी जालसाजों को दिल्ली के हरिनगर क्लाक टावर से गिरफ्तार किया। आरोपितों में नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर-17 स्थित समृद्धि अपार्टमेंट निवासी सौरभ अग्रवाल उर्फ सन्नी तथा साउथ-वेस्ट दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र की कैलाशपुरी एक्सटेंशन, पालन कालोनी निवासी अजीत शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त अरविंद कुमार ने तीन जुलाई 2025 को कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देकर बताया था कि यादव इंटरप्राइजेज नामक फर्म द्वारा बिना वास्तविक खरीद-बिक्री के केवल कागजों पर लेन-देन दर्शाकर भारी मात्रा में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

जांच में मई 2025 के जीएसटी रिटर्न में करीब 18.96 करोड़ रुपये की बोगस आइटीसी दर्शाए जाने का मामला सामने आया था। आरोपितों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और अन्य कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अस्तित्वहीन फर्मों का पंजीकरण कराया। गिरोह के सदस्य वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज और डाटा साझा करते थे।

इन पैमानों पर होगा चयन

प्रथम पृष्ठ से आगे

- पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों और राज्य की राजधानियों को 2025-26 के लिए अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। 10 किमी के दायरे में स्थित दो या अधिक कस्बों के शहरी समूह, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के एक लाख से कम जनसंख्या वाले कस्बों-शहरी केंद्रों पर मामले-दर-मामले विचार किया जा सकता है।
- शहरों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात जाम का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। यह आकलन शहर या कस्बे से गुजरते समय राजमार्ग पर यातायात की गति में गिरावट और शहर या कस्बे के बाहर स्थित राजमार्ग के खंडों पर यातायात की गति में गिरावट के आधार पर किया जाएगा।

ईरान से वार्ता रुकने की आशंका पर ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकारा

लेबनान हमलों को लेकर दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक, बेरूत से लौटाई इजरायली सेना

नेतन्याहू ने कहा- नीति नहीं बदलेगी, दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में आठ और लोग मारे गए

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाह में खटकने लगे हैं। लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर सोमवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर तीखी नोकझोंक हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए कहा, इजरायल की कार्रवाई के कारण उसके प्रति वैश्विक नाराजगी बढ़ रही है। ईरान युद्ध के तीन माह के दौरान यह दूसरा मौका है, जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू के रवैये पर नाराजगी जताई है।

एएनआइ के अनुसार, अमेरिकी समाचार पोर्टल एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यह बातचीत उस समय हुई जब ईरान ने चेतावनी दी कि लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रहने पर वह वाशिंगटन के साथ चल रही कूटनीतिक वार्ताओं को रोक सकता है। इसके बाद ट्रंप ने सीधे नेतन्याहू से बात की और इजरायली हमलों पर अपनी नाराजगी जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का मानना था कि हिज्बुल्ला के एक कमांडर को निशाना बनाने के लिए पूरी इमारतों को ध्वस्त करना जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया है। उन्होंने बेरूत के खिलाफ बढ़ती सैन्य धमकियों पर भी आपत्ति जताई। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि मौजूदा कार्रवाई के कारण दुनिया भर में इजरायल के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि बातचीत के बाद नेतन्याहू कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि इजरायल की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं, अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने दावा किया कि फोन वार्ता के दौरान ट्रंप का दबाव स्पष्ट रूप से हावी रहा और नेतन्याहू ने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया। बाद में ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उनके अनुरोध के बाद नेतन्याहू ने बेरूत में बड़े सैन्य अभियान की योजना को आगे नहीं बढ़ाया और सैनिकों को पीछे हटने का निर्देश दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हित 20 वर्षों में मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में एक ट्रम्स तस्करी नेटवर्क बनाया

हिज्बुल्ला के प्रतिनिधियों से बातचीत की और दोनों पक्षों ने गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई। इसके बावजूद न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली कार्रवाई जारी रही। नबातियेह शहर में हवाई हमलों के साथ टैंकों और तोपों से गोलाबारी भी हुई। वहीं, बेरूत के ऊपर इजरायली ड्रोन मंडराते रहे, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत बनी रही। उधर, हिज्बुल्ला ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ दो अभियानों का एलान किया, हालांकि सीमा पार राकेट हमले नहीं किए गए। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने चेतावनी दी कि यदि उत्तरी इजरायल पर हमले जारी रहे तो बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को खाली कराकर वहां सैन्य कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली कार्रवाई में आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक पिता, पुत्र और पुत्री भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 3,433 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं, इजरायल का दावा है कि हिज्बुल्ला के हमलों में उसके 26 सैनिक और चार नागरिक मारे गए हैं। ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ वार्ताएं तेज गति से जारी हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है।

लेबनान के नबातियेह में मंगलवार को कई स्थानों पर एक साथ हुए इजरायली हमले के बाद उठता धुएं का गुबार। रायटर >>

व्हाट द फ आर यू डूइंग? आप अपने होश गंवा चुके हैं। अगर मैं न होता तो आप जेल में होते। मैं आपको बचाने में लगा हूं। हर व्यक्ति अब आपसे घृणा करने लगा है। सभी लोग केवल आपकी वजह से इजरायल से नफरत कर रहे हैं।**

- एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा

अपने देश में भी घिरे नेतन्याहू

रायटर की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के भीतर भी नेतन्याहू को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार और पूर्व सैन्य अधिकारी गादी आइजेनकोट ने कहा कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इजरायली सैन्य कार्रवाई रुकवाना चिंता का विषय है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अब तक किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। नेतन्याहू सरकार के सहयोगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर ने भी कहा कि ट्रंप के दबाव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं, यरुशलम पोस्ट ने अपने संपादकीय में लिखा कि इजरायल ऐसी अपमानजनक स्थिति में पहुंच गया है, जहां उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी अमेरिकी मंजूरी का इंतजार करना पड़ रहा है। अखबार ने कहा कि अमेरिका इजरायल को निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने से सक्रिय रूप से रोक रहा है।

युद्धविराम समझौते पर जवाब तैयार कर रहा ईरान, ट्रंप बोले-वार्ता जारी

- अंतरिम समझौते पर जोर, तेल निर्यात और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े प्रतिबंधों में राहत चाहता है तेहरान
- अगले सप्ताह युद्धविराम बढ़ाने पर बन सकती है सहमति, तेल की कीमतें एक प्रतिशत तक गिरीं

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अमेरिका-ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समझौते पर तेहरान विचार कर रहा है। इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों के बीच समझौते पर वार्ता जारी है। तनाव कम होने की उम्मीद में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत एक प्रतिशत से ज्यादा गिर गईं। आइआरजीसी ने मंगलवार को दावा किया कि गत 24 घंटों में उसकी नौसेना से अनुमति मिलने के बाद 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं। समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी एमएससी ने कहा, इराक के उम्म कसर बंदरगाह पर खड़े उसके एक जहाज पर एक दिन पहले दो प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया गया। आइआरजीसी ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा,यह कार्रवाई ओमान की खाड़ी में ईरानी पोत पर अमेरिकी हमले के जवाब में की गई।

अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर हमले शुरू किए हुए तीन माह से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान संघर्ष एक तरह के गतिरोध में बदल गया है। अंतरिम समझौता की वार्ता अब तक निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री यातायात भी काफी प्रभावित बना हुआ है। ईरान ने सोमवार को कहा था यदि इजरायल ने बेरूत पर हमले दोबारा शुरू किए तो वह लाल सागर के प्रवेश द्वार बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट तक अपनी नाकेबंदी का दायरा बढ़ा सकता है।

रायटर के अनुसार, मेहर समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान अभी प्रस्तावित समझौते के अंतिम मसौदे पर जवाब तैयार कर रहा है। अमेरिका के पूर्व रिकार्ड व आपसी अविश्वास को देखते हुए तेहरान वार्ता में सख्त रुख अपनाए हुए है।

ट्रंप ने सोमवार को कहा,ईरान के साथ वार्ता जारी है और अगले हफ्ते तक अप्रैल की शुरुआत में हुए युद्धविराम को आगे बढ़ाने तथा होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोलने को लेकर समझौता हो सकता है। हालांकि ट्रंप कई बार शांति समझौते के करीब पहुंचने का दावा कर चुके हैं, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।

गलीबाफ ने कहा, युद्ध समझौते में लेबनान पर हमले रुकना भी जरूरीः एएनआइ के अनुसार, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा है कि अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए होने वाले किसी भी संभावित समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर हमले रोकने का प्रविधान शामिल होगा। लेबनानी संसद अध्यक्ष नबीह बेरी से बातचीत के बाद गलीबाफ ने एक्स पर कहा, व्यापक युद्धविराम किसी भी समाधान की अनिवार्य शर्त है। यदि इजरायल ने सैन्य अभियान जारी रखे तो ईरान न सिर्फ वार्ता प्रक्रिया रोक देगा, बल्कि इजरायल के खिलाफ सीधे खड़ा भी होगा।

भारत ने कहा, शांति और स्थिरता के लिए संवाद व कूटनीति ही रास्ता : भारत ने एक बार फिर संवाद व कूटनीति के जरिये समाधान निकालने पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शांति व स्थिरता की बहाली के लिए वार्ता ही सबसे प्रभावी मार्ग है। लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई और उसके क्षेत्रीय प्रभावों से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि भारत शुरू से ही वार्ता और कूटनीति के पक्ष में रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

होर्मुज स्ट्रेट खोलने के बदले ईरान को प्रतिबंधों में राहत नहीं : रुबियो

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन ने केवल होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के बदले ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने की कोई पेशकश नहीं की है। ईरान युद्ध के मुद्दे पर मंगलवार को अमेरिकी सांसदों के सामने पेश हुए रूबियो ने कहा कि ईरान होर्मुज को पूरी तरह खोल भी देता है, तब भी उस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि न तो ईरान से इस पर कोई चर्चा हुई है और न तेहरान से कोई ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में किसी भी तरह की ढील उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्तों को पूरा करने पर ही निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि परमाणु वार्ता बेहद जटिल है और किसी समाधान तक पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं।

मार्को रुबियो।

अमजद अयूब मिर्जा ने पीएम मोदी से पीओजेके में दखल की अपील की

लंदन, एएनआइ : पाक के कब्जे वाले गुलाम जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने पीएम नरेन्द्र मोदी से निवासियों की ओर से हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने क्षेत्र में व्यापक अधिकारों के उल्लंघन व राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर दबाव का आरोप लगाया है।

मिर्जा ने पीएम मोदी से कहा, भारत की नेतृत्व भूमिका पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों की चिंताओं को उजागर करने में अहम हो सकती है। उन्होंने मोदी के विकास, जवाबदेही व आर्थिक वृद्धि पर जोर देने की प्रशंसा की। कहा, ये सिद्धांत उन लोगों को आशा प्रदान करते हैं जो बेहतर शासन व अवसरों की तलाश में हैं। मिर्जा ने कहा, "केवल मोदी ही न्याय व गरिमा की पुकार करने वालों के लिए बेहतर जीवन की गारंटी दे सकते हैं।" भारत से अपील है कि वह पीओजेके व गिलगित-बाल्टिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दे को उठाए।

550 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को 'संयुक्त राष्ट्र मेडल आफ आनर'

- दक्षिण सूडान में नागरिक सुरक्षा और शांति प्रयासों के लिए सम्मानित
- मलाकाल शहर के समारोह में भारतीय शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआइएसएस) के तहत कार्यरत 53 महिलाओं समेत 565 भारतीय शांति सैनिकों को नागरिकों की सुरक्षा और संघर्ष प्रभावित देश में शांति निर्माण प्रयासों के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। दक्षिण सूडान के मलाकाल शहर में एक समारोह में 565 भारतीय शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट और रवांडा के 464 शांति सैनिकों को यूएन मेडल आफ आनर प्रदान किया गया। ब्लू हेलमेट का तात्पर्य उन सैन्यकर्मियों, पुलिस अफसरों व नागरिक विशेषज्ञों से है जो यूएन शांति सैनिक बलों के संचालनात्मक कमान के तहत कार्यरत हैं।

दक्षिण सूडान में यूएन मिशन के बल कमांडर मेजर-जनरल जुनहुई वू ने कहा,हर मेडल हमारे बहादुर शांति सैनिकों की साहस व सहनशीलता का जश्न मनाता है, जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में टीमवर्क के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करते हैं।" इस सम्मान पर भारत के स्थायी मिशन ने भारतीय दल को बधाई दी। मिशन ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, "भारतीय ब्लू हेलमेट ने सभी कार्यक्षेत्रों में उच्चतम मानकों को बनाए रखा है।" 180 भारतीय शांति सैनिकों ने ड्यूटी के दौरान प्राणों की आहुति दी है, जो कि सैन्य योगदान देने वाले देशों में सर्वाधिक है।

हरभजन व सुजीत को मरणोपरांत डैग हैमरस्कजोल्ड मेडल : पिछले हफ्ते यूएन शांति सैनिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर लांस हवलदार हरभजन सिंह को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ सेवा करने और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को यूएनएमआइएसएस के साथ सेवा के दौरान बलिदान के लिए मरणोपरांत डैग हैमरस्कजोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। डैग हैमरस्कजोल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च आधिकारिक सम्मान है।

मेजर अभिलाषा बरक भी सम्मानित : भारत के लिए मेजर अभिलाषा बरक को 2025 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट आफ द ईयर अवार्ड का प्राप्तकर्ता नामित किया गया। लेबनान में यूएन अंतरिम बल के साथ सेवा करते हुए बरक को पश्चिम एशियाई देश में अपनी तैनाती के दौरान महिलाओं से संपर्क कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बरक भारतीय बटालियन के साथ यूएनआइएफआइएल में महिला सहभागिता टीम की कमांडर हैं और भारतीय सेना की पहली महिला कांबैट हेलीकाप्टर पायलट भी हैं।

अमेरिका ने किया ब्राजील पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव

न्यूयार्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ब्राजील से कई वस्तुओं के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि एक कारोबारी जांच में नतीजा निकला है कि ब्राजील ने अनुचित तरीकों का सहारा लिया है, जिससे अमेरिकी कारोबार पर बोझ पड़ा है। टैरिफ से बीफ, काफी, रेयर अर्थ मेटल्स, विमान के उपकरणों और फल व सब्जियों आदि को छूट दी गई है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने जांच के हवाले से बताया कि ब्राजील बौद्धिक संपदा अधिकारों को ठीक से लागू करने में नाकाम रहा है और उसने भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील के एथेनाल बाजार तक पहुंच पर लगी पाबंदियों और वनों की कटाई विरोधी कानूनों को ठीक से लागू नहीं करने का भी हवाला दिया है।

हिंदूफोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव का अमेरिकी सांसद ने किया समर्थन

- डेमोक्रेट सांसद श्री थानेदार ने जनवरी में पेश किया था यह प्रस्ताव
- राजा कृष्णमूर्ति, सुहास सुब्रमण्यम सहित 32 सांसद कर चुके हैं समर्थन

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने प्रतिनिधि सभा के उस प्रस्ताव का सोमवार को समर्थन किया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हिंदू-अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की गई है और हिंदुओं के प्रति घृणा (हिंदूफोबिया), हिंदू-विरोधी कट्टरता तथा हिंदू समुदाय के मंदिरों पर हमलों की निंदा की गई है। यह प्रस्ताव मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद श्री थानेदार ने 24 जनवरी को पेश किया था। राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम सहित 32 सांसद इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं।

कैलिफोर्निया का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेट सांसद खन्ना ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया, मुझे श्री थानेदार के प्रतिनिधि सभा में पेश प्रस्ताव को सह-प्रायोजित करने पर गर्व है। यह प्रस्ताव अमेरिका में हिंदू-अमेरिकी समुदाय के निरंतर योगदान और उसकी जीवंत विविधता की सराहना करता है।

श्री थानेदार। फाइल

प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है तथा 100 से अधिक देशों में 1.2 अरब से अधिक हिंदू हैं। हिंदू धर्म में विविध परंपराएं और आस्था प्रणालियां समाहित हैं जिनमें स्वीकार्यता, परस्पर सम्मान और शांति जैसे सार्वभौमिक मूल्य निहित हैं। प्रस्ताव के अनुसार, अमेरिका ने दुनियाभर से आए 40 लाख से अधिक हिंदुओं का स्वागत किया है जो अलग-अलग नस्लीय, भाषायी और जातीय पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू-अमेरिकियों के योगदान से अमेरिका की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को काफी लाभ हुआ है। हिंदू-अमेरिकियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और विभिन्न उद्योगों में अहम योगदान दिया है तथा हिंदू परंपराओं एवं प्रथाओं ने दर्शन, आयुर्वेद, कला, संगीत, नृत्य, फैशन, ध्यान, योग और सामुदायिक सेवा के माध्यम से अमेरिकी समाज को समृद्ध किया है। प्रस्ताव में अमेरिका में बढ़ती हिंदुओं के प्रति घृणा, हिंदू-विरोधी कट्टरता, नफरत और असहिष्णुता की निंदा करते हुए कहा गया है कि देश में सकारात्मक योगदान के बावजूद हिंदू-अमेरिकियों को अपनी विरासत और प्रतीकों को लेकर रूढ़ धारणाओं तथा दुष्प्रचार का सामना करना पड़ता है।

यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले,18 की मौत

- रूस ने यूक्रेन पर दागीं 73 मिसाइलें, 656 ड्रोन से भी हमला
- कीव था हमलों का मुख्य निशाना, 100 से अधिक घायल

कीव, रायटरः रूस ने मंगलवार तड़के यूक्रेन के शहरों पर सैकड़ों ड्रोन व दर्जनों मिसाइलों से हमला किया। इनमें 18 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा, रूस ने 656 ड्रोन व 73 मिसाइलें दागीं, जिनमें आठ जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं। एक हजार किमी मारक क्षमता वाली जिरकान की रफ्तार ध्वनि की गति से नौ गुना अधिक है। वायुसेना ने 40 मिसाइलों व 602 ड्रोनों को मार गिराया। ज्ञात हो, रूस ने यूक्रेन के रूसी-नियंत्रित लुहांस्क क्षेत्र में छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के बाद कीव पर बड़े हमले की चेतावनी दी थी।

कीव के मेयर ने बताया कि राजधानी में रातभर चले हमलों में छह लोग मारे गए और तीन बच्चों सहित 80 से अधिक लोग घायल हो गए। निप्रो में चार मंजिला इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई, जिसमें 12 लोग मारे गए। हमलों का मुख्य निशाना कीव था। खार्कीव में हुए एक बच्चे समेत 14 लोग घायल हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा, कीव के आतंकी कृत्यों के जवाब में रूसी संघ के सशस्त्र बलों ने लंबी दूरी के हवाई, जमीनी व समुद्री हथियारों का उपयोग कर बड़ा हमला किया। रूस ने कीव, जपोरिजिया और खार्कीव सहित सात यूक्रेनी क्षेत्रों पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन का प्रयोग किया। कीव में स्थित 10 सैन्य उत्पादन संयंत्रों को निशाना बनाया गया। नाटो सदस्य पोलैंड ने कहा,उसने यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सैन्य जेट विमानों को तैनात किया है। यूक्रेन ने भी रूस के कुछ इलाकों पर हमले किए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने टेलीग्राम पर बताया कि दक्षिणी रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र में स्थित इल्स्की तेल रिफाइनरी में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। यूक्रेन की सेना ने हमले की पुष्टि की। यूक्रेन सीमा से लगे बेलगोरेद क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन के हमले में एक बच्चा घायल हो गया। रूसी समाचार एजेंसियों ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि रूस ने रातभर में 148 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए।

जेलेंस्की ने किया पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर भेजने का आग्रहः यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमले के बाद कहा, यह रूस का स्पष्ट संदेश है, यदि यूक्रेन को मिसाइल हमलों से सुरक्षित नहीं किया जाता है, तो ये हमले जारी रहेंगे। उन्होंने वाशिंगटन से अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर भेजने का फिर आग्रह किया। विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने साझेदारों से यूक्रेन की मदद करने व रूस पर दबाव डालने का आग्रह किया। उन्होंने पोस्ट किया, मास्को युद्ध के मैदान में हार रहा है। मिसाइलों की संख्या इसे नहीं बदल सकती। हम जो बदल सकते हैं वह है रूस की आतंक फैलाने की क्षमता।

कीव में मंगलवार को रूसी हवाई हमले के बाद उठते आग के गोले से पूरे इलाके में फैली रोशनी। रायटर

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार

- आपरेशन चेकमेट के तहत जल्द ही निर्वासित होंगे ये 30 भारतीय
- अधिकांश के पास रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज, जो अब मान्य नहीं

न्यूयार्क, प्रेट्र : अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे और वाणिज्यिक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे 30 भारतीय नागरिकों को एक अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जल्द ही निर्वासित किया जाएगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने एक बयान में कहा कि 11 से 15 मई के दौरान एरिजोना के युमा सेक्टर के सीमा गश्ती एजेंटों ने 'आपरेशन चेकमेट' के तहत 52 व्यक्तियों को अवैध रूप से अमेरिका में रहने के लिए गिरफ्तार किया, जिनमें से 36 सेमी-ट्रक चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए 36 अवैध सेमी-ट्रक ड्राइवरों में से 30 भारत के थे, जबकि शेष छह मेक्सिको, एल साल्वाडोर और रूस के थे। उनके पास कैलिफोर्निया, न्यूयार्क, वाशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों से वाणिज्यिक ड्राइवर के लाइसेंस थे, जबकि कुछ के पास किसी भी प्रकार का ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं था। अधिकांश के पास रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज थे, जो बाइडन प्रशासन के दौरान प्राप्त किए गए थे और अब मान्य नहीं हैं। इन सभी व्यक्तियों को केंद्रीय कानून के तहत निर्वासित किया जाएगा। आपरेशन चेकमेट का उद्देश्य अमेरिका में वाणिज्यिक मोटर वाहनों का संचालन करने वाले अवैध व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना है। यूमा सेक्टर के अमेरिकी सीमा गश्ती के कार्यवाहक प्रमुख डस्टिन काउडल ने कहा, "आपरेशन चेकमेट हमारे समुदायों और सड़कों को अवैध रूप से उपस्थित ड्राइवरों से सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत परिवहन विभाग ने अव्यवस्थित विदेशी ड्राइवरों को वाणिज्यिक ट्रक और बस चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने का आदेश जारी किया था।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने बेहद कड़े मुकाबले में साइप्रस के उम्मीदवार एंड्रियास काकौरिस को हराया। रहमान को 99 वोट मिले जबकि काकौरिस को उपस्थित और मतदान करने वाले 190 सदस्यों में से 91 वोट मिले। निर्वाचित होने के लिए 96 वोटों की आवश्यकता थी। रहमान सितंबर में शुरू होने वाले 193 सदस्यीय महासभा के 81वें सत्र का नेतृत्व करेंगे।

रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्तमान अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक से पदभार ग्रहण करेंगे। एनालेना संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 साल के इतिहास में केवल पांचवीं महिला अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है।

ब्रिटेन में एक पीड़िता से 600-700 अलग-अलग व्यक्तियों ने किया दुष्कर्म

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- ब्रिटिश सांसद ने संसद में बताई पाक ग्रूमिंग गैंग्स की हैवानियत की दास्तां
- कहा, ईसाई व गोरी लड़कियों को नस्ल के आधार पर बनाया गया निशाना

ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव के संसद में हालिया संबोधन से ब्रिटेन में पाकिस्तान के ग्रूमिंग गैंग्स की चर्चा पुनः शुरू हो गई है। ये गैंग्स ब्रिटेन के कई राज्यों में बच्चों के यौन शोषण में शामिल रहे हैं। सरकार की जांच में पाया गया है कि संगठित रूप से बच्चों के यौन शोषण के अपराधी अधिकतर पाकिस्तानी मूल के टैक्सी ड्राइवर व मार्केट ट्रेडर हैं। लोव ने अपने संबोधन के दौरान कई पीड़िताओं के बयान पढ़े, जिसमें एक पीड़िता का कहना था कि तीन वर्ष में 600-700 अलग-अलग व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। एक गवाही में बताया गया कि अपराधियों ने बच्चे के चेहरे पर सिगरेट बुझाई थी।

लोव ने संबोधन में जिन पीड़िताओं के बयान पढ़े, उनमें से अधिकतर में यौन शोषण, बाल गर्भधारण, धमकी, कथित तौर पर पुलिस कदाचार के बारे में बताया गया। लोव के अनुसार, ये बयान जांच के दौरान एकत्रित किए गए थे और इन पीड़िताओं को संगठित ग्रूमिंग गैंग्स ने बचपन में निशाना बनाया था। लोव ने जिन बयानों का जिक्र किया, उनमें बहुत अधिक हिंसा, क्रूरता व यौन शोषण का उल्लेख था। इनमें टूटी बोतलों से दुष्कर्म, कुत्तों के हमले, पुलिस अफसरों को दुष्कर्मी बताना शामिल है। पीड़िताओं ने कहा, उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। अपराधी ऐसी बातें करते थे, जिनमें गोरी व ईसाई लड़कियों को कम नैतिक मूल्यों वाली व मुस्लिम लड़कियों को इज्जतदार व ऊंचे नैतिक मूल्यों वाली बताया जाता था। एक महिला ने बताया कि शोषण के दौरान वह जिन अन्य लड़कियों से मिली थी, वे सब गोरी थीं। गैंग के सदस्य कार का हार्न बजाते थे और फिर चिल्ड्रन होम का कोई कर्मचारी बच्चे को दरवाजे तक ले जाता था। ईद व छुट्टियों के आस-पास हालात बिगड़ जाते थे।

ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का इतिहास : ग्रूमिंग गैंग के बारे में लोगों को वर्ष 2001 में साउथ यार्कशायर के शहर रादरहैम में पता चला था। हालांकि, इस केस में सजा 2010 में हुई थी, जब पाकिस्तानी मूल के पांच व्यक्तियों को 12 से 16 वर्ष की लड़कियों के विरुद्ध अपराधों के लिए जेल हुई थी। यही पैटर्न रोशडेल, आक्सफोर्ड, टेलफोर्ड व ब्रिस्टल जैसे 50 से अधिक शहरों में देखा गया। प्रो. एलेक्सिस जे की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले रादरहैम में 1997 और 2013 के बीच 16 वर्षों में 1,400 से अधिक बच्चों का यौन शोषण हुआ था।

आपत्तिनजक कंटेंट से किशोरों को बचाने के लिए मेटा ने पेश किए नए फीचर

न्यूयार्क टाइम्स से

सैन फ्रांसिस्को : मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर पर किशोरों को दिखाई जाने वाले आपत्तिनजक या हानिकारक कंटेंट को सीमित करने के लिए मंगलवार को नए सुरक्षा फीचर पेश किए। इन्हें किशोरों द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट में विविधता लाने और कुछ खास थीम के बार-बार सामने आने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अक्टूबर में, मेटा ने इंस्टाग्राम पर कंटेंट के लिए फिल्मों के मानदंडों पर आधारित रेटिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। मेटा ने बताया कि इस साल के अंत में फेसबुक व मैसेंजर पर "सीमित कंटेंट" सेटिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये बदलाव कंपनी के टीन अकाउंट्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिसने माता-पिता को बच्चों के अकाउंट पर अधिक नियंत्रण दिया। कंपनी ने माडरेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए लाखों कंटेंट पर माता-पिता से रेटिंग भी ली थी।

2002 में आखिरी बार ब्राजील ने जीता था फुटबाल विश्व कप अब एंसेलोटी की कोचिंग में 24 साल बाद फिर ट्राफी जीतने उतरेगी टीम

ब्राजील को खिताब की दौड़ से बाहर नहीं रख सकते : एंसेलोटी

ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी का कहना है कि 11 जून से शुरू हो रहे फीफा विश्व कप में भले ही कई दावेदार हों, लेकिन ब्राजील को आप कभी खिताब की दौड़ से बाहर नहीं रखा जा सकता है। 2025 में ब्राजील का कोच पद संभालने वाले एंसेलोटी के अनुसार, इस विश्व कप में ब्राजील से बहुत उम्मीदें होंगी क्योंकि टीम 24 साल से खिताब नहीं जीत सकी है। इतालवी मूल के एंसेलोटी को इटली के विश्व कप में क्वालीफाई नहीं कर पाने का भी दुख है। फीफा विश्व कप को लेकर **एंसेलोटी** ने विशेष बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :-

9 दिन शेष

साक्षात्कार

ब्राजील टीम के कोच कार्लो एंसेलोटी और खिलाड़ी केसमीरो ● फाइल फोटो, रायटर

● **1994 में अमेरिका में हुए फुटबाल विश्व कप में आप इटली टीम के सहायक कोच थे और तब टीम फाइनल में ब्राजील से हार गई थी। 32 साल बाद अब आप अमेरिका में होने वाले एक और विश्व कप में ब्राजील के मुख्य कोच होंगे। क्या यह एक तरह से पूरा चक्र पूरा होने जैसा है?**

-वास्तव में ऐसा नहीं है। सच कहूं तो मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा। जब मुझे ब्राजील का कोच बनने का प्रस्ताव मिला, तब मैं रीयल मैड्रिड के साथ काम कर रहा था। मैंने उनसे कुछ समय इंतजार करने को कहा और उन्होंने किया। बाद में उनकी रुचि बनी रही और मुझे दुनिया की सबसे सफल राष्ट्रीय फुटबाल टीम को कोचिंग देने का अवसर रोमांचक लगा। यह महज संयोग है कि दोनों विश्व कप अमेरिका में हो रहे हैं, हालांकि इस बार मेक्सिको और कनाडा भी मेजबान हैं।

● **आपने पांच चैंपियंस लीग खिताब जीते हैं और ब्राजील के पास भी पांच विश्व कप ट्राफियां हैं। इस समानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है?**

-यह भी एक संयोग ही है। हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह ब्राजीलियाई खिलाड़ियों के लिए दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का शानदार अवसर है। हमें ऐसी तैयारी करनी होगी जिससे दुनिया भर में फैले हमारे प्रशंसकों को खुशी मिले।

● **एक और संयोग यह है कि 1994 में ब्राजील ने 24 साल बाद विश्व कप जीता था और अब फिर 24 साल बाद खिताब जीतने की कोशिश करेगा?**

-हां, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ब्राजील हमेशा हर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। पिछले 24 वर्षों में बात नहीं बनी, लेकिन ब्राजील हमेशा मजबूत दावेदारों में शामिल रहा। फुटबाल में आप हर बार नहीं जीत सकते। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि प्रयास में कोई कमी न हो और हम आगामी विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।

● **आपको क्लब फुटबाल में एक महान रणनीतिकार माना जाता है, जबकि ब्राजील हमेशा व्यक्तिगत प्रतिभाओं से भरपूर टीम रही है। इस पर आप क्या कहेंगे?**

-केवल प्रतिभा के दम पर बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते। 1994 में ब्राजील के पास रोमारियो और बेबेटो जैसे शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन टीम ने 4-4-2 फार्मेशन में खेलते हुए मिडफील्ड की बड़ी भूमिका सुनिश्चित की थी। इसी तरह 2002 में ब्राजील ने तीन केंद्रीय डिफेंडरों के साथ खेला था। करीबी मुकाबलों में व्यक्तिगत प्रतिभा अंतर पैदा कर सकती है, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत और संगठित टीम प्रयास होना जरूरी है।

● **क्या आप विश्व कप में कोई नया फार्मेशन लागू करेंगे, जैसे पुराने 4-2-4 सिस्टम की वापसी?**

-किसी भी सिस्टम को खिलाड़ियों पर थोपा नहीं जा सकता। उसे खिलाड़ी तब अपनाते हैं जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे उस तरीके से खेलकर सफल हो सकते हैं। पहले उनका भरोसा जीतना जरूरी है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोच कुछ कहे और खिलाड़ी उसे लागू कर दें। मुझे याद है कि आंद्रे पिरलो ने मुझे सुझाव दिया था कि मैं उन्हें डिफेंसिव मिडफील्डर की भूमिका में खिलाऊं। उन्होंने मुझे इसके लिए आश्वस्त किया और बाद में मैदान पर उस भूमिका को नई पहचान दी। मेरी सोच खिलाड़ियों से बात करके उनकी राय समझने और फिर उनके लिए सबसे उपयुक्त योजना बनाने की है।

● **क्या आप अपनी चुनी हुई टीम से संतुष्ट हैं? कुछ अहम खिलाड़ी जैसे मिलिताओ और रोड्रिगो चोट के कारण बाहर हैं। क्या विश्व कप में उनकी कमी खलेगी ?**

-फुटबाल में चोटें खेल का हिस्सा हैं। मिलिताओ और रोड्रिगो जैसे खिलाड़ियों की कमी जरूर खलेगी, लेकिन इससे नए खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का मौका भी मिलता है। 40 वर्षों से अधिक समय तक कोचिंग करने के अनुभव से मैं जानता हूं कि ऐसी परिस्थितियां किसी भी टीम के साथ कभी भी हो सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है।

● **ब्राजीलियाई प्रशंसकों की उम्मीदों से कैसे निपटेंगे?**

-उम्मीदें वास्तव में जिम्मेदारियां होती हैं। जब आप ब्राजील जैसी टीम को विश्व कप में कोच कर रहे हों तो अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं। मैंने देखा है कि ब्राजील में राष्ट्रीय टीम का हर मैच एक उत्सव जैसा होता है। पूरा देश पीली जर्सी पहनकर टीम का समर्थन करता है और उसके साथ जश्न मनाता है। विश्व कप में ये उम्मीदें और भी बड़ी होंगी। हमें हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा ताकि हम अपने प्रशंसकों को खुश कर सकें।

● **2026 विश्व कप जीतने के लिए क्या कोई स्पष्ट दावेदार है?**

-सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई टीमें हैं। फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और जर्मनी सभी मजबूत दावेदार हैं। इन टीमों के बीच होने वाले मुकाबले किसी भी फुटबाल प्रशंसक के लिए रोमांचक होंगे। इस विश्व कप में फुटबाल अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचेगा और भावनाएं भी चरम पर होंगी। और हां, ब्राजील को भी कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

● **क्या ये परेशान करता है कि आपकी मातृभूमि इटली लगातार तीन विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी?**

-बिल्कुल, यह दुख पहुंचाता है। हमने चार विश्व कप जीते हैं, लेकिन 2018 के बाद से हम विश्व कप में नहीं खेल पाए हैं। इटली के फुटबाल ढांचे में कुछ गंभीर समस्याएं हैं और संबंधित लोगों को जल्द से जल्द उनका समाधान करना होगा। (पीएमजी)

इतिहास रचने को तैयार सबसे बड़ा फुटबाल महाकुंभ

न्यूयार्क में विश्व कप ट्राफी के साथ पूर्व जर्मन फुटबालर बास्टियान श्वेंसटाइगर ● एएफपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : फीफा विश्व कप 2026 के लिए सभी 48 देशों ने अपनी अंतिम टीमों की घोषणा कर दी है। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में रिकार्ड 1248 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी समूह होगा। पहली बार 48 टीमों के प्रारूप में आयोजित होने जा रहे इस विश्व कप में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे।

357 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहले भी किसी न किसी विश्व कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं

891 खिलाड़ी घोषित टीमों में से पहली बार फीफा विश्व कप में खेलने का अनुभव करेंगे

क्रेग गार्डन सबसे उम्रदराज तो गिल्बर्टो मोरा सबसे युवा

क्रेग गार्डन

गिल्बर्टो मोरा

उम्र के लिहाज से भी यह विश्व कप बेहद खास रहेगा। स्काटलैंड के गोलकीपर क्रेग गार्डन 43 वर्ष और 162 दिन की उम्र के साथ टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, जबकि मेक्सिको के गिल्बर्टो मोरा 17 वर्ष और 240 दिन की उम्र में सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। टूर्नामेंट में 20 वर्ष से कम उम्र के 22 खिलाड़ी और 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सात खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 22 पूर्व विश्व कप विजेता खिलाड़ी भी इसमें खेलेंगे।

पहली बार खेलेंगे येदेश

कैप वेर्डे, कुराकाओ, जार्डन और उज्बेकिस्तान पहली बार फीफा विश्व कप में खेलेंगे।

71 देशों के 449 अलग-अलग क्लबों के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व करेंगे

इनका होगा छठा विश्व कप

अर्जेंटीना के लियोन मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेक्सिको के गोलकीपर गिलर्मो ओचोआ अपने रिकार्ड छठे फीफा विश्व कप में उतरकर इतिहास रचेंगे। घाना के कोच कार्लोस क्वेइरोज का भी यह लगातार पांचवां विश्व कप होगा।

नंगे पैर चलकर संत प्रेमानंद से मिले विराट कोहली और अनुष्का

प्रेमानंद से मिलने जाते विराट व अनुष्का।

जागरण संवाददाता, वृंदावन : माथे पर ब्रज रज का तिलक, गले में तुलसी की कंठी माला। यमुना के खादर में ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर नंगे पैर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ मंगलवार को संत प्रेमानंद से मिलने पहुंचे। संत इन दिनों यमुना किनारे कुटिया बनाकर एकांत में रह रहे हैं। संत ने दोनों से कुटिया में वार्ता की और आशीर्वाद दिया।

आरसीबी के लगातार दूसरी बार आइपीएल खिताब जीतने के बाद विराट और अनुष्का सोमवार को वृंदावन पहुंचे। मंगलवार सुबह सात बजे श्रीराधा केलिकुंज आश्रम के संत दोनों को लेकर यमुना खादर में एकांतवास में रह रहे संत प्रेमानंद की कुटिया में पहुंचे। कुटिया से पहले विराट और अनुष्का कार से उतरे और नंगे पैर ही ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चले। रास्ते में वृक्षों के टुकड़े और पत्थर पड़े थे। संत से आशीर्वाद लेकर आधे घंटे तक दोनों ने उनसे आध्यात्मिक चर्चा की। संत ने दोनों को लगातार नामजप करने का संदेश दिया।

आकिब, प्रिंस समेत छह गेंदबाज कराएंगे भारतीय बल्लेबाजों को अभ्यास

मुल्लांपुर, प्रेट्र: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को अफगानिस्तान के विरुद्ध छह जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारत के नेट अभ्यास सत्र के लिए चुने गए छह गेंदबाजों में शामिल किया गया है। नबी को टेस्ट टीम में नहीं चुने जाने पर चयन समिति को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

आकिब नबी के अलावा आइपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले उत्तर प्रदेश के लेग स्पिनर जीशान अंसारी को भी नेट अभ्यास के लिए बुलाया गया है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम में कलाई के स्पिनर होने की संभावना है। नेट अभ्यास के लिए जिन अन्य गेंदबाजों को बुलाया गया है उनमें बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर शिवांग कुमार, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह, आइपीएल की खोज तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और आफ स्पिनर सारांश जैन शामिल हैं।

बीसीसीआइ ने कहा, गुरजपनीत सिंह, आकिब नबी, प्रिंस यादव, सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार टेस्ट मैच की तैयारी में टीम की मदद करने के लिए नेट गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार, आकिब नबी को भारतीय नेट अभ्यास सत्र में शामिल होने के लिए कहा गया है। आकिब ही नहीं पांच अन्य गेंदबाजों को भी नेट अभ्यास के लिए बुलाया गया है। भारतीय टीम के दो प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा सात दिन में आइपीएल के तीन मैच खेलने के कारण नेट अभ्यास में पूरी ताकत नहीं झोंक सकते हैं। बल्लेबाजों को पर्याप्त अभ्यास की जरूरत है। सिराज और प्रसिद्ध दोनों ने क्रमशः धर्मशाला, चंडीगढ़ और अहमदाबाद की यात्रा सहित पांच दिन के अंतराल में आइपीएल का पहला और दूसरा क्वालीफायर तथा फाइनल खेला।

नबी ने 60 विकेट लेकर जम्मू कश्मीर को रणजी ट्राफी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी लेकिन भारतीय टीम में उनके बजाय चयनकर्ताओं ने पंजाब के लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को प्राथमिकता दी गई। भारतीय टीम के पहले अभ्यास सत्र में आइपीएल फाइनल में खेलने वाले खिलाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। आइपीएल की उपविजेता गुजरात टाइटंस के सात खिलाड़ी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं।

बहुतुले बने भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीसीसीआइ ने पूर्व भारतीय स्पिनर साईराज बहुतुले को सीनियर पुरुष टीम का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआइ ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा, बहुत खुशी के साथ साईराज बहुतुले को भारतीय सीनियर पुरुष टीम का स्पिन गेंदबाजी कोच घोषित किया जाता है। बहुतुले शनिवार से अफगानिस्तान के विरुद्ध शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट मैच से भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। वह मानव सुथार और हर्ष दुबे जैसे युवा स्पिनरों के साथ काम करेंगे। घरेलू क्रिकेट के दिग्गज रहे बहुतुले के नाम प्रथम श्रेणी में 630 विकेट के साथ 6,176 रन भी हैं। संन्यास के बाद से ही वह कोचिंग में सक्रिय हैं। मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके बहुतुले विदर्भ, केरल, गुजरात और बंगाल जैसी टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। हाल ही में वह स्पिन कोच के रूप में आइपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के साथ थे। बहुतुले साल 2022 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम के गेंदबाजी कोच थे। वह 2024 में भी इस टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। बहुतुले बीसीसीआइ की नेशनल क्रिकेट अकादमी में भी काम कर चुके हैं।

मुल्लांपुर में अभ्यास के दौरान बात करते गौतम गंभीर और साईराज बहुतुले ● प्रेट्र

खेल डायरी

44 वर्ष की उम्र में वापसी करेंगी सेरेना विलियम्स

पेरिस, एपी: सेरेना विलियम्स 44 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस में वापसी करने जा रही हैं। वह उस खेल में लौट रही हैं, जिस पर उन्होंने दो दशकों तक राज किया है। 23 बार की ग्रैंडस्लैम सिंगल्स चैंपियन अब सबसे पहले क्वीन क्लब में डबल्स टूर्नामेंट में लौटेंगी, लेकिन इसके बाद विंबलडन और यूएस ओपन में भी aउनकी वापसी हो सकती है। पूर्व नंबर एक लिंडसे डेवनपोर्ट ने फ्रेंच ओपन के दौरान कहा है कि ऐसा लगता है कि सेरेना यूएस ओपन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और वहां के फैंस उन्हें सिंगल्स कोर्ट पर वापस देखने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। इससे पहले डब्ल्यूटीए टूर ने सोमवार को घोषणा की थी कि सेरेना ने अगले हफ्ते लंदन में होने वाले ग्रास-कोर्ट टूर्नामेंट में डबल्स खेलने के लिए वाइल्ड-कार्ड का न्योता स्वीकार कर लिया है।

निलंबन का फैसला अप्रत्याशित : क्रिकेट कनाडा

टोरंटो, प्रेट्र: क्रिकेट कनाडा ने आइसीसी द्वारा अपनी सदस्यता निलंबित करने के फैसले को अप्रत्याशित बताया है और कहा है कि उसने खेल की वैश्विक शासी निकाय द्वारा बताई गई शासन और वित्तीय कमियों को दूर करने के लिए व्यापक सुधारात्मक उपाय शुरू कर दिए हैं। आइसीसी ने रविवार को अहमदाबाद में अपनी बोर्ड बैठक में क्रिकेट कनाडा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आइसीसी ने इसे सदस्यता दायित्वों का गंभीर उल्लंघन बताया। हालांकि वैश्विक निकाय ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए कनाडाई राष्ट्रीय टीमें आइसीसी आयोजनों में भाग लेने के लिए पात्र बनी रहेंगी। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रिकेट कनाडा ने कहा कि वह आइसीसी के फैसले का सम्मान करता है और सभी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आइएसएल का नया सत्र एक सितंबर से

नई दिल्ली, प्रेट्र: अखिल भारतीय फुटबाल फेडरेशन (एआइएफएफ) के 2026-27 सीजन के संभावित कैलेंडर के अनुसार, इंडियन सुपर लीग एक सितंबर 2024 से 11 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएगी। फेडरेशन कप 20 अप्रैल 2027 से 10 मई 2027 तक होगा। इंडियन फुटबाल लीग (आइएफएल) नौ अक्टूबर से 14 मार्च तक होगी, जबकि इंडियन वूमेंस लीग (आइडब्ल्यूएल) तीन सितंबर से 24 जनवरी तक होगी। वहीं आइ-लीग 2 प्रतियोगिता एक फरवरी 2027 से 11 अप्रैल 2027 के बीच होगी, जबकि तीसरी डिवीजन की पुरुषों की लीग 15 अगस्त से सात नवंबर तक चलेगी। डूरंड कप 11 जुलाई से 20 अगस्त तक होगा। इंडियन वूमेंस लीग 2 (आइडब्ल्यूएल) नौ जुलाई से 22 अगस्त तक होने का प्रस्ताव है। संतोष ट्राफी अगले साल 19 नवंबर से 17 जनवरी तक होगी। कैलेंडर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप, यूथ लीग, फुटसल चैंपियनशिप और बीच साकर टूर्नामेंट के लिए भी तारीखें तय की गई हैं।

सिंधू दूसरे दौर में, किदांबी और लक्ष्य बाहर

पीवी सिंधू

जकार्ता, प्रेट्र: दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने मंगलवार को सीधे गेम में जीत हासिल कर इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई, जबकि पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन टूर्नामेंट के पहले ही दौर में बाहर हो गए। सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के राउंड आफ 32 के मुकाबले में सिंधू को 51 मिनट तक चले मुकाबले में थाइलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन आखिर में सिंधू ने 25-23, 21-16 से जीत हासिल की।

अब दूसरे राउंड में गैर वरीयता प्राप्त सिंधू का मुकाबला मौजूदा ओलिंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक एन से-यंग से होने की संभावना है। पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत के लिए इंडोनेशिया ओपन में सिंधू के अलावा कई भारतीय शटलरों का सफर पहले ही दौर में थमा यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा। उन्हें पहले दौर में जापान के युशी तनाका के हाथों 19-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा।

वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन भी पहले ही दौर में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से 19-21, 16-21 से हारकर बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़ भी पहले दौर में सातवीं वरीयता प्राप्त पोर्नपावी चोचुवोंग से 21-12, 21-10 से हार गईं। हालांकि पुरुष डबल्स की जोड़ी हरिहरन अमसकारुनन और एमआर अर्जुन ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई।

दीक्षा डोप टेस्ट में फेल, लग सकता है प्रतिबंध

नई दिल्ली, जेएनएन: राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। देश की मध्यदूरी की शीर्ष धाविका केएम दीक्षा डोपिंग के जाल में फंस गई हैं। 1500 मीटर की राष्ट्रीय रिकार्ड धारक दीक्षा को नाडा ने सूचित किया है कि उनके नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया है। हालांकि उन्हें अभी तक अस्थायी निलंबन नहीं दिया गया है, लेकिन दीक्षा के डोपिंग में फंसने से राष्ट्रमंडल खेलों के लिए उनकी पात्रता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक सूत्र ने बताया कि दीक्षा को सूचित किया गया है कि उनके नमूनों में प्रतिबंधित पदार्थ की उपस्थिति पाई गई है। दीक्षा का नमूना टूर्नामेंट से इतर लिया गया था और मई के अंतिम सप्ताह में उन्हें पत्र के जरिये सूचित किया गया।

प्रगनानंद, गुकेश और दिव्या ने जीत के साथ जगाई उम्मीदें

नार्वे शतरंज खिताब में भारतीय चुनौतियों को फिर मिला बल, तीन भारतीय ग्रैंडमास्टर ने जीतने अपने-अपने मुकाबले

ओस्लो, प्रेट्र: नार्वे शतरंज टूर्नामेंट में मंगलवार को भारतीयों ने सातवें राउंड में शानदार वापसी की। डी गुकेश और आर प्रगनानंद ने अहम जीत हासिल की, जबकि दिव्या देशमुख ने पिछले दौर की हार से उबरते हुए हमवतन कोनेरू हंपी को हराया। इससे टूर्नामेंट की खिताब की दौड़ के निर्णायक दौर में पहुंचने के साथ ही देश की चुनौती फिर से मजबूत हो गई है।

विश्व चैंपियन गुकेश ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो के विरुद्ध मुकाबले से 1.5 अंक बचाए। क्लासिकल गेम में जीत का मौका हाथ से फिसलने के बाद उन्होंने आमगेडन टाई-ब्रेक में जीत हासिल की और कुल आठ अंकों पर पहुंच गए। प्रगनानंद ने फ्रांसीसी ग्रैंडमास्टर अलीरेजा फिरोजा को लगातार दूसरी क्लासिकल बाजी में हराया। उन्होंने पूरे तीन अंक हासिल किए और नौ अंकों पर पहुंच गए। प्रगनानंद पांचवें और गुकेश छठे स्थान पर ही बने रहे। फिर भी दोनों भारतीय खिलाड़ी शीर्ष पर चल रहे खिलाड़ियों से ज्यादा पीछे नहीं हैं।

टूर्नामेंट में अभी तीन राउंड बाकी हैं, इसलिए प्रगनानंद और गुकेश आखिरी समय में जोरदार वापसी कर सकते हैं।

ज्वेरेव और आंद्रीवा सेमीफाइनल में, सबालेंका ने ओसाका को हराया

पेरिस, एपी : दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मंगलवार को युवा खिलाड़ी राफेल जोडर पर 7-6 (3) 6-1 6-3 से शानदार जीत दर्ज करते हुए फ्रेंच ओपन में अपनी उम्मीदें जीवित रखीं। इसी के साथ वह छह साल में पांचवीं बार रोलैंड गैरोस के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में रूस की मीरा आंद्रीवा ने रोमानिया की सोराना क्रिस्टिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 19 वर्षीय आंद्रीवा ने क्रिस्टिया पर सीधे सेटों में 6-0, 6-3 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में आंद्रीवा का सामना यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक से होगा, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन एलिना स्वितोलिना को 6-3, 2-6, 6-2 से पराजित किया। वहीं महिलाओं में सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में विश्व नंबर एक एरिना सबालेंका ने जापान की नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।

सोराना क्रिस्टी के विरुद्ध रिटर्न शाट लगातीं मीरा आंद्रीवा ● एपी

पिछले साल यहां फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव को कोर्ट फिलिप-चैट्रियर पर पहले सेट में 19 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन 29 साल के ज्वेरेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने 2-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 2 घंटे 17 मिनट में जीत हासिल की। 19 साल का यह खिलाड़ी पहला सेट जीतने की राह पर लग रहा था, उन्होंने सर्व तोड़कर 5-2 की बढ़त बना ली, लेकिन ज्वेरेव की काबिलियत काम आई, और जर्मन खिलाड़ी ने अगले छह में से पांच गेम जीतकर मैच को टाई-ब्रेक तक पहुंचा दिया। इसके बाद ज्वेरेव तेजी से 3-3 की बराबरी पर पहुंचे और फिर लगातार चार प्वाइंट्स जीतकर सेट अपने नाम कर लिया। यहीं से ज्वेरेव पूरी तरह हावी हो गए। अपनी पहली सर्व पर 71 प्रतिशत प्वाइंट्स जीतकर और जोरदार फोरहैंड लगाते हुए, उन्होंने दूसरे सेट में 1-1 की बराबरी से लगातार सात गेम जीते और दो सेट की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

दूसरी बार सेमीफाइनल में आंद्रीवा: मीरा एंड्रीवा ने अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मैच की शुरुआत से ही आंद्रीवा ने ने अपना दबदबा बनाए रखा। रूसी खिलाड़ी ने पहले छह गेम में सिर्फ नौ अंक गंवाए और 36 वर्षीय क्रिस्टी को एक भी गेम प्वाइंट नहीं दिया। इससे पहले, फ्रेंच ओपन में अपने फैशन से जलवा बिखेरने वाली ओसाका ने सबालेंका के विरुद्ध मुकाबले में शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और शुरुआती बढ़त हासिल कर ली, लेकिन सबालेंका ने अपनी ताकतवर ग्राउंडस्ट्रोक्स और आक्रामक खेल से मैच पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले सेट में 5-5 की बराबरी के बाद उन्होंने निर्णायक ब्रेक हासिल किया और फिर दूसरे सेट में भी दबदबा बनाए रखा। जीत के बाद सबालेंका ने कहा कि ओसाका बेहद आक्रामक खिलाड़ी हैं और उनके खिलाफ दबाव बनाए रखना आसान नहीं था।

एरिना सबालेंका ● एएफपी

गर्मी के मौसम में अनेक चुनौतियों का एक साथ सामना करना पड़ता है। इन दिनों बाहर निकलते समय आंखों और त्वचा को धूप से बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें, शुष्क हवा, धूल और आद्रता के चलते परेशानी होने की अधिक आशंका रहती है। इस मौसम में किन बातों का रखें ध्यान, कैसे बढ़ाएं सतर्कता, बता रही हैं सीमा झा

गर्मी से बचाएं आंखें और त्वचा

• फोटो : मैग्नीफिक

इन दिनों

तेज गर्मी और धूप न केवल नींद छीनती है बल्कि इससे त्वचा और आंखों के संक्रमण का भी खतरा रहता है। गर्मी के कारण एलर्जी और संक्रमण की परेशानी हो सकती है। इससे आपकी दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। गर्मी और उमस से सतर्कता बरती जाए तो ऐसी परेशानियों से बचा जा सकता है। इन दिनों हाइड्रेट रहना जरूरी है, साथ ही सही दिनचर्या और खानपान को लेकर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये भले सामान्य बात लगे, पर इससे गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचे रहेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी से पीड़ित लोगों को इन दिनों अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, खासकर जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें आंखों और त्वचा के संक्रमण की आशंका अधिक रहती है।

मौसमी फल हैं भीतरी सनस्क्रीन

धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाव में मौसमी फल भी सनस्क्रीन की तरह अंदरूनी अंगों को सुरक्षित रखते हैं। इसका प्रभाव हमारी सेहत के साथ त्वचा और आंखों पर पड़ता है। इस मौसम में लोग आंवले का सेवन कम करते हैं, पर गर्मी में भी यह लाभकारी है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, मौसमी फलों जैसे- तरबूज, आम, जामुन आदि का प्रयोग भी धूप से बचाव करने में कारगर होता है, जिन्हें भीतरी सनस्क्रीन कहा जा सकता है। ध्यान रहे पानी पीने के अलावा, खीरा, तरबूज, संतरा और स्ट्राबेरी जैसे अधिक पानी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना न भूलें। ये खाद्य पदार्थ न केवल आपके शरीर को हाइड्रेट करते हैं, बल्कि आपकी त्वचा को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इससे आंखों को भी लाभ मिलता है। हाइड्रेट रहने, धूप से बचाव करने जैसी सतर्कता से त्वचा संक्रमण और आंखों की परेशानियों से बचे रहते हैं।

गर्मी में आंखों को सुरक्षित रखना जरूरी

डा. रोहित सक्सेना
प्रोफेसर, राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र, एम्स, नई दिल्ली

गर्मी में आंखों में सूखापन की समस्या अधिक होती है। यूवी किरणों और प्रदूषण के कारण आंखों में संक्रमण का भी खतरा रहता है। बाहर निकलते समय गागल्स का प्रयोग करना चाहिए। यह आकार में बड़ा हो, ताकि आंखों को पूरी तरह ढक सके। यदि तैराकी के लिए जा रहे हैं तो इसे पहनना न भूलें। बच्चे अक्सर अनदेखी करते हैं। आंखों को सीधी धूप से बचाने के लिए चौड़ी किनारी वाली टोपी या हैट लगाएं। यदि आंखों में खुजली हो रही है या कोई समस्या है तो उन्हें हाथों से मलना नहीं चाहिए, अन्यथा संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कोई भी दवा या आई ड्राप चिकित्सक से परामर्श के बाद ही लें। पंखे या एसी की हवा के सीधे संपर्क से भी आंखों को बचाकर रखें। धूप में अधिक देर रहने या स्क्रीन देखने से आंखों की थकान, उससे लगातार पानी आने की परेशानी हो रही है, तो चिकित्सक से जल्दी परामर्श लें। ब्रेक लेने का नियम अपनाएं, यानी हर 20 मिनट पर 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज को देखें।

ताकि त्वचा रहे स्वस्थ व सुरक्षित

- अक्सर सनस्क्रीन लगाते समय कान, गर्दन और हाथों पर ध्यान नहीं दिया जाता। चेहरे की तरह ही इन पर भी धूप का प्रभाव होता है।
- सुबह 11 बजे से शाम चार बजे के बीच तेज धूप होती है। इस अवधि में बाहर निकलने से बचें या सुरक्षा उपायों के साथ निकलें।
- ऐसे माइश्चराइजर और सीरम चुनें, जिनमें हाइलूरोनिक एसिड, ग्लिसरीन और एलोवेरा जैसे नमी प्रदान करने वाले तत्व मौजूद हों। ये त्वचा में नमी बनाए रखते हैं, इससे त्वचा मुलायम रहती है।
- घर या दफ्तर में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करने से हवा में नमी बढ़ाने और त्वचा को अत्यधिक शुष्क होने से बचाने में मदद मिल सकती है।
- सीरम का प्रयोग करते हैं तो जेल वाले प्रोडक्ट चुनें। साथ ही ऐसे सीरम चुनें, जिनमें विटामिन सी जैसे एंटीआक्सीडेंट्स युक्त हों।
- त्वचा तैलीय है या मुंहासों से परेशान हैं, तो रोमछिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए जेल वाले सनस्क्रीन का प्रयोग बेहतर विकल्प है।

सनस्क्रीन के प्रयोग से त्वचा रहेगी सुरक्षित

डा. दीपाली भारद्वाज
डर्मेटोलाजिस्ट, मैक्स अस्पताल, नई दिल्ली

त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह धूल, मिट्टी, हानिकारक बैक्टीरिया आदि से बचाता है। त्वचा पर होने वाले पसीने के जरिये शरीर का तापमान संतुलित रहता है, पर पसीना लंबे समय तक बना रहे, तो त्वचा संबंधी परेशानी भी हो सकती है। धूप आवश्यक है, क्योंकि इसकी मदद से त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है, लेकिन इन दिनों तेज धूप व गर्मी इसके लिए चुनौती बन जाती है। त्वचा की स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। बुजुर्ग और बच्चे साफ-सफाई में लापरवाही बरतते हैं, इसलिए उनमें संक्रमण व त्वचा संबंधी परेशानी अधिक देखी जाती है। चूंकि उनकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होती है इसलिए सफाई का अधिक ध्यान जरूरी है। साथ ही, रोजाना सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। यह केवल धूप से बचाव के लिए ही नहीं है। इसे घर के भीतर भी लगाएं। यह स्क्रीन से निकलने वाले हानिकारक किरणों से भी सुरक्षा देते हैं। लोग अच्छे ब्रांड का सनस्क्रीन लगाकर मान लेते हैं कि सुरक्षित हैं, पर हर तीन घंटे में सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इसी तरह संक्रमण से बचाव के लिए रोज एक आंवला लेना बेहतर होता है।

आंखों को मिले ठंडक, बनी रहे इसकी सेहत

- यदि आंखों में जलन महसूस हो रही है, थकान महसूस होती है तो ठंडे पानी में कपड़ा भिगो लें और उसे निचोड़कर कुछ देर आंखों पर रखें।
- आरओ वाटर से आंखों को धोएं। सामान्य पानी में संक्रमण होने का खतरा रहता है।
- ठंडे आई मास्क या खीरे के टुकड़े का प्रयोग भी अच्छा है।
- आई मेकअप का प्रयोग करने के बाद उसे अच्छी तरह साफ कर लें। अन्यथा इनसे भी आंखों में जलन या खुजली हो सकती है और आंखों में संक्रमण भी हो सकता है।
- रात को अच्छी नींद भी आंखों की सेहत के लिए आवश्यक है।
- एसी के सीधे और लंबे समय तक संपर्क में रहने से आंखों में मौजूद आंसू की परत सूख सकती है। इससे आंखों में अत्यधिक सूखापन, जलन और खुजली जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
- आहार में एंटीआक्सीडेंट्स से भरपूर फल (खट्टे फल और बेरीज), पत्तेदार सब्जियां और कैरोटीन से भरपूर सब्जियां शामिल करना चाहिए। इससे गर्मियों में होने वाली आंखों की जलन व सूखापन कम करने में मदद मिलती है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनाएं।

खानपान में रहे विशेष ध्यान

- विटामिन-सी से त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद मिलती है। भोजन में बेरी, शिमला मिर्च व ब्रोकली आदि को शामिल करें।
- ओमेगा-3 त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और सूजन को कम करने में मदद करता हैं। यह वसायुक्त मछली (सैल्मन, मैकेरल), चिया सीड्स और अखरोट जैसे खाद्य पदार्थ में खूब होते हैं।
- एंटीआक्सीडेंट्स से भरपूर खाद्य पदार्थ लें। ये धूप के संपर्क में आने से होने वाले फ्री रेडिकल नुकसान से लड़ने में मदद करते हैं। ये ब्लूबेरी, पालक और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों में आपको मिल सकता है।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

जीवनशैली

क्यों चकराता है सिर जानें इसका सही निदान

डा. प्रवीण गुप्ता
चेयरमैन, मैरिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूरो एंड स्पाइन, गुरुग्राम

क्या अचानक चक्कर महसूस होता है और आप इसे कमजोरी, थकान या कोई अन्य सामान्य बात मानकर टाल देते हैं। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो यह वर्टिगो के लक्षण भी हो सकते हैं, इसके लिए सतर्कता बढ़ाने और डाक्टर से परामर्श की जरूरत पड़ती है। आइए जानें...

कई लोग अचानक महसूस करते हैं कि उनके आसपास की चीजें घूम रही हैं या उनका संतुलन बिगड़ रहा है। अक्सर इसे सामान्य चक्कर समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन कई बार यह वर्टिगो हो सकता है। दरअसल, वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर के संतुलन तंत्र में समस्याओं का संकेत है। यह समस्या दैनिक जीवन, कामकाज और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। वर्टिगो में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे कमरा घूम रहा हो या वह खुद घूम रहा हो। यह स्थिति कुछ सेकंड से लेकर घंटों तक रह सकती है और इसमें मतली, उल्टी, कान में आवाज, सिरदर्द या फिर चलने में असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

वर्टिगो के प्रमुख कारण

वर्टिगो के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण इनर ईयर में संतुलन बनाने वाली प्रणाली में गड़बड़ी है। इसे बेनाइन पैराक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो (बीपीपीवी) कहते हैं। इसमें सिर की पोजिशन बदलते ही चक्कर आने लगते हैं।

कुछ अन्य कारण

- कान में संक्रमण
- मेनियर डिजीज
- माइग्रेन
- गर्दन की समस्या
- सिर में चोट
- स्ट्रोक या न्यूरोलाजिकल समस्याएं
- अत्यधिक तनाव और नींद की कमी
- ब्लडप्रेशर या शुगर में अचानक बदलाव

कई लोग लंबे समय तक स्क्रीन देखने, अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण चक्कर की समस्या का अनुभव करते हैं। इसलिए हर चक्कर को सामान्य कमजोरी मान लेना सही नहीं है।

जीवनशैली की है बड़ी भूमिका

वर्टिगो को नियंत्रित करने में जीवनशैली महत्वपूर्ण है। अनियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद न लेना, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी समस्या को बढ़ा सकते हैं। मरीजों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना, अचानक सिर या गर्दन की मूवमेंट से बचना और शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है।

जीवनशैली में करें सुधार

- प्रतिदिन सात से आठ घंटे की नींद आवश्यक है।
- अचानक खड़े होने या झटके से सिर घुमाने से बचें।
- लंबे समय तक मोबाइल या लैपटाप देखने के बीच ब्रेक लेते रहना जरूरी है।
- तनाव कम करने के लिए योग और व्यायाम जैसे उपाय प्रभावी हैं।
- नियमित हल्की एक्सरसाइज करना भी पर्याप्त होता है।
- अल्कोहल और धूमपान से दूरी बनाना जरूरी है। ऐसे छोटे-छोटे सुधार उपयोगी साबित होंगे।

खानपान में करें बदलाव

कई लोगों को पता नहीं होता कि डाइट भी वर्टिगो को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से जिन लोगों को मेनियर डिजीज या फ्लूइड बैलेंस की समस्या होती है, उनके लिए खानपान महत्वपूर्ण हो जाता है। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन चक्कर बढ़ा सकता है।

- पर्याप्त पानी पिएं, नमक सीमित मात्रा में लें।
- अधिक कैफीन व एनर्जी ड्रिंक्स लेने से बचें।
- संतुलित, हल्का भोजन करने का प्रयास करें।
- भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां लें।
- लंबे समय तक खाली पेट न रहें।

यदि शुगर लेवल गिरता है, तो भी चक्कर जैसी स्थिति महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित समय पर भोजन करना जरूरी है।

वर्टिगो को कैसे करें मैनेज

वर्टिगो का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। डाक्टर मरीज की हिस्ट्री, लक्षण और जरूरत पड़ने पर जांच के आधार पर उपचार तय करते हैं। कुछ मामलों में दवाएं मदद करती हैं। जबकि बीपीपीवी जैसी स्थिति में विशेष सिर और गर्दन की एक्सरसाइज, जिन्हें वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज कहते हैं, काफी प्रभावी हो सकती हैं। अगर चक्कर बार-बार आ रहे हैं, चलने में असंतुलन हो, बोलने में दिक्कत हो या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत डाक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह कुछ मामलों में गंभीर न्यूरोलाजिकल समस्या का संकेत हो सकता है।

कैसे करें बचाव

वर्टिगो से पूरी तरह बचाव हर हाल में संभव नहीं है, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है।

- नियमित हेल्थ चेकअप कराएं।
- ब्लडप्रेशर और शुगर नियंत्रित रखें।
- पर्याप्त नींद और हाइड्रेशन बनाए रखें।
- तनाव को नियंत्रित करें।
- सिर की चोट से बचें।
- बिना डाक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें।

वर्टिगो को नजरअंदाज करना सही नहीं है। समय पर पहचान, सही इलाज व संतुलित जीवनशैली से अधिकांश लोग सामान्य व सक्रिय जीवन जी सकते हैं।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

आज का भविष्यफल : 03 जून, 2026 बुधवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष तृतीया का राशिफल।
आज का राहुकाल : दोपहर 12 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : उत्तर
आज की भद्रा : प्रातः 08 बजकर 13 मिनट से रात्रि के 09 बजकर 22 मिनट तक।

कल 04 जून, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल : दक्षिण
विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 23 घंटे 31 मिनट तक, तत्पश्चात पंचमी उत्तराआषाढ़ा नक्षत्र 27 घंटे 42 मिनट तक तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र शुक्ल योग 09 घंटे 03 मिनट तक, तत्पश्चात ब्रह्म योग धनु में चंद्रमा 07 घंटे 42 मिनट तक तत्पश्चात मकर में।

मेष : महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी।
वृष : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
मिथुन : आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन या यात्रा की संभावना है।
कर्क : जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता/अधिकारी से सहयोग मिलेगा।
सिंह : आर्थिक प्रगति होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
कन्या : शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास सार्थक होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।
तुला : आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। मन भय से ग्रसित रहेगा। नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें।
वृश्चिक : पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
धनु : धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। रिश्तों में निकटता आएगी।
मकर : धन, सम्मान में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। संबंधों में निकटता आएगी।
कुंभ : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
मीन : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका में प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी।

वर्ग पहेली-3354

© Bird Features & Writing Agency

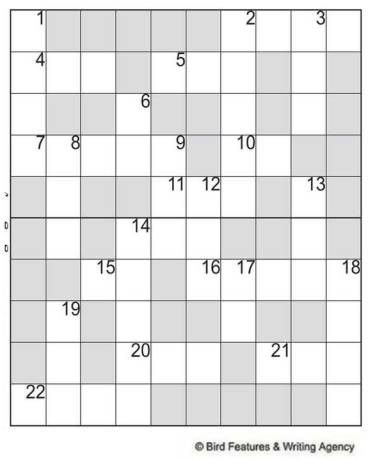

बाएं से दाएं :
2. खटका होना, चुभना (4)।
4. सूख कर अकड़ना (3)।
5. सौ अरब (3)।
7. काम निकल जाने पर उपेक्षा करना (2,3)।
10. धब्बा (2)।
11. बहुत लोगों का भोजन एक साथ पकाने का स्थान (3)।
14. दुखी, खिन्न (3)।
15. हमेशा, सर्वदा (2)।
16. सम्मानित व्यक्ति को अपशब्द कहना (5)।
20. इस रोग में रात में कुछ दिखाई नहीं देता (3)।
21. स्वाभाविक ढंग, तमीज, शिष्टता (3)।
22. मरने तक (4)।

ऊपर से नीचे :
1. मिट्टी के रंग का (4)।
2. होशियार (5)।
3. कली (3)।
6. तट, शर, बाण (2)।
8. बर्रे, भीड़ (3)।
9. एक प्राचीन विश्वविद्यालय (3)।
12. जकड़ कर बांधना (3)।
13. बधिर (3)।
14. दृष्टांत (5)।
17. महीना (2)।
18. धमकी देना, डराना (4)।
19. अटकाव, विश्राम (3)।

कल का हल

1 नि		2 क	3 ह	र		4 ज	ला	व	न
क्षे			ड़			मा			
प		5 अ	प	6 ना	ब	ना	7 ना		8 प
9 क	ला	प		र			10 सू	र	त
		मा				11 डों	र		ला
12 गुं		13 न	क्शा				डा		
14 ठ	न	का			15 बु		16 ल	ह	17 क
ली		18 री	19 ति	ब	द्ध	20 हीं	ना		रा
			मि			म			ह
21 जं	मा	खो	र		22 क्ष	र	ण		ना

सुडोकू-3354

		9		3		6		2
	2						1	
7		5			1		4	
3			7			9		4
	1	7			2		3	
9				8				7
2			5					1
		4				5		
5			9		8		7	

कल का हल

7	9	1	5	2	4	8	3	6
3	6	4	1	8	7	5	9	2
5	8	2	6	3	9	4	1	7
9	3	6	2	4	1	7	8	5
8	4	5	9	7	6	3	2	1
2	1	7	8	5	3	9	6	4
1	5	3	4	9	2	6	7	8
6	7	8	3	1	5	2	4	9
4	2	9	7	6	8	1	5	3

राष्ट्रीय फलक

चारधाम में क्षमता के अनुरूप दर्शन व्यवस्था के लिए बनेगी एसओपी

▸ रात्रि 10 से सुबह चार बजे तक यात्रा मार्गों में वाहनों की आवाजाही पर रोक का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून

चारधाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ के दृष्टिगत दर्शन व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर सरकार कदम उठा रही है। चारों धामों में क्षमता के अनुरूप दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने को विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में हुई चारधाम यात्रा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्गों पर रात्रि 10 से सुबह चार बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही कहा कि यात्रा मार्गों पर ट्रकों व आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को ही केवल रात्रिकाल में अनुमति दी जाए और दिन में ऐसे वाहनों का संचालन बंद रखा जाए। किसी भी धाम अथवा पड़ाव में निर्धारित क्षमता से अधिक भीड़ की स्थिति में ठहराव स्थलों और प्रमुख चेक प्वाइंट पर वाहनों व श्रद्धालुओं की आवाजाही नियंत्रित करने पर भी सीएम ने जोर दिया। कहा कि भीड़ प्रबंधन के लिए चरणबद्ध व्यवस्था अपनाते हुए यात्रियों को आगे भेजा जाए।

सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सूवि

केरलम में लिव-इन रिलेशन में 'रोड़ा' बने मासूम को दी दर्दनाक मौत, ममता हुई शर्मसार

▸ डेढ़ साल के मासूम को तड़पाकर मारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डाक्टरों एवं पुलिस के भी होश उड़े

▸ इस नन्हे से नौनिहाल के शरीर पर कई जगह सिगरेट या किसी गर्म चीज से दागे जाने के गोल निशान भी थे

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरलम से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक डेढ़ साल के मासूम बच्चे, अर्शिद, की मौत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो डाक्टरों से लेकर पुलिस तक के होश उड़ गए। इस नन्हे से बच्चे के शरीर पर एक-दो नहीं, बल्कि 51 गहरे जख्म पाए गए। शरीर पर कई जगह सिगरेट या किसी गर्म चीज से दागे जाने के गोल निशान भी थे। रिपोर्ट से साफ हुआ है कि मासूम को मौत के घाट उतारने से पहले हफ्तों तक रूह कंपा देने वाली यातनाएं दी गईं। पुलिस ने इस मामले में बच्चे की मां अखिला और उसके लिव-इन पार्टनर अश्कर को गिरफ्तार कर लिया है।

लिव-इन पार्टनर के जुल्म और मां की खामोशी : पुलिस जांच में जो सच सामने आया है, वह किसी का भी कलेजा चीरने के लिए काफी है। दरअसल, अर्शिद अखिला की पहली शादी से था। पुलिस का मानना है कि अश्कर और अखिला के साथ रहने की राह में यह मासूम एक 'रोड़ा' बन गया था। इसी वजह से अश्कर उसे लगातार बेरहमी से पीटता था।

हैरानी और दुख की बात यह है कि एक मां आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को तड़पता देखती रही, लेकिन उसने न तो अश्कर को रोका और न ही पुलिस को खबर की। मासूम के दोनों हाथ टूटे हुए थे। कुछ हफ्ते पहले जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो झूठी कहानी गढ़ी गई कि बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था।

शरीर पर मिले जलने के निशान, फूटा जनता का गुस्सा : मासूम अर्शिद की मौत के बाद अश्कर ने इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की और कहा कि खाना खाने के बाद उल्टी होने से बच्चा बेहोश हो गया। लेकिन, बच्चे के ननिहाल वालों ने जब उसके शरीर पर सिगरेट या किसी गर्म चीज से दागे जाने के गोल निशान देखे, तो उन्हें शक हुआ। पोस्टमार्टम में सिर की घातक चोट और आंतरिक रक्तस्राव (इंटरनल ब्लीडिंग) को मौत की वजह बताया गया है।

इस खबर फैलते ही इलाके में भारी जन-आक्रोश फैल गया। जब पुलिस आरोपित अश्कर को सीन रीक्रिएशन के लिए ले गई, तो गुस्साई भीड़ ने उस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस अब अश्कर के पुराने आपराधिक इतिहास और उसकी पहली पत्नी पर हुए जुल्मों की भी जांच कर रही है। कानूनन दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

किश्तवाड़ और डोडा में तीन जगह फटे बादल, कई जगह भूस्खलन

▸ डोडा-किश्तवाड़ राजमार्ग पर भी आया मलबा, घंटों बाधित रहा रास्ता

▸ बादल फटने से जनहानि की सूचना नहीं, राहत कार्य में जुटा प्रशासन

जागरण टीम, किश्तवाड़

किश्तवाड़ और डोडा जिलों में मंगलवार को तीन स्थानों पर बादल फटने से मूसलधार वर्षा से मिट्टी व भारी मलबा पहाड़ों से नीचे रिहायशी क्षेत्रों में आ गया। कई जगह भूस्खलन भी हुआ। इससे स्थानीय लोगों के कई वाहनों व संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। कई संपर्क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल, जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन और अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। बचाव दल मौके पर पहुंच लोगों के साथ राहत कार्य में जुटे हैं।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बादल फटने से उपजे हालात से निपटने के लिए जारी कार्यों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। किश्तवाड़ जिला के सरथल और माछीपाल क्षेत्र में शाम को बादल फटे। इससे डोडा-किश्तवाड़ राजमार्ग पर भी मलबा आ गया।

मौसम ने ली दो की जान

- अनंतनाग में तेज हवाओं के बीच पेड़ गिरने से पति की मौत व पत्नी घायल।
- डोडा जिला में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत।
- पुंछ जिला में चकराडा झूला पुल तेज हवाओं की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे संपर्क मार्ग कट गया है।
- कश्मीर के बांडीपोरा जिला में किश्नगंगा में कुछ वाहन तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें सेना ने सुरक्षित निकाल लिया
- राजौरी और पुंछ जिलों के अलावा रियासी में वर्षा हुई। कटड़ा में माता वैष्णो देवी के लिए हेलीकाप्टर सेवा बीच-बीच में बाधित रही।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

बुधवार, 03 जून, 2026

14

www.jagran.com

माउंटबेटन ने की भारत-पाकिस्तान विभाजन योजना की घोषणा

1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की। जिससे हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत व मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल किया गया। सीमा निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया।

अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अमेरिकी एडवर्ड व्हाइट

1965 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मेजर एडवर्ड व्हाइट द्वितीय ने अंतरिक्ष में पहली बार स्पेसवाक कर इतिहास रचा था। उन्होंने पृथ्वी से 193 किलोमीटर ऊपर यान के बाहर 20 मिनट तक रहकर अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से चहलकदमी की थी।

बाल विवाह निषेध कानून के सूत्रधार थे हरविलास शारदा

1867 में आज ही के दिन समाज सुधारक हरविलास शारदा का जन्म ब्रिटिश भारत के अजमेर प्रांत (वर्तमान राजस्थान) में हुआ था। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1924 तक रजिस्ट्रार और उप-मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहते हुए उन्होंने 1927 में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे बाद में समिति के पास भेजा गया। यह विधेयक 1929 में पारित हुआ और एक अप्रैल 1930 से कानून के रूप में लागू हुआ। इसी कारण इसे 'शारदा अधिनियम' के नाम से भी जाना जाता है। 20 जनवरी 1955 को उनका निधन हुआ।

हर्बल सिगरेट से निकलने वाला धुआं ज्यादा हानिकारक

अध्ययन ▶ शोधकर्ताओं ने भारत के दो सबसे अधिक बिकने वाले तंबाकू ब्रांडों और चार हर्बल सिगरेट के उत्सर्जन की तुलना की

हर्बल सिगरेट से निकलने वाले उत्सर्जन लगभग हर मापदंड पर तंबाकू सिगरेट के समान या उससे अधिक थे

नई दिल्ली, प्रेट्र : हर्बल सिगरेट को भारत और विदेश में प्राकृतिक, तंबाकू मुक्त और चिकित्सीय विकल्प के रूप में बेचा जाता है। लेकिन एक नए अध्ययन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसके तहत नियमित तंबाकू सिगरेट की तुलना में हर्बल सिगरेट सुरक्षित नहीं हैं। यह ऐसा उत्सर्जन पैदा करती हैं जो तंबाकू के धुएं के समान या उससे भी अधिक हानिकारक हो सकता है। इस बारे में जर्नल आफ हैजर्डस मैटेरियल्स में निष्कर्ष प्रकाशित किया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि भारतीय बाजार में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हर्बल और तंबाकू सिगरेट से निकलने वाले मुख्यधारा (पहले हाथ) धुएं के भौतिक, रासायनिक और आक्सीडेटिव गुणों की व्यापक तुलना प्रस्तुत की गई है। आइ आइआइटी गांधीनगर के सिविल इंजीनियरिंग व केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर समीर पटेल ने कहा, हमारे निष्कर्ष उस व्यापक धारणा को चुनौती देते हैं कि तंबाकू मुक्त का मतलब जोखिम मुक्त है। शोधकर्ताओं ने भारत के दो सबसे अधिक बिकने वाले तंबाकू ब्रांडों और तुलसी, लौंग, दालचीनी, पुदीना, हरी चाय, जल कुमुद व कैमोमाइल के संयोजनों वाली चार लोकप्रिय हर्बल किस्मों के उत्सर्जन की तुलना की।

पते में लिपटी हर्बल किस्में ज्यादा हानिकारक : पटेल ने कहा, हर्बल सिगरेट से निकलने वाला धुआं हर मापदंड पर तंबाकू सिगरेट के समान या

प्रतीकात्मक

उससे अधिक थे। पत्ते में हर्बल किस्में सभी परीक्षण किए गए नमूनों में सबसे हानिकारक साबित हुईं। टीम ने नोट किया कि दो हर्बल ब्रांडों ने तेंदू पत्तियों का उपयोग किया, जो बीडी में उपयोग की जाने वाली पत्तियों के समान हैं, जो देश में सबसे अधिक उपभोग की जाने वाला धूमपान है। निष्कर्ष बताते हैं कि एचसी (हर्बल सिगरेट) के उत्सर्जन के गुण टीसी (तंबाकू सिगरेट) के समान या उससे अधिक हैं। यह सुझाव देते हुए कि एचसी उतनी ही हानिकारक हैं, जितनी कि टीसी।

हर्बल सिगरेट की सांद्रता 20 प्रतिशत अधिक : कहा कि एचसी में 500 एनएम (नैनोमीटर) से कम आकार वाले कणों की सांद्रता टीसी की तुलना में (लगभग) 20 प्रतिशत अधिक थी। ये महीन कण हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों से तेजी से जुड़ते जा रहे हैं। हर सिगरेट को एक बंद, स्वचालित दो चैंबर वाले रिग के अंदर जलाया गया था, जिसे इंसानों की सांस लेने की दर की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। उत्सर्जन की संभावित विषाक्तता के संकेतक के रूप में एकत्र किए गए नमूनों की आक्सीडेटिव क्षमता (जो धुएं की प्रतिक्रियाशील आक्सीजन प्रजातियों को पैदा करने की क्षमता को मापती है) का निर्धारण किया गया। हर्बल सिगरेट से निकलने वाले कणों में तंबाकू सिगरेट से निकलने वाले कणों की तुलना में काफी अधिक आक्सीडेटिव क्षमता पाई गई।

सबसे अधिक सीसा सांद्रता पाई गई : विशेष रूप से तेंदू पत्ते में लिपटी किस्मों ने कागज में लिपटी किस्मों की तुलना में 49 प्रतिशत अधिक आक्सीडेटिव क्षमता दिखाया। एक रासायनिक विश्लेषण ने जानकारी दी कि एक हर्बल सिगरेट जो तुलसी से भरी थी में सबसे अधिक सीसा सांद्रता थी, हालांकि इसे 100 प्रतिशत प्राकृतिक भराव के साथ रासायनिक मुक्त स्वस्थ जीवनशैली के रूप में विपणन किया गया था। अमेरिका के इलिनोइस विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर विशाल वर्मा ने कहा, यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि कई उपभोक्ता निकोटीन-मुक्त उत्पादों को कम हानिकारक मानते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि हर्बल सिगरेट के आसपास एक नियामक अंतराल की समस्या है।

मणिपुरी फिल्म बोंग ने न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जीते तीन पुरस्कार

न्यूयार्क, प्रेट्र: बाफ्टा पुरस्कार विजेता मणिपुरी फिल्म 'बोंग' ने न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में तीन पुरस्कार जीते। फिल्म के युवा नायक गुगुन किपगेन को उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि फिल्म निर्माता लक्ष्मीप्रिया देवी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म की सफलता में एक और उपलब्धि यह रही कि महोत्सव के समीक्षकों की समिति ने बोंग को सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म का खिताब भी दिया।

न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 का चार दिवसीय समापन रविवार को एक पुरस्कार समारोह के साथ हुआ, जिसमें दस श्रेणियों में भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया गया। 28 से 31 मई तक आयोजित इस महोत्सव में 15 भाषाओं में बनी विविध फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इंडो-अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित चार दिवसीय महोत्सव रविवार को भारतीय स्वतंत्र फिल्मों के विविध संग्रह को प्रस्तुत करने के बाद समाप्त हो गया।

मणिपुरी फिल्म बोंग। फाइल

इस वर्ष के कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से 19 फीचर फिल्में, चार वृत्तचित्र और 27 लघु फिल्में शामिल थीं। महोत्सव के आयोजकों ने बताया कि 15 भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत प्रविष्टियां क्षेत्रीय सिनेमा की बढ़ती वैश्विक अपील को दर्शाती हैं।

इधर-उधर

ठोड़ी पर चलती चेनसा रख बनाया विश्व रिकार्ड

चार मिनट तक सिर पर मंडराता रहा खतरा ● इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका के डेविड रश ने ठोड़ी पर चलती हुई चेनसा (लकड़ी काटने वाली मोटर चालित आरी) को लगातार 4 मिनट 0.99 सेकंड तक संतुलित रखकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया। यह कारनामा उन्होंने इडाहो में बेटे की फुटबाल टीम के अंतिम अभ्यास सत्र के दौरान किया। रिकार्ड के नियमों के अनुसार, चेनसा को पहले लकड़ी काटनी होती है और पूरे प्रयास के दौरान उसका ब्लेड चलता रहना चाहिए।

2050 तक कैंसर से निपटने में नर्सों व विशेषज्ञों की होगी बड़ी कमी

- 2050 तक कैंसर की देखभाल के क्षेत्र में दुनिया भर में 10 करोड़ कर्मचारियों की कमी होने का अनुमान
- 2050 तक कैंसर के मामलों में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुनिया में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। द लैंसेट आंकोलाजी आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक कैंसर की देखभाल के क्षेत्र में दुनिया भर में 10 करोड़ कर्मचारियों की कमी होने का अनुमान है। वहीं, 2050 तक कैंसर के मामलों में 21% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिसका सबसे ज्यादा असर कम और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ेगा। शोध लेखकों ने लिखा, सबसे ज्यादा कमी नर्सों (6.5 करोड़) और डायग्नोस्टिक (रेडियोलाजी और पैथोलाजी) विशेषज्ञों (1.6 करोड़) की होगी, खासकर अफ्रीका और एशिया में।"

दक्षिण एशिया के 55 देशों समेत एक व्यापक वैश्विक कैंसर के कार्यबल के विस्तार से कैंसर मृत्यु दर को 50 प्रतिशत से अधिक कम कर सकता है। सर्जनों की संख्या बढ़ाने से दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा 3.64 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है, खासकर अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया में; वहीं, डायग्नोस्टिक व इमेजिंग कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से 7.61 प्रतिशत की सबसे बड़ी कमी आ सकती है।

अमेरिका के हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ, आस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी और ब्राजील के साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के लेखकों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ने कहा, सभी स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी से 55 देशों में कैंसर से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आने का अनुमान है, खासकर अफ्रीका, मध्य अमेरिका और दक्षिण एशिया में।

नर्सों और डायग्नोस्टिक विशेषज्ञों की कमी का अनुमान : 2050 में कई अध्ययनों से प्राप्त जीवित रहने के आंकड़ों का विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे कम दरें अफ्रीका (34.4 प्रतिशत) और एशिया (38.7 प्रतिशत) में होंगी, जबकि सबसे ज्यादा दरें उत्तरी अमेरिका (63.9 प्रतिशत) और ओशिनिया (70 प्रतिशत से ज्यादा) में होंगी।

प्रतीकात्मक

रिपोर्ट में कहा गया है, कैंसर की देखभाल करने और रिसर्च करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, ज्यादा आय वाले देशों और कम व मध्यम आय वाले देशों के बीच कैंसर से बचने की दरों में मौजूद असमानताओं को कम करने में बड़ी बाधा बनी है।"

17 करोड़ टाली जा सकती हैं मौतें : शोधकर्ताओं ने कहा कि भविष्य में कैंसर के मामलों में होने वाली बढ़ोतरी से निपटने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी और कार्यबल विकास में निवेश करने का काम अभी से शुरू करना होगा। ओलिविया न्यूटन जान कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और लेखक एंड्रयू स्काट ने कहा, "कैंसर के मरीजों की इमेजिंग के लिए कार्यबल में मौजूद कमियों की पहचान करना जरूरी है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि सभी देशों में मरीजों को सही जांच और इलाज मिल सके।"

इसमें कार्यबल की बेहतर योजना बनाने, ट्रेनिंग में खास तौर पर निवेश करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जांच और इलाज की सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना शामिल है। रिपोर्ट में पाया गया है कि कैंसर के इलाज से जुड़े कार्यबल को बढ़ाने से 17 करोड़ तक मौतें टाली जा सकती हैं और मृत्यु दर में लगभग 40 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है। साथ ही, 2030 से 2050 के बीच 120 ट्रिलियन अमेरिकी डालर का आर्थिक फायदा भी होगा। इसका मतलब है कि निवेश किए गए हर एक अमेरिकी डालर पर चार अमेरिकी डालर का वैश्विक रिटर्न तब्दील होता है।

अध्ययन में आटिज्म के दो उपप्रकारों की हुई पहचान

अनुसंधान

आटिज्म न्यूरोडेवलपमेंट विकार है, जिसमें व्यक्ति दोहरावदार व्यवहार करता है और उसके सामाजिक कौशल में कमी दिखाती है। एक अध्ययन में आटिज्म के दो उपप्रकारों की पहचान की गई है, जिनमें से एक मस्तिष्क की बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से संबंधित है जो इम्यून-संबंधित प्रणालियों से जुड़ा है, जबकि दूसरा न्यूरान्स के बीच संकेत भेजने में मदद करने वाले साइनैप्टिक पथों से जुड़ी कम कनेक्टिविटी से संबंधित है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि ये निष्कर्ष व्यक्तिगत और सटीक आटिज्म देखभाल के लिए उपकरण विकसित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आटिज्म मस्तिष्क के क्षेत्रों के बीच असामान्य हाइपरकनेक्टिविटी या अधिक संचार और हाइपोकनेक्टिविटी या कम संचार के पैटर्न से चिह्नित होता है। इस अध्ययन की अगुआई इटालियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी व अमेरिका के चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने की। अध्ययन में 20 चूहों के माडल और 940 बच्चों और युवाओं के मस्तिष्क स्कैन किया गया, जिनमें आटिज्म था। विश्लेषण में दो पुनरुत्पादित आटिज्म उपप्रकारों का पता चला - एक जो मस्तिष्क की कनेक्टिविटी में कमी, या हाइपोकनेक्टिविटी से चिह्नित है व साइनैप्टिक पथों से जुड़ा है व दूसरा इम्यून-संबंधित प्रणालियों से जुड़ी कनेक्टिविटी या हाइपरकनेक्टिविटी से चिह्नित है। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

रिया चक्रवर्ती बोलीं, अब अभिनय मेरा मुख्य पेशा नहीं

आगामी दिनों में वेब सीरीज फैमिली बिजनेस में नजर आएंगी रिया। फाइल

साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने बाद उनकी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगाए गए। इन आरोपों के अलावा पुलिस, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), और एनसीबी (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। इसके साथ ही उन्हें 28 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। रिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने जेल के अनुभवों के साथ यह भी साझा किया अब अभिनय उनका मुख्य पेशा नहीं रहा। जेल के अनुभवों पर उन्होंने कहा, 'जेल में रहना ही सबसे मुश्किल है। यह सुनना मुश्किल है कि अब आप समाज का हिस्सा नहीं है, आप कोई व्यक्ति नहीं, बस एक अंक (कैदी नंबर) हैं। यह भी स्वीकार करना मुश्किल है कि आपको समाज में रहने के लिए योग्य नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आप बहुत बुरे हैं। इसलिए आपको समाज से दूर रखा गया है। ऐसी परिस्थितियां आपके स्वाभिमान को चूर कर देती हैं। परिवार से दूरी, स्वतंत्रता को लेकर अनिश्चितता रहती है।' आगे रिया ने कहा कि मैंने नेटफ्लिक्स के लिए एक शो किया है, जो इसी साल प्रदर्शित होगा। उसका नाम है फैमिली बिजनेस। मैंने करीब सात साल बाद अभिनय किया। उससे मेरी सारी भावनाएं जुड़ी था। हालांकि, अब यह मेरा मुख्य पेशा नहीं रहा। मैंने एक नया करियर शुरू किया उसके बाद मुझे यह प्रोजेक्ट मिला।

हैसियत बढ़ी, दुश्मन बढ़े: कंगना

एक बार फिर अभिनेत्री कंगना रनौत वास्तविक विषयों को फिल्म में समेटकर ला रही हैं। 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली उनकी अभिनीत फिल्म भारत भाग्य विधाता कामा अस्पताल की उन नर्सों पर बनी हैं, जिन्होंने साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों की जान बचाई थी। इस फिल्म को करने को लेकर कंगना कहती हैं कि राजनीति की वजह से मुझे फिल्मों से दूर होकर लोगों के बीच जाने का मौका मिला था, इस कारण मैं नर्स का यह रोल कर पाई। कई वार कलाकार अपनी प्रोटीन शेक और जिम की दुनिया में इतना खोया होता है कि उसे वास्तविकता दिखाई नहीं देती है। मैं मध्यमवर्गीय परिवार से रही हूं, लेकिन फिर भी मुझे इस रोल को करने के लिए तपस्या करनी पड़ी।

@kanganaranaut

जान ने दिया शीर्षक, प्रधानमंत्री की पहल ...

पहले फिल्म का नाम नर्सेस आफ कामा रखा था। इस शीर्षक को बदलने को लेकर कंगना ने बताया कि भारत भाग्य विधाता नाम प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) जी ने ही साल 2025 में हमारे श्रमिक वर्ग को दिया था। यह बात छुई थी, इसलिए हम चाहते थे कि यह शीर्षक हमें मिले। यह शीर्षक जान (अब्राहम) सर के पास था। टाइटल अगर किसी के पास हो, तो लोग अक्सर देते नहीं हैं। जान सर ने एक ही दिन में हमें यह टाइटल बिना कोई पैसे लिए दे दिया। अगर प्रधानमंत्री जी भी भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर फिल्म देखेंगे, तो सबके लिए अच्छा संदेश होगा।

रणवीर सिंह के मुद्दे पर बोलीं ...

इस मौके पर रणवीर सिंह पर सिने संस्था के कर्मियों द्वारा असहयोग करने के फरमान पर कंगना ने अपनी राय रखते हुए कहा कि मुझे तो हर किसी ने बैन किया है। जब आपकी हैसियत बढ़ती है, तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है कि उनके इतने दुश्मन है। अच्छी बात है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, तो कई तरह की रुकावटें आती हैं। मेरे साथ इतना हुआ हैं, देखिए आज मेरी गाड़ी अच्छी चल रही है। सब कुछ आखिरकार ठीक हो जाता है।

आतंकी हमले वाला वो दिन...

इस मौके पर कंगना से पूछा गया कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए उस आतंकी हमले के दौरान वह कहां थीं? इस पर उन्होंने कहा कि हम सब विशेष फिल्म्स में काम कर रहे थे और संघर्षरत स्ट्रगलर्स थे। शहाना गोस्वामी ने यारी रोड में घर लिया था, उन्होंने कहा की घर आ जाओ, पार्टी करते हैं। वहां भट्ट साहब (महेश भट्ट) आए और कहा टीवी आन करो आंतकी हमला हो गया है। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि हम घर जाएं या पार्टी करते रहें। अगर भट्ट साहब नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता।

फिल्म पसंद आई तो बनेगी...

फिल्म को बतौर फ्रेंचाइजी के रूप में आगे बढ़ाने के सवाल पर कंगना ने कहा कि मेरे लिए तो एक संपूर्ण अलग दुनिया खुली है। मैं भाग्यशाली हूं की मुझे कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कई लोग हैं, जो भारत की रीढ़ ही हड्डी हैं, खासकर महिलाएं तो देश की साइलेंट हीरोज होती हैं। फिर चाहे वह खेती कर रही हो या बुनकर कारिगरी का काम। महिलाएं बिना किसी प्रसिद्धि और पहचान की चाह के कई काम करती हैं। अगर यह फिल्म पसंद की गई, तो आगे चलकर बहुत सी कहानियां हैं, जो दर्शकों तक पहुंचाई जा सकती हैं।

इसलिए रोहित शेट्टी जैसी फिल्में बनाना चाहती हैं किरण राव

साल 2011 में प्रदर्शित फिल्म धोबी घाट से निर्देशन में कदम रखने के बाद किरण राव ने दूसरी फिल्म लापता लेडीज (2023) निर्देशित करने में करीब 12 साल का समय ले लिया। जिसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हालांकि, वो इस बीच बतौर प्रोड्यूसर कई फिल्मों से जुड़ी। हालांकि, किरण चाहती हैं कि वह फिल्मकार रोहित शेट्टी की तरह जल्दी जल्दी फिल्में बनाएं। फिल्मों के निर्देशन के बारे में अपनी सोच को लेकर किरण का कहना है, 'जाहिर सी बात हैं कि मैं आगे भी बस निर्देशन करते रहना चाहती हूं।

आगे पांच अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं किरण। फाइल

हर निर्देशक बस एक फिल्म से दूसरी फिल्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहता है। काश मैं भी रोहित शेट्टी जैसी होती। सच में जब वह एक फिल्म एडिट कर रहे होते हैं, तो अगली फिल्म निर्देशित कर रहे होते हैं और उसी समय अपनी तीसरी का प्रमोशन भी कर रहे होते हैं। अगर मुझमें बस इतना आत्मविश्वास होता कि मैं बिना परिणाम की चिंता किए यह कर सकूं तो मैं और भी बहुत सी फिल्में बनाती। किरण फिलहाल पांच अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जिनमें से एक हारर फिल्म है, दूसरी कामेडी ड्रामा है।

विवेक चौधरी को फिल्मों में भी काम आ रहा है विज्ञापन का अनुभव

राम माधवानी से लेकर शूजित सरकार, आर बाल्की और नितेश तिवारी समेत हिंदी सिनेमा में ऐसे कई फिल्मकार हैं, जिन्होंने फिल्में निर्देशित करने से पहले विज्ञापन फिल्में बनाई। फिल्म टोस्टर के निर्देशक विवेक दास चौधरी ने भी विज्ञापन फिल्में बनाने के बाद फिल्म टोस्टर से बतौर निर्देशक हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया। इन दिनों विवेक अपनी अगली फिल्म के लेखन पर काम कर रहे हैं। आज रील्स और शार्ट्स जैसे छोटे वीडियो के दौर में उन्हें लोगों का आकर्षण बनाए रखने में विज्ञापन फिल्मों के अनुभव काम आ रहे हैं। विवेक कहते हैं, 'मुझे हमेशा से यही (फिल्में बनाना) करना था, क्योंकि मेरे परिवार में भी कुछ लोग विज्ञापन फिल्मों में काम करते थे। मैं उनको देखता था, उनके सेट पर मेरा आना-जाना लगा रहता था। तो मुझे पहले विज्ञापन फिल्मों में काम करना ज्यादा सही लगा। वो अनुभव मुझे फिल्म निर्माण में भी काम आ रहा है, क्योंकि 20-30 सेकेंड में कोई कहानी बताना आसान नहीं होता है। यह एक कला होती है। विज्ञापन की दुनिया ने ही मुझे सिखाया है कि आप एक सीन को कैसे पकड़कर रख सकते हैं। किस तरीके से उसे एक भी सेकेंड के लिए ढीला नहीं छोड़ना है।'

अगली फिल्म के लेखन पर काम कर रहे हैं विवेक। फाइल

इसलिए फिल्म 'रामायणम्' से जुड़ गए यश

फिल्म रामायणम् में यश हैं रावण की भूमिका में। फाइल

कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जिनसे जुड़ना कलाकारों के लिए जरूरी हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ अभिनेता यश के साथ, जिन्होंने रामायणम् में न केवल रावण का रोल करने के लिए हां कहां, बल्कि बतौर सहनिर्माता भी जुड़े। इस फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा यश के फिल्म से जुड़ने को लेकर कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर भरोसा करके मेरे भव्य विजन को आकार दिया है। यश की खासियत केवल यह नहीं है कि वह एक कमाल के अभिनेता हैं, बल्कि जब इस प्रोजेक्ट की महत्वाकांक्षा और इसे बनाने को लेकर मेरे सपने के बारे में जाना, तो वह इससे जुड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि नमित, अगर हम यह करने जा रहे हैं, तो हमें इसे मिलकर करना होगा और इसे दुनिया के सामने सबसे बेहतरीन तरीके से पेश करना चाहिए। यह बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब उनके कद का कोई व्यक्ति सिर्फ अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्माता के तौर पर पूरी ताकत और समर्थन देता है, तो उससे फर्क पड़ता है। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह भारत की ओर से दुनिया के लिए कुछ ऐसा है, जो पहले कभी नहीं किया गया है। नमित ने कहा कि देखा जाए तो इसे तीन पार्ट में बनना चाहिए था, लेकिन इसे दो पार्ट में बनाया है, जो करना कठिन रहा।

बच्चों से माफी मांगना चाहते हैं शाहिद

फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि 40-45 वर्ष की उम्र से ज्यादा के कलाकार भी कालेज में पढ़ने वाले 17-18 वर्ष के किशोरों की भूमिकाएं निभाते हैं। 19 जून को प्रदर्शित हो रही फिल्म काकटेल 2 में अभिनेता शाहिद कपूर भी कुछ ऐसे दृश्यों में नजर आएंगे। हालांकि, शाहिद ऐसे दृश्यों में सहज नहीं रहते। ट्रेलर लांच के दौरान शाहिद ने कहा, कालेज वाले सीन करने में शर्म आती है। मैं बच्चों से माफी भी मांगना चाहता हूं। क्योंकि मुझे पता है, जब वे बड़े होंगे तो कहेंगे कि डैड, आप 45 साल की उम्र में यह कर रहे थे। आखिर क्यों? हालांकि, मुझे कहना चाहिए कि बतौर अभिनेता मुझे हर तरह की भूमिकाएं निभाना पसंद है।

@shahidkapoor

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

दूरी बनी सुष्मिता और ललित के ब्रेकअप का कारण

इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले चेयरमैन रहे ललित मोदी ने साल 2022 अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद खूब चर्चा में आ गए थे। इस पोस्ट में उन्होंने अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप के बारे में आधिकारिक घोषणा की थी। हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और कुछ सप्ताह के बाद ही दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें आने लगीं। अब ललित ने कहा, 'सुष्मिता मेरे लिए बहुत खास थीं। उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मैं आज जो कुछ भी हूं, वो बन पाया। वो बहुत खास थीं। वो उस समय मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा थीं और आज भी होतीं। हालांकि, बात बस इतनी थी कि हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। वह अब भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं।'

इंटरनेट मीडिया

JOIN OUR PAID SERVICE – 2026

Daily PDF Access | Editorial Bonus | Almost All Editions

ENGLISH NEWSPAPERS

The Hindu, Indian Express, Hindustan Times, Business Line, Business standard, The Live Mint, Times of India, Telegraph, New Indian Express, Asian Age, Statesman, Tribune, Pioneer, Financial Express, The Economic Times, Mid-Day, Deccan Chronicle, Employment News, Free Press Journal, Hans India, Deccan Herald, Lokmat Times, Mirror, Telangana Today

HINDI NEWSPAPERS

दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, राजस्थान पत्रिका, हरी भूमि, लोकसत्ता , पायनियर , दैनिक ट्रिब्यून , द हिन्दू, राष्ट्रीय सहारा , नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता, देशबंधू, प्रभात खबर, दैनिक नवज्योति, आईनेक्स्ट लाइव, लोकमत, नव भारत, नई दुनिया

Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

Full Package : All in One Plan

The Hindu Plan

(Starter) 1 Month = ~~199~~ ₹99

(★ Popular) 6 Month = ~~599~~ ₹349

(Best Value) 1 Year = ~~999~~ ₹549

Special Offer

You will Get

- 20+ Hindi Newspapers
- 22+ English Newspapers
- THE Hindu, BL,IE,TOI,ET, etc..
- Dainik Jagran, NBT, DB, Etc..
- Editorial Complation (En & Hi)
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

The Hindu, BL, IE, NIE Plan

The Hindu Plan

(Starter) 1 Month = ~~149~~ ₹69

(★ Popular) 6 Month = ~~499~~ ₹269

(Best Value) 1 Year = ~~799~~ ₹399

Special Offer

You will Get

- The Hindu (TH)
- Business Line (BL)
- Indian Express (IE)
- New Indian Express (NIE)
- Editorial Complation
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

LIMITED TIME OFFER

Telegram Access Available

→ CLICK HERE & JOIN NOW